



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22082020-221307  
CG-DL-E-22082020-221307

**असाधारण  
EXTRAORDINARY**

**भाग I—खण्ड 1**

**PART I—Section 1**

**प्राधिकार से प्रकाशित**

**PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं. 206]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 21, 2020/श्रावण 30, 1942

No. 206]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 21, 2020/SHRAVANA 30, 1942

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2020

मामला सं. (एसजी) 05/2019

**विषय – सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय की पहचान और आकलन) नियमावली, 1997 के तहत भारत में “सिंगल मोड आप्टिकल फाइबर” के आयातों के संबंध में रक्षोपाय जांच- प्रारंभिक जांच परिणाम के संबंध में।**

**फा.सं. 22/5/2019 – डी जी टी आर.— क. भूमिका**

- मैसर्स सेटलाइट टेक्नोलोजीज लिमिटेड ('एसटीएल') और मैसर्स बिडला फुर्लकावा फाइबर ऑप्टिक्स प्राइवेट लि. ('बीएफएल') (इसके बाद से इन्हें 'आवेदक' के रूप में भी कहा गया है) द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आकलन) नियमावली, 1997 (इसके बाद से इसे “कथित नियम” के रूप में भी कहा गया है) के नियम 5 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1997 (इसके बाद से इसे “कथित अधिनियम” के रूप में भी कहा गया है) की धारा 8 ख के तहत समान अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी उत्पादों के घरेलू उद्योग को बढ़ाते आयातों से हुई गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति होने की आशंका के लिए रक्षोपाय हेतु भारत में “सिंगल मोड आप्टिकल फाइबर” (इन्हें इसके बाद

“विचाराधीन उत्पाद” अथवा “पी यू सी” के रूप में भी कहा गया है) के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लगाने का अनुरोध करने के लिए महानिदेशक (रक्षोपाय) के समक्ष दिनांक 18.07.2019 को एक याचिका दाखिल की है। आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि संबद्ध वस्तुओं के आयातों में वर्ष 2018-19 में काफी वृद्धि हुई है और हाल ही की अवधि में अर्थात् जनवरी, 2019 से जून, 2019 तक वृद्धि का स्तर जारी रहा है। आवेदकों ने यह दावा किया है कि वे आयातों का मुकाबला करने और अपना बाजार अंश पुनः हासिल करने में सक्षम नहीं हैं जिससे उन्हें अपना उत्पादन बंद करने अथवा अपने उत्पादन का आंशिक भाग निष्क्रिय रखने के लिए मजबूर होना पड़ा है और अपनी क्षति को कम करने के लिए रक्षोपाय शुल्क लगाने का अनुरोध किया। प्राधिकारी ने दिनांक 06 नवंबर, 2019 को प्रारंभिक जांच परिणाम भी जारी किया जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया था।

#### **ख. अपनाई गई प्रक्रिया**

2. आवेदन और उसके साथ प्रस्तुत किए गए साक्ष्य/ विवरण/ दस्तावेज की जांच से यह निष्कर्ष निकलता है कि आवेदन में कथित नियमावली के नियम 5 की अपेक्षाओं को पूरा किया गया है। अतः भारत में विचाराधीन उत्पाद आयातों के विरुद्ध रक्षोपाय जांच जी सी आर सं. 293 (ई) के माध्यम से दिनांक 23.09.2019 की भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से शुरूआत की गई थी।

3. कथित नियमावली के नियम 6 के उप नियम (2) और (3) के अनुसार दिनांक 23.09.2019 जांच शुरूआत अधिसूचना की एक प्रति और घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल की गई याचिका के अगोपनीय अंश (एन सी वी) की एक प्रति केन्द्र सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय, प्रमुख निर्यातक देशों की सरकारों को उनके भारत में दूतावासों के माध्यम से और उक्त याचिका में उल्लिखित हितबद्ध पक्षकारों को प्रेषित की गई थी। इसके अलावा, उक्त नियमावली के नियम 6(4) के तहत यथानिर्धारित निर्यातकों/ आयातकों/ घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्तर दिए जाने वाली प्रश्नावली ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को प्रेषित की गई थी, जिसमें एन ओ आई जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर लिखित में अपने उत्तरों से अवगत कराने का अनुरोध किया गया था।

4. इसी बीच, अनंतिम रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए आवेदकों द्वारा किये गये अनुरोध की जांच की गई थी और प्रथम दृष्टया यह पाया गया था कि नाजुक परिस्थितियां मौजूद थीं जिसमें अनंतिम रक्षोपाय शुल्क लगाने में विलंब से घरेलू उद्योग को अपूरणीय क्षति होगी। अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा आज की तारीख तक प्रस्तुत किये गये अनुरोधों की भी जांच की गई थी।

5. तदनुसार, अनंतिम रक्षोपाय शुल्क के लिए प्रारंभिक जांच परिणाम 06 नवंबर, 2019 सीमा प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 9 (2) के अंतर्गत जारी किया गया था और उसे उसी दिन भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। हालांकि, सिफारिश की गई अनंतिम रक्षोपाय शुल्क को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया था।

6. तदंतर, कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध पर, प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने के लिए समयसीमा का विस्तार 15 नवंबर, 2019 तक किया गया था। ये अनुरोध और प्रश्नावली के उत्तर निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त हुए थे :

- I. कोर्निंग टेक्नोलॉजी इंडिया प्रा. लिमि.
- II. कोर्निंग फिनोलेक्स ऑप्टिकल फाइबर प्रा. लिमि.
- III. फिनोलेक्स केबल लिमि.
- IV. एच एफ सी एल लिमि. इंडिया
- V. वेस्टकोयस्ट ऑप्टिलिंक्स
- VI. फाइबरहोम इंडिया प्रा. लिमि.

- VII. सुमिटोमो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज लिमि. ('एस ई आई'), जापान
- VIII. एस डब्ल्यू सी सी शोवा केबल सिस्टम्स कं. लिमि., जापान
- IX. फूजीकूरा लिमि., जापान
- X. पीटी. जेड टी टी केबल, इंडोनेशिया
- XI. पीटी. सुप्रीम केबल मेनिफेक्चरिंग एंड कॉमर्स टीबीके, इंडोनेशिया
- XII. पीटी. वोकसेल इलेक्ट्रिक टीबीके., इंडोनेशिया
- XIII. पीटी. यांगटजे ऑप्टिकल फाइर, इंडोनेशिया
- XIV. पीटी. कॉम्यूनिकेशन केबल सिस्टम्स, इंडोनेशिया

7. उपर्युक्त के अलावा, पारामाउण्ड केबल लिमि., ओरियंट केबल इंडिया प्रा. लिमि. और ओम आप्टल इंडस्ट्रीज प्रा. लिमि. ने भी अपने अनुरोध विस्तारित समयसीमा अवधि के समाप्त होने के बाद प्रस्तुत किये थे। सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा या तो आम सुनवाई में अथवा अन्य प्रकार से किये गये अनुरोधों की जांच उपर्युक्त रूप से की गई है और उसका समाधान संगत पैराओं के अंतर्गत किया गया है। चूंकि, कई मुद्दों को दोहराया गया है अतः उनका सामूहिक रूप से समाधान किया गया है।

8. कोविड-19 महामारी के कारण लगाये गये व्यापार प्रतिबंधों और उसके पश्चात लॉकडाउन के देखते हुए आम सुनवाई दिनांक 12.05.2020 को डिजीटल वीडियो कॉफ्रैंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। इसी बीच महानिदेशक (रक्षोपाय) में परिवर्तन हुआ था और इस कारण से एक दूसरी आम सुनवाई वर्तमान महानिदेशक द्वारा दिनांक 17.07.2020 को डिजीटल वीडियो कॉफ्रैंसिंग के द्वारा की गई थी।

9. दोनों आम सुनवाईयों के दौरान, घरेलू उद्योग के साथ साथ हितबद्ध पक्षकारों को अपना मौखिक अनुरोध करने का समुचित अवसर दिया गया था। सीमा प्रश्तुक (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 6 के उपनियम (6) के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों जिन्होंने आम सुनवाई में भाग लिया था, से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किये गये विचारों को लिखित अनुरोध के रूप में प्रस्तुत करें।

10. घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दोनों आम सुनवाई के बाद प्रस्तुत किये गये लिखित अनुरोधों की प्रतियां सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई थी। हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिखित अनुरोधों के संबंध में प्रतिउत्तरों, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए अवसर भी दिया गया था।

11. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिनांक 12.05.2020 और 17.07.2020 को संपन्न आम सुनवाई के अनुसरण में उनके द्वारा व्यक्त किये गये लिखित अनुरोधों के रूप में उनके सभी विचारों की जांच की गई थी और उपर्युक्त निर्धारण करने के लिए इस पर विचार किया गया है। प्राप्त की गई अथवा ली गई सूचना का अगोपनीय पाठ सार्वजनिक फाइल में गोपनीय रखा गया है। उसके बाद घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दोनों सुनवाईयों के बाद प्रस्तुत किये गये लिखित अनुरोधों के प्रतिउत्तरों पर भी विचार किया गया था।

12. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों का डेस्क सत्यापन डिजीटल वीडियो कॉफ्रैंसिंग के माध्यम से किया गया था जिसमें घरेलू उद्योग ने सत्यापन के लिए संगत आंकड़ों को दर्शातु हुए अपने सिस्टम का स्क्रीन शेयर किया।

### जांच की शुरुआत के बाद अनुरोध

13. जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना लेकिन आम सुनवाई के पूर्व सूचना के उत्तर में प्राप्त अनुरोधों का सार नीचे दिये गये अनुसार है :

#### 13.1 फिनोलेक्स केबल्स लिमि.

फिनोलेक्स केबल्स लिमि. भारत में विचाराधीन उत्पाद के छ: उत्पादों में से एक है। उन्होंने भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर रक्षोपाय उपाय शुल्क लगाने के लिए घरेलू उद्योग की याचिका का समर्थन

किया है। उन्होंने जांच की अवधि के लिए अपने उत्पादों, बिक्री, क्षमता का उपयोग और मालसूची से संबंधित सूचना प्रस्तुत की है। तदनुसार, उन्होंने दावा किया है कि आयातों में अचानक उछाल हुआ है और इसके कारण घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति होने का खतरा उत्पन्न हो रहा है।

### **13.2 कोरनिंग टेक्नोलॉजीज इंडिया प्रा. लिमि. और कोरनिंग फिनोलेक्स आप्टिकल फाइबर प्रा. लिमि.**

- 13.2.1 टेक्नोलॉजीज इंडिया प्रा. लिमि. भारत में पी यू सी का एक उत्पादक है और कोरनिंग फिनोलेक्स आप्टिकल फाइबर प्रा. लिमि. कोरनिंग एस ए एस और फिनोलेक्स केबल्स लिमि. जो कोरनिंग टेक्नोलॉजीज इंडिया प्रा. लिमि. (इसके बाद 'कोरनिंग' के रूप में भी सामूहिक रूप से संदर्भित) द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री में लगा हुआ है, के बीच एक संयुक्त उद्यम है। कोरनिंग ने रक्षोपाय शुल्क की लेवी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका का समर्थन किया है।
- 13.2.2 उन्होंने यह अनुरोध किया है कि आयातों में हालिया, अचानक, बहुत अधिक और तीव्र वृद्धि के कारण घरेलू उत्पादों को गंभीर क्षति हुई है अथवा होने का खतरा उत्पन्न हो रहा है। यह भी अनुरोध किया गया था कि उन्होंने कम कीमत पर आयातों के कारण विशेष रूप जनवरी – जून 2019 में बहुत अधिक कीमत न्यूनीकरण और कीमत ह्रास का सामना किया है।
- 13.2.3 कोरनिंग जांच की अवधि के दौरान बिक्री की लागत में परिवर्तन के अनुपात में अपनी बिक्री कीमत बनाये रखने में सक्षम नहीं हुआ है।
- 13.2.4 उन्होंने घरेलू उद्योग द्वारा व्यक्त की गई इस चिंता को भी साझा किया था कि निर्यातकों द्वारा दिये गये बीजक के बाद बहुत अधिक क्षुट के कारण आयात आंकड़ों में दर्शायी गई कीमतों की तुलना में आयात किये गये वस्तुओं की वास्तविक कीमत बहुत अधिक हद तक कम है।
- 13.2.5 उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि निम्नलिखित "अप्रत्याशित घटनाक्रमों" के फलस्वरूप आयातों में अचानक वृद्धि हुई है :
- क. चीनी आप्टिकल फाइबर बाजार में मांग में गिरावट
  - ख. यू एस और जापान से आयात किये गये आप्टिकल फाइबर पर चीन जन. गण. द्वारा लगाया गान्नरोधी शुल्क
  - ग. वैश्विक अत्यधिक क्षमता
  - घ. आप्टिकल फाइबर प्रीफार्म में निवेश
  - ड. चीन से आप्टिकल फाइबर के आयातों पर यू एस द्वारा लगाया गया प्रशुल्क

### **13.3 एच एफ सी एल लिमि.**

वे भारत में पी यू सी के आयातकों में से एक हैं। उन्होंने मुख्य रूप से पी यू सी के क्षेत्र के अंतर्गत जी652 ग्रेड को छोड़कर अन्य ग्रेडों को शामिल किये जाने पर आपत्ति की है। उनके द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि भारत की मांग प्राथमिक रूप से नॉन डिस्प्रेशन शिफ्टीट फाइबर अर्थात् जी 652 ग्रेड का है। फाइबर केबल और अन्य उत्पाद जिसका निर्माण जी652 को छोड़कर अन्य ग्रेडों के लिए किया जा रहा है, प्रमुख रूप से भारत से बाहर निर्यात किया गया है और इसकी भारत में मांग और बाजार में कमी के कारण उपयोग नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार से, जी652 को छोड़कर अन्य ग्रेडों के आयातों से घरेलू उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है और इस कारण से इन सभी ग्रेडों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्रों से बाहर किया जाना चाहिए।

### **13.4 मैक्सिको की सरकार**

मैक्सिको से भारत में 01 जनवरी, 2016 से 30 जून, 2019 के दौरान विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं किया गया है। इस कारण से, विश्व व्यापार संगठन के रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 9.1 के संबंध में और इस तथ्य के कारण की मैक्सिको विश्व व्यापार संगठन का एक विकासशील सदस्य देश है, भारत को

मैक्सिको से पी यू सी के निर्यातों को वर्तमान जांच से लिये गये किसी रक्षोपाय शुल्क के थोत्राधिकार से बाहर किया जाना चाहिए।

#### 14. प्रारंभिक जांच परिणाम के बाद अनुरोध

निम्नलिखित अनुरोध प्रारंभिक जांच परिणामों को जारी किये जाने के बाद हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त हुए हैं :

##### 14.1 सुमिटोमो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज लिमि. जापान

14.1.1 ऐसी कोई नाजुक परिस्थितियां नहीं हैं जिसके कारण आरंभिक रक्षोपाय शुल्क लगाया जाना आवश्यक हो। उन्होंने अनुरोध किया है कि जबकि 2018-19 की तिमाही 2 में आयातों में अचानक वृद्धि हुई है, उसके बाद आयातों में बहुत अधिक हद तक गिरावट आई है।

14.1.2 घरेलू उद्योग के लाभ और हानि की गणना स्वतंत्र ग्राहक को बिक्री की कीमत के साथ घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत की गणना करते हुए की गई है। संबंधित / कैप्टिव पक्षकारों को बिक्री कीमत को बाहर करने के कारण आंकड़ों में तोड़ मरोड़ किया गया है।

14.1.3 जनवरी – जून, 2019 के लिए वार्षिक आंकड़ों का उपयोग इस प्रकार के वार्षिकीकरण के लिए आवश्यकता की व्याख्या के अभाव में क्षति संबंधी मानदंडों के विश्लेषण के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में, उन्होंने इंडिया – स्टील सेफगार्ड में पैनल के जांच परिणामों पर निर्भरता दर्शायी है।

14.1.4 बड़े हुए आयातों को दर्शाने में अपर्याप्तता जिसे जापान सहित सभी देशों से आयातों द्वारा बढ़ती हुई प्रवृत्ति को नहीं दर्शाया जाता है। घरेलू उद्योग को हो रही क्षति, यदि कोई हो, चीन से आयातों में अचानक वृद्धि के कारण ही हुई है।

14.1.5 यह अनुरोध किया जाता है कि अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत आयात किये जा रहे केवल एस टी एल (घरेलू उद्योग) के आयातों को बाहर रखना आंकड़ों के विश्लेषण में अनुचित है क्योंकि समान बहिर्गमन अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत पी यू सी के सभी आयातों के लिए किया गया है।

14.1.6 घरेलू उद्योग के आंकड़ों का विश्लेषण गंभीर क्षति के मौजूद रहने को नहीं दर्शाता है। कैप्टिव / संबंधित पक्षकार की बिक्री को बाहर करने के बाद किया गया विश्लेषण घरेलू उद्योग की स्थिति की सही तस्वीर नहीं देता है।

14.1.7 इसके अलावा, यह अनुरोध किया गया था कि आयातों में वृद्धि किसी “अप्रत्याशित घटनाक्रमों” के कारण नहीं हुई थी क्योंकि गैट के अनुच्छेद XIX की आवश्यकता वर्तमान मामले में पूरी नहीं की गई है। थ

क. इस संबंध में यह अनुरोध किया जाता है कि वैश्विक स्तर पर अत्यधिक क्षमता के फलस्वरूप सभी स्रोतों से बढ़ी हुई मात्रा में विचाराधीन उत्पाद का आयात किया जा रहा है। वर्तमान मामले में, अधिकांश आयात (लगभग 84 प्रतिशत) चीन से हुआ है और अन्य देशों जैसे जापान से आयात बहुत कम (2018-19 में 8 प्रतिशत) है।

ख. चीन द्वारा व्यापार उपचार लगाये जाने के फलस्वरूप उन देशों से बढ़ा हुआ आयात होना चाहिए था।

ग. इस तथ्य के संबंध में कोई भी बात नहीं है कि चीन जन. गण. से पी यू सी की कम कीमत पर आयातों के फलस्वरूप भारत में कीमत में कटौती हुई है। इसे देखते हुए, उन्होंने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग को क्षति लेकिन ‘गंभीर क्षति’ नहीं का एकमात्र स्रोत चीन से कम कीमत पर आयातों का होना है।

- 14.1.8 घरेलू उद्योग को चीन से कम कीमत पर आयातों जैसा अनुचित व्यापार प्रथा के कारण नुकसान हो रहा है और इस कारण से उसका उपचार पाठनरोधी प्रावधानों और न कि रक्षोपाय प्रावधान के अंतर्गत किया जाना है। तदनुसार, वर्तमान जांचों को उपनियमावली के अनुबंध के पैरा 8 के संबंध में समाप्त किया जाना चाहिए।
- 14.1.9 घरेलू उद्योग अपनी याचिका में अनुच्छेद XIX के अंतर्गत यथाअपेक्षित “गैट 1994 के अंतर्गत लिये गये दायित्व” के संबंध में कोई दावा करने में असफल रहा है और इसके अलावा, प्रारंभिक जांच परिणामों में भी इस मुद्दे पर कोई विश्लेषण नहीं किया गया है।
- 14.1.10 इसके अलावा निर्यात ने यह दावा किया है कि ग्रेड जी654 को पी यू सी के क्षेत्र से बाहर किया जाना चाहिए क्योंकि इसका उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है।
- 14.1.11 निर्यातक द्वारा निर्माण किये गये ग्रेड जी652, जी655 और जी657 को भी बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पादों और एसईआई द्वारा निर्मित उत्पादों के बीच गुणवत्ता, समय पर डिलीवरी, ग्राहक का समर्थन और पैकेजिंग आदि के संदर्भ में बहुत अधिक अंतर है।
- 14.1.12 घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका में विभिन्न कारकों का कोई सार्थक सारांश दिये बिना अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।

#### **14.2 पारामाउण्ड केबल लिमि., ओरियंट केबल इंडस्ट्रीज लिमि. और ओम ऑप्लट इंडस्ट्रीज प्रा. लिमि.**

- 14.2.1 यद्यपि उपर्युक्त पक्षकारों ने दी गई विस्तारित समयाविधि के दौरान “हितबद्ध पक्षकारों” के रूप में पंजीकृत नहीं किया है फिर भी उनके अनुरोधों को विचार किये जाने के लिए रिकार्ड पर लिया गया है।
- 14.2.2 उक्त पक्षकार संबद्ध वस्तुओं के आयातक हैं। उन्होंने इस जांच की शुरुआत पर आपत्ति की है और यह अनुरोध किया है कि पी यू सी के घरेलू उत्पादकों कोई क्षति नहीं हुई है।
- 14.2.3 उनके द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि एस टी एल को छोड़कर, पी यू सी के सभी भारतीय उत्पादक केबल आयात किये गये प्रीफार्म को ऑप्टिकल फाइबर में परिवर्तित करते हैं और इस कारण से उन्हें एक निर्माण उद्योग के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- 14.2.4 रक्षोपाय शुल्क लगाये जाने के फलस्वरूप पी यू सी की कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि होगी और उसके कारण एम एम ई केबल उद्योग को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
- 14.2.5 इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर पर रक्षोपाय शुल्क लगाये जाने के फलस्वरूप ऑप्टिकल फाइबर केबल के आयात में बहुत अधिक वृद्धि होगी, जिसके फलस्वरूप केबल निर्माता एककों जो आयातों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हो पायेंगे, को बंद करना पड़ सकता है।
- 14.2.6 घरेलू उद्योग के आयातों में पूर्व के वर्षों की तुलना में 2018-19 में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है। एस टी एल द्वारा किये गये ये दावे कि उनके द्वारा किया गया आयात उन ग्रेडों का है जिनका सामान्य तौर पर उनके द्वारा निर्माण नहीं किया जाता है, जूठा प्रतीत होता है। घरेलू उद्योग को उनके द्वारा किये गये आयातों के संबंध में उनके दावों को प्रमाण के आधार पर रखा जाना चाहिए।

#### **14.3 ऑप्टि फाइबर सिस्टम जे एस सी, रूस**

- 14.3.1 वे भारत की कुल संस्थापित क्षमता का लगभग 7-8 प्रतिशत की संस्थापित क्षमता के साथ रूसी संघ में ऑप्टिकल फाइबर का एकमात्र उत्पादक हैं। अतः भारत को उनकी बिक्री बहुत कम मात्रा में हुई है।
- 14.3.2 इस प्रकार से रूसी संघ से आयातों के कारण भारत के उत्पादकों को कभी भी कोई क्षति नहीं हुई है। अतः रूसी संघ से निर्यातों पर कोई रक्षोपाय शुल्क लगाया नहीं जाना चाहिए।

## 15. दिनांक 12.05.2020 को आयोजित आम सुनवाई के बाद प्रस्तुत किया गया लिखित उत्तर

### 15.1 घरेलू उद्योग – एस टी एल और बी एफ एल

- 15.1.1 विचाराधीन उत्पाद (“पी यू सी”) “सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर” (“एम एम ओ एफ”) है जिसका वर्गीकरण सीटीएच 9001 1000 के अंतर्गत किया जा सकता है। यह उत्पाद और इसके ग्रेडों को इंटरनेशनल टेलिकोम्युनिकेशन यूनिय (आई टी यू – टी) के मानकों के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। इन उत्पादों का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर केबल का निर्माण करने के लिए किया जाता है, जिसका प्राथमिक रूप से उपयोग दूरसंचार प्रचालनों, सी ए टी बी, एफ टी टी एच आदि में किया जाता है। घरेलू और आयात किये गये उत्पादों के बीच पूर्ण प्रतिस्थापनीयता होती है। घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद आयात किये गये उत्पाद के तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से सदृश्य है। भारत में ‘समान वस्तु’ के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा (लगभग 60 प्रतिशत) के उत्पादक होने के कारण याचिकाकर्ता “घरेलू उद्योग” के रूप में योग्य हैं।
- 15.1.2 भारतीय मांग का 95 प्रतिशत से अधिक जी652 ग्रेड फाइबर का है। 2018-19 के लिए आंकड़ों से, यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग का आयात और घरेलू बिक्री दोनों का 97 प्रतिशत जी652 फाइबर का था और शेष 3 प्रतिशत अन्य ग्रेडों का था। इस कारण से, चूंकि घरेलू उत्पाद का ग्रेड मिश्रण आयात किये गये उत्पादों के ग्रेड मिश्रण के सदृश्य है, अतः रक्षोपाय जांच में ग्रेडवार विश्लेषण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस संदर्भ में, उन्होंने कुछ स्टील उत्पादों के संबंध में रक्षोपाय जांच में अर्जटीना फुटवियर और यूरोपीय समुदाय के विनियम में अपीलीय निकाय के जांच परिणामों पर विश्वास किया था।
- 15.1.3 उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग के पास एसएमओएफ की सभी ग्रेडों का निर्माण करने की प्रौद्योगिकी और क्षमता है। जी-654 ग्रेड का न तो घरेलू उद्योग द्वारा भारत में आयात किया जाता है और न ही इसकी बिक्री की जाती है क्योंकि भारत में उक्त उत्पाद की कोई मांग नहीं है। इस कारण से पी यू सी के क्षेत्र से जी-654 को बाहर किया जाना आवश्यक नहीं है। इस संदर्भ में, उन्होंने चीन जन. गण. और इजरायल के लोकतांत्रिक गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये सिनकोनस डिजीटल हाइटरकी ट्रांसमिशन इक्यूप्टमेंट (एस टी एच इक्यूप्टमेंट) के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की जांच में दिनांक 12.01.2012 को जारी किये गये अंतिम जांच परिणामों पर विश्वास किया है जिसमें यह माना गया था कि किसी विशेष प्रकार को बाहर किये जाने के लिए दावे को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता है जब तक उसका निर्यात भारत को संगत अवधि के दौरान नहीं किया गया हो।
- 15.1.4 भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातों में 2016-17 और 2017-18 की तुलना में 2018-19 में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है। आधार वर्ष की तुलना किये जाने पर, 2018-19 में 271 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने आगे यह अनुरोध किया है कि तिमाही दर तिमाही विश्लेषण किये जाने से भी यह स्पष्ट है कि 2018-19 के प्रत्येक तिमाही 2019-20 की पहली तिमाही में आयात 2016-17 और 2017-18 की पूर्व वर्षों की तिमाहियों से बहुत अधिक थी।
- 15.1.5 इसके अलावा, यह अनुरोध किया गया है कि अन्य के साथ साथ यू एस – लाइन पाइप और यू एस – स्टील सेफगाइर्स में पैनल द्वारा निर्धारित विधिशास्त्र के साथ पठित गैट की धारा 8ख (1) और अनुच्छेद XIX के अंतर्गत, यह स्पष्ट है कि कानून की आवश्यकता “बढ़े हुए आयातों” का है और न कि “बढ़ती हुई आयातों” का है और इस कारण से जांच की अवधि के अंत में गिरावट के कारण पूर्व की वृद्धि समाप्त नहीं होती है।
- 15.1.6 घरेलू उद्योग को आयातों में अचानक वृद्धि के कारण गंभीर क्षति उठानी पड़ रही है। इस नियमावली के अनुबंध में यथाउलिलिखित सभी संगत पैरा घरेलू उद्योग की स्थिति में बहुत अधिक गिरावट को दर्शाते हैं।

इस प्रकार की गिरावट की अवधि प्रत्यक्ष तौर पर आयातों में अचानक वृद्धि की अवधि के समय में हुई है। अतः गंभीर क्षति और कार्य संबंध की आवश्यकता वर्तमान मामले में पूरी की गई है।

- 15.1.7 इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि अनेक अप्रत्याशित घटनाक्रम जो पिछले वर्षों विशेष रूप से 2016-17 और 2017-18 के दौरान हुई हैं, के एक साथ होने के फलस्वरूप भारत को आयात में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इन कारकों में 5जी को योजनाबद्ध तरीके से आरंभ करने में विलंब, अपेक्षाकृत कम डिजीटलीकरण, चीन के बाजार में आशा से कम मांग, विभिन्न देशों में नई आहरण सुविधाएं को स्थापित करने, जो पूर्व में फाइबर निर्माण देशों में से अधिकांश देशों के विरुद्ध चीन द्वारा व्यापार शुल्कों को लगाये जाने, आयात पर निर्भर होने, यू एस ए, आस्ट्रेलिया आदि जैसे देशों द्वारा चीन से दूरसंचार उपकरण/ संघटकों के आयात पर लगाया गया नीतिगत प्रतिबंध और चीन द्वारा निर्मित फाइबर के विरुद्ध प्रमुख टेलीकॉम ऑपरेटरों (विशेष रूप से पश्चिम यूरोप और यू एस ए के टेलीकॉम ऑपरेटरों) द्वारा लगाये गये अन्य गैर राजकोषीय/ गैर नियामक प्रतिबंधों जिसके फलस्वरूप भारत को आयातों का अचानक विपथन हुआ है, के कारण फाइबर उद्योग में वैश्विक स्तर पर बहुत अधिक क्षमता होना शामिल है।
- 15.1.8 जांच की अवधि की बाद की अवधि में आयातों में गिरावट के संबंध में, यह अनुरोध किया गया है कि यह कानून प्राधिकारी से यह अपेक्षा करता है कि वे जांच की अवधि और न कि उसके बाद की अवधि के संदर्भ में भी “बढ़े हुए आयातों” की जांच करें। हालांकि, उपर्युक्त के संबंध में पूर्वाग्रह के बिना यह भी अनुरोध किया गया है कि यदि आयातों में कोई गिरावट होती है तब इसकी जांच इस तथ्य के संबंध में की जानी अपेक्षित है कि क्या आयातों में गिरावट, यदि कोई हो एक अस्थायी घटना है अथवा नहीं (**संदर्भ – अर्जटीना फुटवियर में अपीलीय निकाय और डोमिनियम रिपब्लिक – ट्यूबलर बैग और पोलिप्रोपलिन बैग में पैनल**)।
- 15.1.9 चूंकि 2019-20 की दूसरी तिमाही में आयातों में गिरावट संकटग्रस्त दूसरंसचार क्षेत्र आपवादिक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सामना किये जा रहे सरलता की समस्या, भारी मानसून, भारत में परियोजनाओं आदि की घोषणा में विलंब के कारण भारत की मांग में कोई अस्थायी गिरावट के कारण हुआ था, इस कारण से “बढ़े हुए आयातों” की जांच करने के लिए इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, तिमाही 2 की तुलना में 2019-20 की तिमाही 3 में आयातों में गिरावट मुख्य रूप से आयातों को प्रतिस्थापित करते हुए घरेलू बिक्री के कारण हुआ है क्योंकि आयातक 25 प्रतिशत अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क का खतरा लेने से बचना चाहते थे। हालांकि, इस प्रकार की बिक्री उस कीमत पर की जानी थी जो आयात की कीमतों से तुलनीय हो और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान और अधिक हो गई है। गंभीर क्षति के प्रायः सभी मानदंडों की स्थिति आगे जांच की अवधि की बाद की अवधि में बदतर हो गई है और घरेलू उद्योग बंद होने के कगार पर है।
- 15.1.10 आगे यह भी अनुरोध किया है कि 2019-20 की दूसरी तिमाही में आयातों में गिरावट के बावजूद, ये आयात आधार वर्ष की तुलना में स्वतंत्र रूप में तथा घरेलू उत्पादन की तुलना में 2019-20 में “2019-20 के पहली और दूसरी तिमाही के आधार पर वार्षिकीकृत” में बहुत अधिक उच्च स्तरों पर होना जारी रहा है। इसके अलावा स्टेनेलॉन आधार पर भी, घरेलू उत्पादन की तुलना में आयातों में वृद्धि 2016-17 और 2017-18 स्तरों की तुलना में 2019-20 की दूसरी तिमाही में अपेक्षाकृत बहुत अधिक स्तर पर रही है। इस प्रकार से, 2019-20 की दूसरी तिमाही में भी आयात बढ़े हुए स्तर पर होना जारी रहा है।

- 15.1.11 यह भी अनुरोध किया गया था कि वर्तमान मामला पाटनरोधी शुल्क के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि जांच की अवधि के दौरान पाटित कीमतों पर आयात के होने का कोई साक्ष्य नहीं है। इसके अलावा, सभी प्रमुख निर्यात करने वाले देशों की कीमतें उसी सीमा में हैं, केवल जापान की कीमत चीन से कम है। इसके अलावा, अधिकांश एम एम ओ एक निर्माताओं की या तो कुल स्वामित्व वाली संयंत्रों के माध्यम से अथवा विभिन्न देशों में संयुक्त उद्यमों के द्वारा मौजूदगी है। इस कारण से, देश विशिष्ट पाटनरोधी शुल्क लगाना घरेलू उद्योग को समुचित संरक्षण नहीं देगा।
- 15.1.12 शुल्कों को लगाया जाना जनहित में है क्योंकि घरेलू उद्योग को इस प्रकार संरक्षण दिये बिना वह जिंदा रहने में सक्षम नहीं होगा। इसके अलावा, टेलिकॉम ऑपरेटरों (प्रयोक्ता उद्योग) पर शुल्कों के प्रभाव के बारे में याचिकाकर्ताओं की राय में यह प्रभाव उनकी लागत से 1 प्रतिशत से कम है। केबलर भी शुल्कों के प्रभाव को टेलिकॉम ऑपरेटरों पर डालने में सक्षम हुए हैं क्योंकि केबल की कीमतें हमेशा फाइबर की कीमतों से प्रभावित होती हैं। इसके अलावा, भरोसेमंद घरेलू उद्योग का होना प्रयोक्ता उद्योग अर्थात् केबल उद्योग और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के भी व्यापक हित में है।
- 15.1.13 इस कारण से उन्होंने गंभीर क्षति को रोकने अथवा उसका उपचार करने के लिए तथा सकारात्मक समायोजन को आसान बनाने के लिए क्षति के मार्जिन की पूरी सीमा तक रक्षोपाय शुल्क को तत्काल लगाने का अनुरोध किया है।
- 15.2 कोरनिंग टेक्नोलॉजी इंडिया प्रा. लिमि. और कोरनिंग फिनोलेक्स आप्टिकल फाइबर प्रा. लिमि.** (“कोरनिंग”)
- 15.2.1 स्वतंत्र रूप में आयातों में वृद्धि**
- क. एस एम ओ एफ के कुल आयात में 2016-17 की तुलना में 2018-19 में बहुत अधिक हद तक 5 गुणा से अधिक वृद्धि हुई है और वह उसके बाद बढ़ते हुए स्तर पर लगातार हो रही है।
  - ख. घरेलू उद्योग द्वारा किये गये आयातों को बाहर किये जाने के बाद एस एम ओ एफ के आयातों में भी 2016-17 की तुलना में 2018-19 और जनवरी से जून 2019 के दौरान (वार्षिकीकृत) के दौरान 3 गुणा से अधिक वृद्धि हुई है।
- 15.2.2 सापेक्ष रूप में आयातों में वृद्धि**
- क. घरेलू उत्पादन की तुलना में, पी यू सी के आयातों में (घरेलू उद्योग के आयातों को छोड़कर) 2016-17 से जनवरी – जून 2019 के दौरान सतत रूप से वृद्धि हुई है और यह आधार वर्ष से 3 गुणा से अधिक हो गया है।
  - ख. भारतीय मांग में आयातों के हिस्से में (घरेलू उद्योग के आयातों को छोड़कर) 2016-17 की तुलना में 2018-19 में पांच गुणा तक वृद्धि हुई है और इसका उसके बाद बढ़ना जारी रहा है।
- 15.2.3 जांच की अवधि के दौरान आयातों में वृद्धि**
- क. जांच की अवधि की बाद की अवधि में आयातों में गिरावट आयातों में वृद्धि के आकलन के लिए संगत नहीं है।
  - ख. यू एस-लाइन पाइप (सेफगार्ड) मामले में विश्व व्यापार संगठन के पैनल में यह नोट किया कि आयातों में “हालिया” वृद्धि का अभिपाय यह नहीं होता है कि इसे जांच करने वाले प्राधिकारी के निर्धारण के तत्काल पूर्व की अवधि और न ही जांच की अवधि के अंत तक की अवधि तक जारी रहना चाहिए।

### **15.2.4 अप्रत्याशित घटनाक्रम**

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाये गये प्रशुल्क, चीन में मांग में गिरावट, प्री-फार्म क्षमता की संस्थापना अप्रत्याशित स्थिति है जिसके फलस्वरूप चीन जन. गण. में अत्यधिक क्षमता और उसके परिणामस्वरूप भारत में आयातों में वृद्धि हुई है।

### **15.2.5 गंभीर क्षति**

- क. जांच की अवधि के दौरान बाजार हिस्से, बिक्री, उत्पादन, उत्पादकता, क्षमता का उपयोग, लाभप्रदता और रोजगार में गिरावट आई है।
- ख. घरेलू उद्योग और कोरनिंग दोनों को आयातों की पहुंच मूल्य में गिरावट के कारण कीमत पर दबाव देखना पड़ रहा है। जांच की अवधि के पिछले छः महीनों में कोरनिंग की घरेलू बिक्री कीमत में 22 अंकों तक गिरावट आई है। घरेलू उत्पादक बिक्री की लागत में परिवर्तन के अनुपात में बिक्री कीमत को बनाये रखने में सक्षम नहीं हैं।

### **15.2.6 बढ़े हुए आयातों और गंभीर क्षति के बीच कारणात्मक संबंध**

घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में गिरावट उसी अवधि में हुआ है जिस अवधि में आयातों में अचानक और बहुत अधिक वृद्धि हुई थी। अन्य कारक जैसे खपत, निर्यात कार्यनिष्पादन, प्रौद्योगिकी के विकास आदि में गिरावट के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

### **15.3 एच एफ सी एल लिमि.**

- 15.3.1 दिनांक 23.09.2019 की जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में दिये गये अनुसार विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा ने पी यू सी की परिभाषा में उनके संबंधित कोड के साथ ऑप्टिकल फाइबर के कुछ प्रकारों को शामिल किया है। हालांकि, ऑप्टिकल फाइबर के इनमें से कुछ प्रकार और अधिक विशिष्ट रूप से डिस्प्रेशन शिफिटिड फाइबर (जी.653), कट-ऑफ शिफिटिड सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर (जी 654), नॉन जीरा डिस्प्रेशन शिफिटिड फाइबर (जी.655 और जी.656) और बेंड इंसेटिव सिंगल मोड फाइबर (जी.657 ए1 और ए2) का भारत में प्रायः मामूली मात्रा में आयात हुआ है।
- 15.3.2 इसके अलावा, यह सत्यापित किया जा सकता है कि ऑप्टिकल फाइबर केवल और अन्य उत्पादों जिसका निर्माण नॉन डिस्प्रेशन शिफिटिड फाइबर (जी.652) को छोड़कर ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करते हुए किया जाता है, का प्रमुख रूप से निर्यात भारत में मांग और बाजार के न रहने के कारण भारतीय घरेलू बाजार में उपयोग करने के बजाय भारत से बाहर किया जाता है। इस कारण से नॉन डिस्प्रेशन शिफिटिड फाइबर (जी.652) को छोड़कर ऑप्टिकल फाइबर के आयातों से घरेलू उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।
- 15.3.3 घरेलू उद्योग ने अपने पी यू सी के अपने उत्पादन, बिक्री, निर्यात आदि का कोई ब्यौरा अथवा दो भागों में विभक्त (ग्रेड वार) भी नहीं उपलब्ध कराया है, जिसकी जांच प्राधिकारी द्वारा की जानी अपेक्षित है।
- 15.3.4 इन ग्रेडों डिस्प्रेशन शिफिटिड फाइबर (जी.653), कट-ऑफ शिफिटिड सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर (जी 654), नॉन जीरा डिस्प्रेशन शिफिटिड फाइबर (जी.655 और जी.656) और बेंड इंसेटिव सिंगल मोड फाइबर (जी.657 ए1 और ए2) की कीमतें जी.652 की कीमतों की तुलना में पर्याप्त रूप से अधिक हैं। इन सभी ग्रेडों की तुलना की जा सकती है और उन्हें एक ही माना जा सकता है।
- 15.3.5 इस संदर्भ में उन्होंने अनुरोध किया है कि “भारत में प्रोजेक्ट्स”, बी एस एन एल, बी बी एन एल, रेलवे, पी जी सी आई एल, रेलटेल और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए भी केवल जी652 डी फाइबरों के उपयोग का उल्लेख है। इस कारण से, पी यू सी के अन्य ग्रेडों को पी यू सी की परिभाषा से बाहर रखा

जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग पी यू सी में सभी प्रकार के फाइबरों को शामिल कर अपना एकाधिकार बनाना चाहता है।

#### 15.4 सुमिटोमो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज लिमि., जापान

- 15.4.1 घरेलू उद्योग को क्षति, यदि कोई हो केवल कीमत संबंधी क्षति के साथ चीन जन. गण. से बहुत अधिक मात्रा में आयातों के कारण हुआ है। इस कारण से इस प्रकार की क्षति को दूर करने के लिए उपयुक्त मंच पाटनरोधी जांच के माध्यम से है जो रक्षोपाय जांच के विरुद्ध है, जो सभी देशों से आयातों को प्रभावित करता है। इस प्रकार से वर्तमान जांचों को समाप्त किया जाये।
- 15.4.2 घरेलू उद्योग “अप्रत्याशित घटनाक्रम” जिसके फलस्वरूप आयातों में अचानक वृद्धि “यदि कोई हो”, हुआ हो, को प्रस्तुत करने में असफल रहा है। घरेलू उद्योग द्वारा ‘अप्रत्याशित परिस्थितियों’ को स्थापित करने के रूप में अपनी याचिका में उल्लिखित कारणों में किसी भी कारण का समाधान विशेष रूप से संबद्ध जांच में पी यू सी के आयात के प्रति नहीं किया गया है। बल्कि घरेलू उद्योग ने ‘आप्टिक फाइबर’ की व्यापक श्रेणी में अचानक वृद्धि का आरोप लगाया है। यह अनुरोध किया जाता है कि समग्र ‘आप्टिक फाइबर उद्योग’ की व्यापक श्रेणी में कुछ अप्रत्याशित घटनाक्रमों का आरोप मात्र अप्रत्याशित घटनाक्रमों और भारत में पी यू सी के आयातों में अचानक वृद्धि के बीच तार्किक संबंध को दर्शाने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- 15.4.3 पी यू सी के लिए डी जी सी आई एंड एस आयात संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण आयातों में हालिया, अचानक, तीव्र और बहुत अधिक वृद्धि को दर्शाता है जिसके कारण रक्षोपाय शुल्क लगाना आवश्यक हो गया है। आयात के आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि जांच की पूरी अवधि के दौरान तथा एंड टू एंड विश्लेषण के आधार पर भी पी यू सी के आयात की कोई बढ़ती हुई प्रवृत्ति नहीं है, आयात संबंधी मात्राओं में बहुत अधिक हद तक गिरावट आई है।
- 15.4.4 उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि 2019-20 की पहली तिमाही के लिए आयात संबंधी आंकड़े सही नहीं हैं।
- 15.4.5 इसके अलावा, चूंकि वर्तमान रक्षोपाय जांच की शुरुआत और उसके साथ ही जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में पहचान की गई ‘सबसे अधिक हाल की अवधि’ के समय से बहुत अधिक समय बीत चुका है अतः जांच की अवधि के बाद की अवधि के आंकड़ों का विश्लेषण वर्तमान मामले में आवश्यक नहीं है। इस संबंध में यह नोट किया जाना चाहिए कि वित्तीय वर्ष 2019-20 की दूसरी और तीसरी तिमाही के लिए आंकड़ों के अनुसार, पी यू सी के आयातों में बहुत अधिक हद तक गिरावट आई है।
- 15.4.6 इसके अलावा, यदि आयात संबंधी मात्राओं का विश्लेषण एंड टू एंड आधार पर किया जाना था तब यह पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि आयातों में 2017-18 की पहली तिमाही में 769 केएफकेएम से 2019-20 की तीसरी तिमाही में 273 केएफकेएम तक गिरावट आई है और इस प्रकार से इसमें 496 केएफकेएम का अंतर है।
- 15.4.7 आर्थिक और कार्यनिष्पादन संबंधी मानदंड का समग्र विश्लेषण यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई जांच और इसके कार्यनिष्पादन के संबंध में उपलब्ध कराये गये आंकड़े न तो समुचित हैं और न ही पर्याप्त और इसके साथ ही वह गलत आंकड़ों पर आधारित है। इस प्रकार से घरेलू उद्योग के दावे के संबंध में उपलब्ध कराये गये और विचार किये गये आंकड़े तथा घरेलू उद्योग को हो रही गंभीर क्षति के प्रारंभिक जांच परिणाम पी यू सी के संबंध में घरेलू बाजार की स्थिति की सही तस्वीर नहीं दर्शाते हैं।

- 15.4.8 इसके अलावा, घरेलू उद्योग की आर्थिक और कार्यनिष्पादन संबंधी मानदंडों के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध सीमित आंकड़ों को देखते हुए, इन मानदंडों ने पर्याप्त सुधार दर्शाया है। इस प्रकार से ऐसे मानदंडों के विश्लेषण पर निर्भर रहते हुए क्षति के किसी दावे को कृपया माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार किया जाये।
- 15.4.9 घरेलू उद्योग एक अर्थक्षम समायोजन योजना जो भारतीय रक्षोपाय कानूनों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अपेक्षा है उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं हुआ है। आवेदकों ने संपूर्ण समायोजन योजना के संबंध में उसका एक सार्थक अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराये बिना अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। उन्होंने गोपनीयता के लिए अपने दावे के संबंध में कोई सही कारण उपलब्ध नहीं कराया है।
- 15.4.10 उत्पाद ग्रेड जी.654 को वर्तमान जांच में पी यू सी के क्षेत्र से बाहर किया जाना चाहिए क्योंकि उसका निर्माण घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है और न ही इसके पास वैसा करने की क्षमता है।
- 15.4.11 इसके अलावा, उत्पाद ग्रेड जी.652.डी, जी.655 और जी.657. ए1 को भी वर्तमान जांच में पी यू सी के क्षेत्र से बाहर किया जाना चाहिए क्योंकि एस ई आई द्वारा निर्यात किये गये पी यू सी और घरेलू उद्योग द्वारा निर्माण किये गये उत्पाद के बीच भौतिक गुणों, उपभोक्ता की पसंद, गुणवत्ता आदि के संबंध में बहुत अधिक अंतर है।
- 15.4.12 इसके अलावा यह अनुरोध किया गया था कि चूंकि अग्रिम अधिकरण योजना के अंतर्गत आयात घरेलू उत्पादों से प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं क्योंकि वे निर्यात बाजार की ओर निर्देशित हैं और उसके कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं होती है, उन्हें वर्तमान जांच में आयात के विश्लेषण से बाहर किया जाना चाहिए।
- 15.4.13 घरेलू उद्योग पी यू सी बढ़े हुए आयातों और उससे घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करने में असफल रहा है।
- 15.4.14 अंत में, यह अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग यह दर्शाने में सफल नहीं हुआ है कि रक्षोपाय शुल्क लगाया जाना 'जनहित' में है जिसकी परिकल्पना रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया गया है।
- 15.5 फाइबरहोम इंडिया प्रा. लिमि.**
- 15.5.1 उन्होंने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग प्रथम दृश्या 'अप्रत्याशित घटनाक्रमों' जिसके फलस्वरूप भारत में विचाराधीन उत्पाद का बढ़ा हुआ आयात हुआ है कि पहचान करने में असफल रहे हैं। अतः गैट के अनुच्छेद XIX की अपेक्षा को वर्तमान मामले में पूरा नहीं किया गया है।
- 15.5.2 इसके अलावा, यह अनुरोध किया गया है कि चूंकि रक्षोपाय शुल्क "बिना किसी त्रुटि वाले सिद्धांत" पर आधारित है, इस कारण से उनको अपनाने का तरीका तभी लिया जा सकता है जब गुणों के आधार पर बहुत मजबूत मामला हो और कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं हो।
- 15.5.3 एस टी एल की स्टेण्डएलॉन वित्तीय विवरण यह सुझाव देता है कि उन्होंने जांच की अवधि के दौरान अधिक लाभ अर्जित किया है और इस कारण से ऐसा प्रतीत होता है कि याचिका में उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों में हेर केर किया गया है।
- 15.5.4 घरेलू उद्योग के घरेलू उत्पादन में बहुत अधिक सीमा तक वृद्धि हुई है, यदि उन्होंने स्वयं भारी मात्रा में आयात नहीं किया होता। इस प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही यदि कोई हो, का कारण स्वतंत्र आयातों को नहीं माना जा सकता है।

- 15.5.5 सबसे हाल की अवधि अर्थात् जनवरी से जून 2019 में कुल आयातों में गिरावट आई है अतः बढ़े हुए आयातों की आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया है।
- 15.5.6 घरेलू उद्योग अर्थक्षम समायोजन योजना देने में असफल रहा है। समायोजन के अभाव में, रक्षोपाय जांच को समाप्त किये जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में, 1999 में यूनाटेड फोस्फोरस द्वारा दायर किये गये आवेदन में महानिदेशक रक्षोपाय द्वारा जारी किये गये जांच परिणामों तथा **यूनाटेड फोस्फोरस बनाम महानिदेशक (रक्षोपाय) 2000 (118) ई.एल.टी. 326 (डीईएल)** के निर्णय का हवाला दिया गया है।
- 15.5.7 यह भी अनुरोध किया गया था कि वर्तमान मामले में रक्षोपाय शुल्क लगाया जाना जनहित के विरुद्ध होगा क्योंकि इसके फलस्वरूप अनिवार्य रूप से देश में रोजगार और आर्थिक क्रियाकलाप में कमी आयेगी और आप्टिकल फाइबर केबल के आयातों को प्रोत्साहन मिलेगा।
- 15.6 पारामाउण्ड वॉयर्स एंड केबल्स लिमि.**
- उन्होंने दिनांक 20.01.2020 के पत्र के माध्यम से किये गये अपने अनुरोधों को दोहराया है, जिसकी चर्चा ऊपर में की गई है।
- 15.7 इंडोनेशिया सरकार, ब्राजील सरकार और ताइवान सरकार**
- 15.7.1 इण्डोनेशिया सरकार, ब्राजील सरकार और ताइवान सरकार ने रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 9.1 का पालन करने का अनुरोध किया है जिसमें विकासशील देश जहां से आयात न्यूनतम स्तर से कम पर किये गये हैं, को बाहर किये जाने का प्रावधान है।
- 15.7.2 यह अनुरोध किया गया है कि चूंकि उपर्युक्त देशों से आयात 30 प्रतिशत से कम है अतः किसी भी रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश भारत को पी यू सी के उनके निर्यातों पर नहीं की जानी चाहिए।
- 15.8 रूस फेडरेशन सरकार**
- 15.8.1 रक्षोपाय जांच की अंतर्गत गंभीर चुनौती को सिद्ध करने की आवश्यकताएं पाटनरोधी जांच में सिद्ध करने की आवश्यकताओं से बहुत अधिक कठोर हैं। रक्षोपाय शुल्क केवल विशेष परिस्थितियों में लगाया जायेगा।
- 15.8.2 रूस से निर्यात भारत में पी यू सी के कुल आयातों का 0.2 प्रतिशत है अतः रूस से आयातों के द्वारा घरेलू उत्पादकों को कोई क्षति होने की संभावना नहीं है।
- 15.9 जापान सरकार**
- 15.9.1 डीएस 98 और डीएस 252 ने पैनल/ ए.बी.रिपोर्टों के मद्देनजर प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वे ‘अप्रत्याशित घटनाक्रमों’ जिसके फलस्वरूप आयातों में वृद्धि हुई है, का निर्धारण करें और तब आयात किये गये और घरेलू उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धी संबद्ध में बदलाव करते हुए घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति का निर्धारण करें।
- 15.9.2 वैश्विक स्तर पर अत्यधिक क्षमता दीर्घावधिक मांग और आपूर्ति की स्थिति का परिणाम मात्र है और उसे आवश्यक रूप से ‘अप्रत्याशित’ के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, अन्य देशों द्वारा लगाये गये आयात प्रतिबंधात्मक शुल्कों का मुकाबला करने के लिए आयात प्रतिबंधात्मक शुल्क लगाने से वैश्विक व्यापार में तोड़-मरोड़ होगा।
- 15.9.3 भारत सरकार ‘गैट के अंतर्गत’ प्राप्त दायित्व के साथ बढ़े हुए आयातों का संबंध स्थापित करने में असफल रहा है।

- 15.9.4 चूंकि पी यू सी का भारत में अधिकांश आयात चीन से होता है अतः भारत सरकार को उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में स्पष्ट रूप से पुष्टि करनी चाहिए जिनके आयातों के कारण भारतीय घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हो रही है। इसके अलावा, चूंकि आयात कुछ चुनिंदे देशों से हो रहा है, यह देखा जाना है कि क्या रक्षोपाय शुल्क सबसे उपयुक्त होगा।
- 15.9.5 रक्षोपाय शुल्क लगाने से भारत की डिजीटल अवसंरचना विकास परियोजनाएं बाधित होगी क्योंकि इस प्रकार के शुल्क राष्ट्रीय हित में नहीं होंगे।
16. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिखित अनुरोधों के संबंध में प्रतिउत्तर में प्रस्तुत किये गये संगत मुद्दों का सार दिनांक 12.05.2020 को आयाजित जन सुनवाई के बाद प्रस्तुत किया गया जो नीचे दिये गये अनुसार है :
- 16.1 घरेलू उद्योग – एस टी एल और बी एफ एल**
- 16.1.1 जांच की अवधि की बाद की अवधि में आयातों में गिरावट**
- क. गैट की धारा 8ख और अनुच्छेद XIX के अंतर्गत अपेक्षा “बढ़े हुए आयातों” का है और न कि “बढ़ती हुई आयातों” का। इस प्रकार से आयातों में प्रत्येक कमी “बढ़े हुए आयातों” के निर्धारण को रोकता है। यदि इसे स्थापित किया जा सकता है कि कमी के बावजूद आयात आधार वर्ष अथवा पिछले वर्ष की तुलना में “बढ़े हुए स्तर” पर होना जारी है।
  - ख. इसके अलावा, “बढ़े हुए आयातों” का विश्लेषण इस जांच की शुरुआत के समय यथापरिभाषित पर्याप्त रूप से लंबी अवधि की जांच ('पी ओ आई') के लिए किया जाना है ताकि अस्थाई अंतर और मौसमी गिरावट बराबर हो सके। जांच की अवधि की बाद की छोटी अवधि के लिए आंकड़ों का विश्लेषण कानून के अंतर्गत यथाअपेक्षित “बढ़े हुए आयातों” का वस्तुपरक मूल्यांकन करने की अनुमति नहीं देगी।
  - ग. 2019-20 की दूसरी तिमाही (अर्थात जांच की अवधि की बाद की अवधि) में आयातों का बढ़े हुए स्तरों पर होना जारी रहा है। स्टेण्डएलॉन आधार पर भी, 19-20 की दूसरी तिमाही में उत्पादन के प्रतिशत के रूप में आयात 2016-17 का 186 प्रतिशत और 2017-18 के स्तर का 162 प्रतिशत था। इस कारण से, ‘‘बढ़े हुए आयातों’’ की आवश्यकता जांच की अवधि की बाद की अवधि में भी पूरी कर ली गई है।
  - घ. पहली तिमाही की तुलना में 19-20 की दूसरी तिमाही में आयातों में अस्थाई गिरावट कुछ बाजार कारकों के कारण इस उत्पाद की मांग में अस्थाई संकुचन के कारण हुई थी। यह एक सामान्य कानून है कि बाजार में अस्थाई गिरावट और अंतरों पर ‘‘बढ़े हुए आयातों’’ का मूल्यांकन करते समय विचार नहीं किया जाना चाहिए।
  - ड. 2019-20 की तीसरी तिमाही में वर्तमान जांच की शुरुआत की गई थी और प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किये गये थे जिसके कारण घरेलू बाजार की स्थिति खराब हो गई। इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग तीसरी तिमाही में आयातों को प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं था। हालांकि, इस प्रकार की बिक्री उस कीमत पर की गई थी जिसकी तुलना आयातों कीमतों से की जा सकती है और इस कारण से, बिक्री की प्राप्ति बहुत कम थी और इससे घरेलू उद्योग को और अधिक गंभीर क्षति हुई।
  - च. इस कारण से यह अनुरोध किया गया था कि क्षति की बाद की अवधि के लिए आयात संबंधी आंकड़ों पर ‘‘बढ़े हुए आयातों’’ का निर्धारण करने के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।

पूर्वाग्रह के बिना यदि उस पर विचार भी किया जाता है तब “बढ़े हुए स्तर” पर आयातों के जारी रहने के साथ “बढ़े हुए आयातों” का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है।

### 16.1.2 पी यू सी के क्षेत्र से कुछ ग्रेडों को बाहर रखना

- क. कुछ ग्रेड को बाहर रखने के लिए किये गये अनुरोधों के संबंध में, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि रक्षोपाय कानून के अंतर्गत ग्रेड-वार विश्लेषण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, विशेषकर उन मामलों में जहां आयात किये गये उत्पाद का ग्रेड मिश्रण घरेलू उत्पादों के ग्रेड मिश्रण के समान है। (संदर्भ – कुछ स्टील उत्पादों के आयातों के संबंध में रक्षोपाय जांच में अर्जटीना फुटवियर और यूरोपीय कमीशन विनियम में अपीलीय निकाय)
- ख. वर्तमान मामले में, भारतीय मांग का लगभग 95-97 प्रतिशत जी652 ग्रेड का है और 5-3 प्रतिशत अन्य ग्रेडों जैसे जी657, जी655 आदि का है। 2018-19 के आयात आंकड़ों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि आयात किये गये उत्पादों का ग्रेड मिश्रण घरेलू उत्पादों के ग्रेड मिश्रण का सदृश्य है। इस कारण से वर्तमान जांच में ग्रेड-वार विश्लेषण करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- ग. ग्रेड जी654 को बाहर रखने के संबंध में, यह अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग के पास जी654 ग्रेड का निर्माण करने के लिए प्रौद्योगिकी और क्षमता है। हालांकि, चूंकि भारत में उक्त ग्रेड की कोई वाणिज्यिक मांग नहीं है अतः उसका न तो भारत में उत्पादन किया गया है और न ही आयात किया गया है। जब उक्त ग्रेड का आयात भारत में नहीं किया गया है तब समान उत्पाद की अनुउपलब्धता का प्रश्न इस आधार पर की घरेलू उद्योग ने उस उक्त ग्रेड का उत्पादन नहीं किया है, नहीं उठता है।
- घ. इसके अलावा, चूंकि पी यू सी के ग्रेडों को आंशिक रूप से एक दूसरे ग्रेडों से बदला जा सकता है और उनका समान अंतिम उपयोग है। अतः बिना किसी स्पष्ट कारण के कुछ ग्रेडों को बाहर करने से शुल्क, यदि लगाया गया हो का संपूर्ण उद्देश्य व्यर्थ हो जायेगा। इसके अलावा, पी यू सी के सभी ग्रेड स्पष्ट रूप से सदृश्य हैं और उनकी विक्री समान चैनलों के माध्यम से की जाती है, उनमें उत्पादकों/ ग्राहकों का वही समुच्चय होता है और उनका वर्गीकरण उसी सीटीएच 9001 1000 के अंतर्गत किया जा सकता है। अतः ग्रेडों को बाहर करने के फलस्वरूप किसी रक्षोपाय शुल्क जिसे लगाया जा सकता है कि प्रवचना होगी।

### 16.1.3 रक्षोपाय शुल्क के बजाय पाटनरोधी शुल्क के अंतर्गत मार्ग

- क. सभी प्रमुख निर्यातक देशों से आयात की कीमतें 2018-19 तथा जनवरी – जून 2019 के दौरान उसी सीमा में रही हैं। अतः यह आरोप लगाना कि घरेलू उद्योग को क्षति चीन से कम कीमत पर आयातों के कारण हुआ है, का कोई आधार नहीं है। इसके अलावा, किसी भी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह दर्शाने के लिए की चीन से आयात पाटित कीमतों पर हुए थे, कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- ख. इसके अलावा यह स्वीकारोक्ति की केवल चीन से आयातों में वृद्धि हुई है, सही नहीं है क्योंकि आयात संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि कई अन्य देशों जिसमें यू.एस.ए, कोरिया, इण्डोनेशिया आदि से आयातों में आधार वर्ष की तुलना में 2018-19 के दौरान वृद्धि हुई थी।
- ग. इसके अलावा, चूंकि एसएमओएफ का उत्पादन करने वाली अधिकांश कंपनियों का या ता पूर्ण रूप से स्वामित्व वाले संयंत्रों के माध्यम से अथवा विभिन्न देशों में संयुक्त उद्यमों के माध्यम से

वैश्विक उपस्थिति है अतः इस बात की पूरी संभावना है कि किसी देश विशिष्ट शुल्क की लेवी से बचने के उद्देश्य से ये कंपनियां अन्य ध्वेत्राधिकार में अपनी कंपनियों के माध्यम से निर्यात करना शुरू करती है।

- घ. चूंकि पाटनरोधी शुल्क “पाटिट आयातों” के विरुद्ध और न कि “सस्ते आयातों” अथवा “बढ़े हुए आयातों” के विरुद्ध लगाया गया है, यह अनुरोध किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क वर्तमान परिस्थितियों में अर्थक्षम विकल्प नहीं है।

#### 16.1.4 अप्रत्याशित घटनाक्रम

यह अनुरोध किया गया है कि विभिन्न कारकों के एक समय होने के फलस्वरूप भारत में आयातों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इनमें से कुछ कारक नीचे दिये गये हैं :

- क. घोषित 5जी रॉल आउट योजनाओं में विलंब, एफ टी टी एच की तैनाती आशा से कम गति से और चीन की मांग में बहुत अधिक गिरावट के साथ ध्रीमी गति से डिजीटलीकरण जो वैश्विक एसएमओएफ का 50 प्रतिशत से अधिक खपत करता है, के कारण वैश्विक स्तर पर अत्यधिक क्षमता रही।
- ख. पी यू सी के आयात पर अनेक देशों द्वारा व्यापार अवरोध लगाना जिसके कारण पी यू सी के वैश्विक बाजार की गति में परिवर्तन आया।
- ग. चीन के फाइबर के प्रवेश पर कठोर प्रतिबंध लगाते हुए अधिकांश पश्चिमी देशों में टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा लगाया गया विभिन्न गैर नियामक/ गैर राजकोषीय अवरोध।

16.1.5 घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि प्रत्याशित वर्षवार बचत के साथ-साथ एक विस्तृत समायोजन योजना इस याचिका में दी गई है। यह नोट किया जा सकता है कि एसएमओएफ उद्योग प्रौद्योगिकी पर जोर देने वाला उद्योग है। चूंकि समायोजन योजना ट्रेड मार्क युक्त प्रौद्योगिकी के विकास और प्रक्रिया/पद्धतियों से संबंधित है जिसके फलस्वरूप कम्ब्ल माल और संसाधनों की बेहतर उपयोगिता होगी, याचिकाकर्ताओं ने इस पर गोपनीयता का दावा किया है।

16.1.6 कंपनी स्तर पर एसटीएल द्वारा प्रकाशित वित्तीय विवरण/तुलन-पत्र अथवा दिए गए कथन के संदर्भ में, यह अनुरोध किया गया है कि पीयूसी अर्थात ऑप्टीकल फाइबर यूनिट के साथ-साथ, एसटीएल की कई अन्य व्यापार इकाईयां जैसे ऑप्टीकल फाइबर केबल, कॉपर केबल, सर्विसेज, साफ्टवेयर आदि हैं। कंपनी का वित्तीय विवरण इस प्रकार की सभी बिजनेस इकाईयों से संबंधित है और इस कारण से वह वर्तमान जांच के क्षेत्र से परे है।

16.1.7 इस दावे के संबंध में कि रक्षोपाय शुल्क एक ऐसा शुल्क है जिसमें “कोई त्रुटि नहीं है”, याचिकाकर्ताओं ने यह अनुरोध किया है कि सहमति से रक्षोपाय शुल्क “बिना त्रुटि वाला शुल्क” है और इस कारण से “दंडात्मक उपाय” नहीं है। उन्हें केवल उसी सीमा तक लगाया जाता है जिस सीमा तक वह गंभीर क्षति को रोकने अथवा उसका निवारण करने और आयात संबंधी प्रतिस्पर्धा के प्रति समायोजन करने के लिए घरेलू उत्पादकों को सहज बनाने के लिए आवश्यक हो।

#### 16.2 फाइबरहोम इंडिया प्रा. लि.

16.2.1 घरेलू उद्योग का आयातों और गंभीर क्षति में अचानक वृद्धि के संबंध दावे का कोई आधार नहीं है क्योंकि यह इस याचिका में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है।

16.2.2 इसके अलावा, आयातों में 2018-19 की दूसरी तिमाही से (2797) से 2019-20 की तीसरी तिमाही(305) तक लगभग 89 प्रतिशत गिरावट आई है जो एक बहुत बड़ी गिरावट है। जब आयातों में 2018-19 की दूसरी तिमाही और 2019-20 की तीसरी तिमाही जो सबसे हाल की अवधि है और जिसमें जांच की अवधि शामिल है के बीच 89 प्रतिशत तक गिरावट आई है, यह कहना पूर्ण रूप सही नहीं है कि आयातों में कुछ उछाल आयात है।

16.2.3 घरेलू उद्योग गंभीर क्षति, गंभीर क्षति के खतरे अथवा उनके द्वारा सामना की जा रही क्षति और आयातों के बीच किसी कारणात्मक संबंध को स्थापित करने में असफल रहा है। अतः रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के लिए पूर्व अपेक्षा वर्तमान मामले में पूरा नहीं किया गया है।

16.2.4 इन अनुरोधों के संबंध में कि जांच की बाद की अवधि में आयातों पर विचार नहीं किया जाना है, यह अनुरोध किया जाता है कि घरेलू उद्योग को उच्च मानदंडों के लिए जांच की अवधि की आंकड़ों पर चयनित रूप से विश्वास करने तथा अन्य के लिए इसकी अपेक्षा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

16.2.5 इसके अलावा, घरेलू उद्योग का यह मानना कि मांग में गिरावट के साथ-साथ आयातों में गिरावट हुई थी का अर्थ यह है कि मांग में गिरावट के आधार पर कार्य-निष्पादन में अस्थाई सुधार को रक्षोपाय शुल्क लगाकर रोका नहीं जा सकता है।

### 16.3 सुमिटोमो इलैक्ट्रिक लिमिटेड, जापान

16.3.1 कुछ ग्रेडों को बाहर किए जाने के संबंध में किए गए अनुरोधों के बारे में, यह अनुरोध किया गया था कि जैसाकि स्वीकार्य तौर पर घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान जी654 का उत्पादन नहीं किया है, उसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना है।

16.3.2 घरेलू उद्योग के अलग-अलग न किए गए विश्लेषण के पहलू पर अर्जेन्टाइन फुटवियर ने अपीलीय निकाय की रिपोर्ट पर निर्भरता के संबंध में, यह अनुरोध किया गया था कि अपीलीय निकाय का निर्णय उस तथ्य के आधार पर था कि उक्त मामले में विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा को चुनौती नहीं दी गई थी। हालांकि, चूंकि वर्तमान मामले में, निर्यातक ने विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा पर प्रश्न उठाया है अतः अपीलीय निकाय का तर्क वर्तमान मामले में लागू नहीं है।

16.3.3 इसके अलावा, घरेलू उद्योग के इस दावे के उत्तर में कि इसने भारत में मांग न होने के कारण इस ग्रेड का निर्माण नहीं किया है, उन्होंने भारत के मुख्य भू-भाग में चेन्नई और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बीच एक ऑप्टिकल सब मरीन केवल सिस्टम का डिजायन बनाने, उसकी इंजीनियरिंग करने, आपूर्ति करने, संस्थापित करने, परीक्षण करने और कार्यान्वित करने के लिए एनईसी टेक्नोलॉजी इंडिया प्रा. लि. (“एनईसीटीआई”) के साथ बीएसएनएल द्वारा किए गए संविदा का साक्ष्य प्रस्तुत किया है।

16.3.4 इसके अलावा यह अनुरोध किया गया था कि घरेलू उद्योग द्वारा जांच की अवधि की बाद की अवधि में आयातों में अस्थाई गिरावट के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध तथ्यात्मक रूप से सही नहीं हैं क्योंकि टेलीकॉम ऑपरेटरों पर 2019-20 की दूसरी तिमाही के पहले भी बहुत अधिक दबाव रहा है। इसके अलावा, लंबे मानसून संबंधी रिपोर्ट जिसका घरेलू उद्योग द्वारा संदर्भ लिया गया है, केवल पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में है जो विचाराधीन उत्पाद के भारतीय बाजार का बहुत कम मात्रा होती है।

16.3.5 घरेलू उद्योग “अप्रत्याशित घटनाक्रमों” जिसके फलस्वरूप आयातों में वृद्धि हुई है, को दर्शाने में असफल रहा है। सीआरयू रिपोर्ट पर विश्वास करना विशेष रूप से चीन में मांग में गिरावट के संबंध में यह सिद्ध करता है कि आयातों में वृद्धि केवल चीन और न कि अन्य देशों से हुई है।

16.3.6 शुल्कों को लगाया जाना जनहित में नहीं होगा क्योंकि यह प्रयोक्ता अर्थात केवल निर्माण उद्योग पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव डालेगा।

17. उसके पश्चात, महानिदेशक में परिवर्तन के कारण, वर्तमान महानिदेशक ने दिनांक 17.07.2020 को एक दूसरी आम सुनवाई आयोजित की जिसमें घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अपने मौखिक अनुरोध किए। तदनंतर, सीमा प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आंकलन) नियमावली 1997 के नियम 6 के उप-नियम (6) के संबंध में, सभी इच्छुक पक्षकारों जिन्होंने आम सुनवाई में भाग लिया था, से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से प्रस्तुत किए गए विचारों को लिखित अनुरोध के रूप में प्रस्तुत करें। घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा

किए गए अनुरोधों का एक सार यहां नीचे फिर से प्रस्तुत किया गया है। चूंकि पहली सुनवाई के दौरान किए गए अधिकांश अनुरोधों को ठीक से दोहराया गया है अतः संक्षिप्तता के वास्ते, उसे यहां नीचे फिर से प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। दूसरी सुनवाई के बाद किए गए अतिरिक्त अनुरोधों का एक सार नीचे दिए गए अनुसार है:

### 17.1 घरेलू उद्योग – एसटीएल – बीएफएल

17.1.1 घरेलू उद्योग ने बढ़े हुए आयातों, गंभीर क्षति, गंभीर क्षति के खतरे, अप्रत्याशित घटनाक्रमों, जनहित के संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ अपने पूर्व के अनुरोधों को दोहराया है।

17.1.2 इसके अलावा, यह अनुरोध किया गया था कि घरेलू उत्पादन के संबंध में आयातों में 2018-19 तथा सबसे हाल की अवधि अर्थात जनवरी, 2019 से जून, 2019 के दौरान भी बहुत अधिक हड़ तक वृद्धि हुई है।

17.1.3 इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया कि घरेलू उद्योग के उत्पादन के प्रतिशत के रूप में आयातों में जांच की अवधि की बाद की अवधि में भी वृद्धि हुई है। यह अनुरोध किया गया था कि दूसरी तिमाही, 2019 में उत्पादन की तुलना में आयात 2016-17 के स्तर का 186 प्रतिशत और 2017-18 के स्तर का 163 प्रतिशत था।

17.1.4 इसके अलावा, 2019-20(अप्रैल-दिसंबर, 2019) में घरेलू उद्योग के उत्पादन की तुलना में आयातों का बहुत अधिक होना जारी रहा है और 2018-19 में तीव्र वृद्धि 2019-20 में गिरावट के द्वारा समाप्त कर दिया गया है जो नीचे ग्राफ से स्पष्ट है:

**घरेलू उद्योग के उत्पादन के % के रूप में आयात**

(अनुक्रमित)



17.1.5 इसके अलावा यह अनुरोध किया गया है कि रक्षोपाय नियमावली का नियम 2(ग) या तो स्वतंत्र रूप में अथवा घरेलू उद्योग के उत्पादन की तुलना में आयातों में वृद्धि को शामिल करने के लिए “बढ़ी हुई मात्रा” को परिभाषित करता है। इस संबंध में, उन्होंने व्यूबों, पाईप और होलो प्रोफाइल्स, सीमलेस ऑफ आयरन, अलाय अथवा नॉन-अलाय स्टील के आयातों के संबंध में जांचों में जारी किए गए दिनांक 11.03.2014 के अंतिम जांच परिणामों का संदर्भ लिया है जिसमें नीचे दिए गए अनुसार यह माना गया था:

#### “26 बढ़ा हुआ आयात :

सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख रक्षोपाय शुल्क बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार की शक्तियों का विवेचन करता है और नीचे दिए गए अनुसार प्रावधान करता है:

“(1) यदि केन्द्र सरकार इस प्रकार की जांच जिसे यह उपयुक्त मानता हो करने के बाद इस बात से संतुष्ट हो कि किसी वस्तु का आयात भारत में इस प्रकार की बढ़ी हुई मात्राओं में और ऐसी परिस्थितियों में किया जाता हो

ताकि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होती हो अथवा होने का खतरा उत्पन्न होता हो तब यह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा उस वस्तु पर रक्षोपाय शुल्क लगा सकता है”

इसके अलावा, सीमा प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आंकलन) का नियम 2 “बढ़ी हुई मात्रा” को नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित करता है:

“बढ़ी हुई मात्रा” में चाहे तो स्वतंत्र रूप में अथवा घरेलू उत्पादन की तुलना में आयातों में वृद्धि शामिल है”

उपर्युक्त से, यह देखा गया है कि कानून अर्थात् धारा 8ब और यह नियमावली रक्षोपाय शुल्क के उपयोग के लिए एक मौलिक पूर्व शर्त के रूप में आयातों में वृद्धि को अनिवार्य बनाता है। इस प्रकार से यह निर्धारित करने के लिए कि क्या विचाराधीन उत्पाद के आयातों में रक्षोपाय शुल्क लागू करने के उद्देश्य से “ऐसी मात्राओं में वृद्धि” हुई है, यह नियमावली स्वतंत्र रूप में अथवा घरेलू उत्पादन की तुलना में आयातों में वृद्धि का विश्लेषण अपेक्षित है। यह भी देखा गया है कि “बढ़ी हुई मात्रा” अभिव्यक्ति को समाहित रूप में परिभाषित किया गया है और इस परिभाषा में दो मानदंड अर्थात् स्वतंत्र रूप में आयातों में वृद्धि और घरेलू उत्पादन की तुलना में आयातों में वृद्धि शामिल है। यह भी देखा गया है कि ये दोनों मानदंड को एक साथ रहने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ी हुई मात्रा को या तो स्वतंत्र रूप में अथवा घरेलू उत्पादन की तुलना में मापा जाना है। एक मानदंड की संतुष्टि अथवा उसका होना कानूनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

17.1.6 घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि किसी भी स्थिति में, अर्जेन्टीना – फुटवियर, अपीलीय निकाय के निर्णय के संबंध में आयातों में अस्थाई गिरावट को ‘बढ़े हुए आयात’ का निर्धारण करते समय विचार किए जाने से बाहर रखा जाना है। जांच की अवधि की बाद की अवधि में आयात घरेलू मांग में अस्थाई गिरावट के कारण कम हो गई है और यह टेलीकॉम उद्योग की नाजुक स्थिति, कुछ भारत नेट परियोजनाओं में विलंब, दूसरी तिमाही 2019-20 में अप्रत्याशित वर्षा के कारण हुई है। हालांकि वर्तमान बाजार की प्रवृत्तियां यह संकेत देती हैं कि निकट भविष्य में मांग के बढ़ने की संभावना है।

17.1.7 घरेलू उद्योग ने अपनी समायोजन योजना भी प्रस्तुत की है जिसमें उनका उद्देश्य आयातों के प्रति अधिक प्रतिस्पर्धी होने के लिए कार्यान्वित करने का है। उन्होंने अनुरोध किया है कि यद्यपि उनके द्वारा पूरी की जा रही विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से, उनका अनुमान है कि उत्पादन की लागत में कच्चे माल से उन्नत उपज के कारण कमी आएगी और आयात किए गए कच्चे माल पर उनकी निर्भरता कम हो जाएगी।

17.1.8 इंडोनेशिया से आयातों में जांच की अवधि की बाद की अवधि के दौरान बहुत हद तक वृद्धि हुई है अर्थात् यह 2019-20 की दूसरी तिमाही में कुल आयातों का 7 प्रतिशत है। इसके अलावा उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि कुछ प्रमुख चीन की एसएमओएफ मन्युफैक्चरिंग कंपनियों जैसे कि जेडटीई और वाईओएफसी ने इंडोनेशिया में अपनी एसएमओएफ ड्रा संयंत्र स्थापित किया है और वे इंडोनेशिया के माध्यम से भारत को अपना निर्यात अब कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अनुरोध किया है कि 2019-20 की दूसरी तिमाही से, चीन से आयातों पर 15 प्रतिशत शुल्क लगता है जबकि इंडोनेशिया से आयातों पर आशियान एफटीए के कारण शून्य बीसीडी लगता है।

## 17.2 जापान, इंडोनेशिया, ब्राजील, रूसी संघ और ताईवान की सरकार

17.2.1 उपर्युक्त सरकारों ने अपने दूतावासों के माध्यम से अपने पूर्व के अनुरोधों को फिर से दोहराया है जिसे पहले ही ऊपर में दिया जा चुका है।

## 17.3 संयुक्त अरब अमीरात की सरकार

17.3.1 यूएई की सरकार ने अनुरोध किया है कि इसे वर्तमान जांच के उद्देश्य से “विकासशील देश” के रूप में माना जा सकता है। तदनुसार, यूएई से निर्यातों का भारत में कुल आयातों का 3 प्रतिशत से कम होने के कारण यूएई को किसी रक्षोपाय शुल्क जिसे लगाया जा सकता है, के क्षेत्र से बाहर किया जाए।

## 17.4 सुमिटोमो इलैक्ट्रिक इंडस्ट्रीज लि., जापान

17.4.1 एसईआई लि. ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग को क्षति, यदि कोई हो, कीमत की क्षति के साथ चीन जन.गण से आयातों की अधिक मात्रा के कारण ही हुई है। इस कारण से, इस प्रकार की क्षति को दूर करने के लिए उपयुक्त मंच रक्खोपाय जांच के विरुद्ध एक पाटनरोधी जांच के माध्यम से होता है जो सभी देशों से आयातों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और वर्तमान जांच समाप्त करने किए जाने के लायक है।

17.4.2 घरेलू उद्योग द्वारा अपनी याचिका में “अप्रत्याशित परिस्थितियाँ” होने के रूप में दिया गया कोई भी कारण का समाधान विशेष रूप से संबद्ध जांच में विचाराधीन उत्पाद के आयात के प्रति नहीं किया गया है। बल्कि, घरेलू उद्योग ने “आप्टिक फाइबर” की व्यापक श्रेणी में अचानक वृद्धि का आरोप लगाया है। यह अनुरोध किया गया है कि समग्र “आप्टिक फाइबर उद्योग” के वृहद श्रेणी में कुछ अप्रत्याशित घटनाक्रमों का आरोप लगाना मात्र अप्रत्याशित घटनाक्रमों और भारत में विचाराधीन उत्पादों के आयातों में अचानक वृद्धि के बीच एक कारणात्मक संबंध को दर्शाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

17.4.3 रक्खोपाय शुल्क लगाए जाने को अनिवार्य बनाने के लिए एक सकारात्मक जांच परिणाम के वास्ते इस प्रकार की बढ़ी हुई मात्रा में आयातों को होना चाहिए। रक्खोपाय जांच में आयातों की मात्रा में इस प्रकार की वृद्धि गंभीर क्षति के होने अथवा होने के खतरे के लिए हालिया, अचानक, तीव्र और पर्याप्त होनी चाहिए। विचाराधीन उत्पाद के लिए डीजीसीआईएंडएस के आयात संबंधी आंकड़े वही नहीं होने चाहिए और बल्कि यह सिद्ध करता हो कि जांच की पूरी अवधि के दौरान और ऐंड टू ऐंड विश्लेषण पर भी विचाराधीन उत्पाद के आयात की कोई बढ़ी हुई प्रवृत्ति नहीं है, आयात की मात्राओं में बहुत अधिक हद तक गिरावट आई है।

17.4.4 घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए तिमाही-वार आंकड़ों के अनुसार, 2019-20 की पहली तिमाही के लिए विचाराधीन उत्पाद के गैर-घरेलू उद्योग आयातों की आयात संबंधी मात्रा 1678 केएफकेएम के रूप में बताई गई है। हालांकि, प्रतिवादी द्वारा प्राप्त किए गए डीजीसीआईएंडएस के आयात संबंधी आंकड़ों के अनुसार, विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातों की आयात संबंधी मात्रा जिसमें घरेलू उद्योग का आयात शामिल है 1527 केएफकेएम है। इस प्रकार से, ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग वर्तमान जांच में माननीय महानिदेशक को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है।

17.4.5 वित्तीय वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही में आयातों में बहुत अधिक हद तक गिरावट आई है। विचाराधीन उत्पाद के आयातों में 2019-20 की पहली तिमाही में 1527 केएफकेएम से केवल 2019-20 की तीसरी तिमाही में 373 केएफकेएम तक गिरावट आई है जो 1254 केएफकेएम का बहुत बड़ा अंतर है।

17.4.6 इसके अलावा, यदि आयात की मात्राओं का विश्लेषण ऐंड टू ऐंड आधार पर किया जाना होता तब यह पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि आयातों में 2017-18 की पहली तिमाही में 769 केएफकेएम से 2019-20 की तीसरी तिमाही में 273 केएफकेएम तक गिरावट आई है और इस प्रकार से इसमें 496 केएफकेएम का अंतर है।

17.4.7 आर्थिक और कार्य-निष्पादन संबंधी मानदंडों का समग्र विश्लेषण यह दर्शाता है कि माननीय महानिदेशक द्वारा की गई जांच और इसके कार्य-निष्पादन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े न तो समुचित हैं और न ही पर्याप्त हैं; और इसके अलावा वे गलत आंकड़ों पर आधारित हैं। इस प्रकार से, घरेलू उद्योग के दावे और घरेलू उद्योग को हो रही गंभीर क्षति के प्रारंभिक जांच परिणामों के संबंध में उपलब्ध कराए गए आंकड़े और विचार किए गए आंकड़े विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू बाजार की स्थिति की सही तस्वीर नहीं प्रस्तुत करते हैं।

17.4.8 इसके अलावा, घरेलू उद्योग के आर्थिक और कार्य-निष्पादन संबंधी मानदंडों के संबंध में प्रतिवादी को उपलब्ध सीमित आंकड़ों को देखते हुए, इन मानदंडों ने पर्याप्त सुधार दर्शाया है। इस प्रकार से मानदंडों के विश्लेषण पर निर्भर रहते हुए क्षति के किसी दावे को माननीय महानिदेशक द्वारा कृपया अस्वीकार कर दिया जाए।

17.4.9 अर्थक्षम समायोजन योजना का मौजूद रहना भारतीय रक्षोपाय कानूनों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आवेदकों ने उसका एक सार्थक अगोपनीय पाठ भी उपलब्ध कराए बिना संपूर्ण समायोजन योजना पर अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। उन्होंने गोपनीयता के लिए अपने दावे के संबंध में कोई सही कारण उपलब्ध नहीं कराया है।

17.4.10 उन्होंने वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से उत्पाद ग्रेड जी.654 को बाहर रखे जाने के लिए अनुरोध किया है क्योंकि उसका निर्माण न तो घरेलू उद्योग द्वारा किया गया है और न ही इसके पास वैसा करने की क्षमता है।

17.4.11 इसके अलावा, उन्होंने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से उत्पाद ग्रेड्स जी.652.डी, जी.655 और जी.657.ए1 को बाहर रखे जाने का अनुरोध किया है क्योंकि भौतिक गुणों, उपभोक्ता की पसंद, गुणवत्ता आदि तथा एसईआई द्वारा निर्यात किए गए पीयूसी और घरेलू उद्योग द्वारा निर्माण किए गए उत्पाद के बीच भौतिक गुणों, उभोक्ता की पसंद, गुणवत्ता आदि के संबंध में बहुत अंतर है।

17.4.12 इसके अलावा उन्होंने यह अनुरोध किया है कि चूंकि अग्रिम अधिकरण योजना के अंतर्गत आयात घरेलू उत्पादों से प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं क्योंकि वे निर्यात बाजार की ओर निर्देशित हैं और उनके कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं होती है अतः उन्हें वर्तमान जांच में आयात संबंधी विश्लेषण से अग्रिम अधिकरण योजना के अंतर्गत किए गए सभी आयातों से बाहर रखा जा सकता है।

17.4.13 इसके अलावा, घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद के बढ़े हुए आयातों और घरेलू उद्योग द्वारा उसके कारण हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंधी स्थापित करने में असफल रहा है।

17.4.14 घरेलू उद्योग ने जनहित में होने के कारण रक्षोपाय शुल्क के संबंध में कोई तर्क करने में असफल रहा है और इस कारण से वह समाप्त किए जाने के लायक है।

## 17.5 एचएफसीएल लि.

17.5.1 आयातक ने यह अनुरोध किया है कि भारत की मांग मुख्य रूप से जी652 फाइबर की है। अन्य विशिष्ट सिंगल मोड आप्टिकल फाइबर अर्थात डिस्पर्सन शिफ्ट फाइबर (जी 653), कट-ऑफ शिफ्टड फाइबर (जी.654), नॉन जीरो डिस्पर्सन शिफ्टड फाइबर (जी.655 और जी.656) और बैंड इन्स्ट्रोस्ट्रिक्ट एसएमओएफ (जी657 ए1 और ए2), का भारत में मामूली घरेलू बाजार है जो उनके नगण्य आयातों और घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री से स्पष्ट है। अतः, इस प्रकार के विशिष्ट ग्रेड को वर्तमान जांच के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।

17.5.2 घरेलू उद्योग ने समायोजन योजना का अगोपनीय पाठ प्रस्तुत नहीं किया है। अतः हितबद्ध पक्षकार अपनी समायोजन योजना की व्यवहार्यता पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं।

17.5.3 चालू महामारी के दौरान, आयातों में गिरावट के कारण, घरेलू उद्योग घरेलू मांग को पूरा कर पाने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि आगे ऐसा कोई संरक्षण आवश्यक नहीं है।

## 17.6 फाइबर होम इंडिया प्रा. लि.

17.6.1 उन्होंने बढ़े हुए आयातों, गंभीर क्षति, समायोजन योजना, अप्रत्याशित घटनाक्रमों और जनहित के न रहने के संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ अपने पूर्व के अनुरोधों को दोहराया है। उन्होंने अनुरोध किया है कि आयातों में कमी और घरेलू उद्योग को क्षति, यदि कोई हो प्राथमिक रूप से अपने स्वयं के आयातों के कारण हुई है और इस कारण से यह खुद प्रभावित हुआ है। अतः यह अनुरोध किया गया है कि रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के लिए आवश्यकताओं को वर्तमान मामले में पूरा नहीं किया गया है।

## 18. दिनांक 17.07.2020 को आयोजित दूसरी आम सुनवाई के बाद प्रस्तुत किया गया प्रति उत्तर संबंधी अनुरोध

घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रति उत्तर संबंधी अनुरोधों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों का भी सार नीचे दिए गए अनुसार है। चूंकि कुछ अनुरोधों को दोहराया गया है अतः दूसरे प्रति उत्तर में किए गए नए/अतिरिक्त अनुरोधों का सार नीचे दिया गया है:

## 18.1 घरेलू उद्योग – एसटीएल – बीएफएल

18.1.1 घरेलू उद्योग ने अग्रिम लाइसेंस आदि के अंतर्गत गभीर क्षति, आयात, चीन से वस्तुओं से पाटन के कारण बढ़े हुए आयातों, क्षति के संबंध में अपने अनुरोधों को दोहराया है।

18.1.2 इसके अलावा, उन्होंने अपने लिखित अनुरोधों में एसईआई लि. के इस आरोप से इंकार किया है कि घरेलू उद्योग ने दूसरी आम सुनवाई के दौरान यह स्वीकार किया है कि जी.654 ग्रेड का आयात जांच की अवधि के दौरान किया गया था। उनके द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि भारत में ग्रेड जी 654 का कोई आयात नहीं किया गया था। तथापि, यह केवल निर्यातक के मौखिक अनुरोध के उत्तर में था कि उत्तर ग्रेड का आयात भारत में किया गया था, यह कि उन्होंने बिना किसी पूर्वाग्रह के यह अनुरोध किया है कि यदि इस प्रकार का आयात था भी तो यह किसी वाणिज्यिक/उल्लेखनीय मात्रा नहीं रहा होगा। वे अपने स्पष्ट दृष्टिकोण को बनाए रखते हैं कि उत्तर ग्रेड का आयात भारत में जांच की अवधि के दौरान नहीं किया गया है।

18.1.3 एनईसी टेक्नोलॉजी इंडिया प्रा. लि. (“एनईसीटीआई”) के साथ बीएसएनएल के बीच एसईआई द्वारा संविदा के संबंध में किए गए संदर्भ के बारे में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उत्तर संविदा आप्टिकल फाइबर केबल के लिए और न कि पीयूसी के लिए है क्योंकि इस प्रकार का रक्षोपाय शुल्क केवल उन आयातों पर लागू नहीं होगा जिनका आयात उत्तर संविदा के अंतर्गत किया गया है। पूर्वाग्रह के बिना उन्होंने आगे अनुरोध किया है कि इन केबलों में खपत की गई फाइबर की मात्रा बहुत कम अर्थात् लगभग 18 केएफकेएम है, अतः उत्तर आयातों को भारत में जी 654 ग्रेड के वाणिज्यिक आयातों के रूप में नहीं माना जा सकता है।

18.1.4 उन्होंने आगे यह अनुरोध किया है कि उनके द्वारा किए जा रही अनुसंधान परियोजना की मालिकाना प्रवृत्ति को देखते हुए, समायोजन योजना को गोपनीय रखा गया है।

18.1.5 उन्होंने अनुरोध किया है कि “आयातों में वृद्धि” के संबंध में निर्यातकों द्वारा किया गया अनुरोध तथ्यात्मक रूप से कानूनी आधार पर सही नहीं है। ये आयात स्वतंत्र रूप में तथा घरेलू उत्पादन की तुलना में बढ़े हुए स्तरों पर जारी रहे हैं। एसईआई लिमि. के इस अनुरोध के संबंध में कि यूस-स्टील रक्षोपाय में अपीलीय निकाय ने यह माना है कि “आयातों में अचानक वृद्धि के परीक्षण को आयात की मात्रा में स्पष्ट और बिना बाधा के ऊपर की ओर की प्रवृत्ति को दर्शाना ही चाहिए” कानून का सही अभ्यावेदन नहीं है बल्कि तथ्यों को जान बूझकर तोड़ा मरोड़ा गया है क्योंकि निर्यातक द्वारा दिए गए उत्तर वाक्य उत्तर रिपोर्ट में कहीं भी मौजूद नहीं है।

## 18.2 इंडोनेशिया की सरकार

18.2.1 इंडोनेशिया की सरकार ने इस दावे से इंकार किया है कि जांच की अवधि की बाद की अवधि में इंडोनेशिया से आयातों में वृद्धि हुई है। यह अनुरोध किया गया है कि 2019 के पूरे वर्ष में इंडोनेशिया से आयात विश्व से भारत के कुल आयात में से केवल 0.14 प्रतिशत रहा है। इसके अलावा उन्होंने अनुरोध किया है कि याचिकाकर्ता ने गलत तरीके से यह अनुरोध किया है कि जुलाई, 2019- जून, 2020 की अवधि के दौरान इंडोनेशिया से आयात का हिस्सा 11 प्रतिशत था। यह अनुरोध किया गया है कि 2019 और 2020 के संपूर्ण वर्ष को मिलाकर इंडोनेशिया से एसएमओएफ का भारत के आयात की मात्रा 0.2 प्रतिशत की सीमा तक हुआ है।

18.2.2 उन्होंने आगे यह भी अनुरोध किया है कि आवेदकों का यह अनुरोध कि भारत में चीन का निवेश इंडोनेशिया के माध्यम से चीन से भारत में निर्यात के रास्ते से करने में सक्षम होगा, बहुत बढ़ाचढ़ा कर प्रस्तुत किया गया। इस कारण से इंडोनेशिया में एसएमओएफ के कारखानों के निवेश को देखा जाना चाहिए क्योंकि इंडोनेशिया में एक बहुत बड़ी मांग है जो एसएमओएफ कारखानों के निवेश को इस देश में होने को सक्षम बनाता है।

### 18.3 सुमिटोमो इलैक्ट्रिक इंडस्ट्रीज लि., जापान

18.3.1 एसईआई लि. ने अन्य बातों के साथ-साथ बढ़े हुए आयातों, गंभीर धनि, कारणात्मक संबंध, अप्रत्याशित घटनाक्रम, जनहित और समायोजन योजना के न होने के संबंध में अपने अनुरोधों को फिर से दोहराया है। यह अनुरोध किया गया है कि बढ़े हुए आयातों और गंभीर धनि के किसी साक्ष्य के न होने की स्थिति में, रक्षोपाय शुल्क लगाया जाना आवश्यक नहीं है।

18.3.2 विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से कुछ ग्रेडों को बाहर किए जाने के संबंध में इसने यह अनुरोध किया है कि एसईआई द्वारा यथा-निर्मित उच्च ग्रेडों का या तो घरेलू उद्योग द्वारा निर्माण नहीं किया जाता है अथवा घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पादों के समान अथवा घरेलू स्तर पर प्रतिस्पर्धी नहीं है। यहां यह भी उल्लेख करना संगत है कि एसएमओएफ के प्रत्येक ग्रेड का अलग-अलग अंतिम उपयोग है और वे प्रतिस्थापनीय अथवा एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाने लायक नहीं हैं। इस कारण से ऐसे ग्रेडों को वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर किया जाना अपेक्षित है।

18.3.3 घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में एसएमओएस का जी.654 ग्रेड का निर्माण अथवा उसकी विक्री नहीं की है, इस कारण से इसे वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, यह अनुरोध किया है कि ग्रेड जी.652, जी.655 और जी.657 को भी बाहर किया जाना चाहिए क्योंकि एसईआई द्वारा निर्माण किए गए और बेचे गए ये ग्रेड उन ग्रेडों से अलग होते हैं जिनका निर्माण घरेलू उद्योग द्वारा किया जाता है और वह भौतिक विशेषताओं, उपभोक्ता की पसन्दगी, गुणवत्ता आदि में अंतर के कारण अलग है। इसके अलावा, चूंकि इन ग्रेडों में से प्रत्येक ग्रेड अलग-अलग होता है और उसे अन्य ग्रेडों के साथ प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है अतः इन ग्रेडों अर्थात् जी.652, जी.654, जी.655 और जी.657 जिसका निर्माण एसईआई द्वारा किया गया है, को पीयूसी के क्षेत्र के भीतर शामिल करने के लिए कोई आधार नहीं है।

18.3.4 घरेलू उद्योग का यह दावा कि इसके पास जी.654 फाइबर का निर्माण करने के लिए प्रौद्योगिकी है, की पुष्टि याचिका में दिए गए साक्ष्य द्वारा नहीं की गई है। घरेलू उद्योग द्वारा विश्वास किए गए 2012 न्यूज रिपोर्ट संयुक्त उद्यम बिरला फुर्साका फाइबर आप्टिक्स लि. की क्षमताओं को प्रमाणित नहीं करता है जो जी.654 फाइबर का निर्माण करने के लाए वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग के घटकों में से एक घटक है बल्कि वह फुर्साका इलैक्ट्रिक ग्रुप, जापान की क्षमताओं को प्रमाणित करता है।

18.3.5 घरेलू उद्योग का यह दावा कि भारत में जी.654 की कोई मांग नहीं है, सही नहीं है। यह नोट किया जाना चाहिए कि जी.654 का उपयोग सब-मरीन केबलों के निर्माण में किया जाता है। उपर्युक्त अनुरोध में जिस न्यूज आर्टिकल का संदर्भ लिया गया है, उसके अनुसार, बीएसएनएल में भारत के मुख्य विभाग चेन्नई और अंडमान तथा निकोबाल द्वीप समूह के बीच एक आप्टिकल सब मरीन केबल सिस्टम का डिजाइन बनाने, इंजीनियरिंग करने, आपूर्ति करने, संस्थापित करने, परीक्षण करने और कार्यान्वित करने के लिए एनईसीटीआई के साथ करार किया। इसके अलावा, चूंकि इस परियोजना को 2020 में पूरा किए जाने की आशा थी, इसका अर्थ यह है कि उसका आयात भारत में जांच की अवधि के दौरान किया गया था।

### 18.4 फाइबरहोम इंडिया प्रा. लि.

18.4.1 उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ बढ़े हुए आयातों, गंभीर धनि, अप्रत्याशित घटनाक्रमों, समायोजन योजना और जनहित के न होने के संबंध में अपने पूर्व के अनुरोधों को फिर से दोहराया है।

18.4.2 घरेलू उद्योग के चीन में गिरती हुई कीमतों के कारण गंभीर धनि के खतरे जिसे जुलाई, 2020 में चीन की मोबाइल के टेंडर से देखा जा सकता है जो लगभग 200 रु. प्रति एकेएम प्रबंध हुआ, के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे के बारे में यह अनुरोध किया गया था कि उक्त दावा बिना किसी आधार के किया गया है।

भारत में कीमत उक्त डील से प्रभावित नहीं होगी और भारतीय उद्योग उस समय में भी अच्छा कर रहा है जब चीन की कीमतें नीचे की ओर है।

18.4.3 ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग की चिंताएं मांग में गिरावट के कारण हैं क्योंकि इस प्रकार के रक्षोपाय शुल्क के लगाने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

#### **ग. महानिदेशक (रक्षोपाय) की जांच और जांच परिणाम**

19. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जांच की शुरुआत, प्रारंभिक जांच परिणाम और आम सुनवाई के उत्तर में किए गए अनुरोधों, विभिन्न प्राथमिक और गौण उपलब्ध रिकॉर्डों, किए गए घरेलू सत्यापन डीवीसी के माध्यम से किया गया था, और अपने अंतिम जांच परिणाम नीचे दिए गए अनुसार रिकॉर्ड किए हैं:

20. सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लगाने की विवेचना करता है। इसका उपभाग (1) किसी वस्तु पर केन्द्र सरकार द्वारा रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने का प्रावधान करता है यदि उस वस्तु का आयात भारत में इस प्रकार की बढ़ी हुई मात्राओं में और ऐसी परिस्थितियों में किया जा रहा हो जिसके कारण घरेलू उद्योग को गंभीर झंति होती हो अथवा उसका खतरा हो।

21. सीमा प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आंकलन) नियमावली, 1997 जांच को शासित करने वाले तरीके और सिद्धांतों का प्रावधान करता है।

22. यह जांच उक्त नियमावली के अनुसार की गई है और अंतिम जांच परिणाम को इस अधिसूचना के माध्यम से रिकॉर्ड किया गया है।

#### **क) विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)**

23. जांच की शुरुआत संबंधी नोटिस और प्रारंभिक जांच परिणाम में, विचाराधीन उत्पाद को “सिंगल मोड आप्टिकल फाइबर” (“एस एम ओ एफ”) के रूप में परिभाषित किया गया है। एस एम ओ एफ आप्टिकल फाइबर से संबंधित है, जो लाइट के एक सिंगल स्पेशियल मोड कैरियर के रूप में पारेषण सुविधाएं प्रदान करता है और यह कतिपय बैंड में सिंगल पारेषण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मानकीकृत सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर टाइप में नॉन-डिस्पर्सन शिफ्टेड फाइबर (जी 652), डिस्पर्सन शिफ्टेड फाइबर (जी 653), कट ऑफ शिफ्टेड सिंगल मोड आप्टिकल फाइबर (जी 654) तथा नॉन जीरो डिस्पर्सन शिफ्टेड फाइबर (जी 655 और 657) के साथ-साथ बैंड इंटेंसिव सिंगल मोड फाइबर (जी 657) शामिल हैं- जैसा कि इंटरनेशनल टेलिकम्युनिकेशन यूनियन (आईटीयू-टी), जो दूरसंचार प्रणालियों और विक्रेताओं के लिए एक वैश्विक मानक निकाय है, द्वारा परिभाषित किया गया है।

24. सिंगल मोड आप्टिकल फाइबर का उपयोग यूनि-ठ्यूब और मल्टी-ठ्यूब स्ट्रांडेड केबल, टाइट बफर केबल, आर्म्ड और अन आर्म्ड केबल, एडीएसएस और फिग-18 केबल, रिबन केबल, वेट कोर और ड्राई कोर केबल आदि सहित आप्टिकल फाइबर केबल के निर्माण के लिए होता है। सिंगल मोड आप्टिकल फाइबर मुख्यतः हाई-डाटा रेट, लंबी दूरी और नेटवर्क ट्रांसपोर्टेशन सुविधा के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए यह मुख्यतः लोंग हॉल, मेट्रो एरिया नेटवर्क, सी ए टी वी, आप्टिकल एक्सेस नेटवर्क (उदाहरण के लिए एफ टी टी एच) और यहां तक कि यथा लागू कम दूरी के नेटवर्क के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। मुख्य खपत ग्राम पंचायत, रक्षा (एनएफएस परियोजना) तथा डेटा सेन्टर की टेल्को की कनेक्टिविटी से 3जी/4जी/5जी द्वारा संचालित है।

25. संबंधित उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची के सीमा प्रशुल्क शीर्ष 9001 10 00 के तहत वर्गीकरण किए जाने योग्य है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

26. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने पीयूसी के क्षेत्र से एसएमओएफ की कुछ ग्रेडों/प्रकारों को बाहर किए जाने के लिए अनुरोध किया गया है, जिसे मान लिया गया है। किए गए अनुरोधों तथा आयात और घरेलू उद्योग के आंकड़ों के विश्लेषण से यह देखा गया है कि भारतीय मांग प्रमुख रूप से जी.652 ग्रेड का है। हालांकि अधिकांश अन्य ग्रेडों का भी

आयात भारत में किया गया है तथा उसकी बिक्री उसी अनुपात में घरेलू उद्योग द्वारा की गई थी। यह देखा गया है कि आयात किए गए उत्पादों का ग्रेड मिक्स वही है जो घरेलू उत्पादों का है। इसके अलावा, इन ग्रेडों को आंशिक रूप से एक दूसरे के स्थान पर आयात किया जा सकता है और उसका समान उपयोग है। अतः पीयूसी के क्षेत्र से किसी ऐसे ग्रेड को बाहर करने का कोई सही कारण नहीं है।

27. हितबद्ध पक्षकारों में से एक एसईआई लि., जापान ने दावा किया है कि एसईआई द्वारा निर्मित और बेची गई ग्रेड जी652, जी655 और जी657 घरेलू उद्योग द्वारा बनाए गए उत्पादों से भौतिक विशेषताओं, ग्राहक की पसंदगी, गुणवत्ता आदि में अंतर के कारण अलग-अलग है। इस संबंध में, यह नोट किया जाता है कि एसएमओएफ के ग्रेडों को इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियम (आईटीयू-टी) द्वारा परिभाषित किया गया है जिसे वैश्विक रूप से स्वीकार किया गया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि उनकी वस्तु न केवल घरेलू बाजार में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी एसईआई लिमिटेड द्वारा निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करती है। संबंधित निर्यातक के मामले में भी ऐसा नहीं है कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित ग्रेड आईटीयू-टी द्वारा दिए गए तकनीकी विनिर्देश के अनुरूप नहीं हैं अथवा यह कि इस प्रकार के विनिर्देश अस्पष्ट अथवा सही नहीं हैं। इस प्रकार से, एसईआई लिमिटेड के इस दावे की पुष्टि करने के लिए किसी विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में कि उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं पर उपभोक्ता की पसंदगी में कोई अंतर अथवा उसका कोई उदाहरण है, इन ग्रेडों को बाहर किए जाने के लिए उनके तक को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

28. इसके अलावा, एक अन्य हितबद्ध पक्षकार, एचएफसीएल लि. ने अनुरोध किया है कि भारत की मांग प्राथमिक रूप से नॉन डिस्पर्सन शिफ्टर फाइबर ग्रेड 652 का है। एसएमओएफ के अन्य ग्रेडों जैसे जी654, जी655 और जी657 के लिए भारतीय बाजार में नगण्य मांग है जो आवेदकों के आयात संबंधी आंकड़े तथा घरेलू बिक्री से स्पष्ट हैं। इस संबंध में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि 2018-19 में घरेलू उद्योग के कुल आयातों तथा घरेलू बिक्री का लगभग 97 प्रतिशत जी652 ग्रेड के फाइबर का था। एसएमओएफ के अन्य ग्रेड भारतीय मांग का लगभग केवल 3 प्रतिशत था। उनके द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि चूंकि आयात किए गए उत्पाद का ग्रेड मिक्स आवेदकों की घरेलू बिक्री के ग्रेड मिक्स के सदृश्य है अतः वर्तमान मामले में ग्रेडवार विश्लेषण किया जाना अपेक्षित नहीं है।

29. इसी संदर्भ में घरेलू उद्योग ने **अर्जेन्टीना - फुटवियर** में अपीलीय निकाय के निर्णय को प्रस्तुत किया है जिसमें यह माना गया था कि अलग-अलग आधार पर विश्लेषण रक्षोपाय शुल्क की जांच में किया जाना अपेक्षित नहीं है। अपीलीय निकाय की रिपोर्ट का संगत पैरा यहां नीचे प्रस्तुत किया गया है:

#### **“(क) उत्पाद खंड**

- 1.1 अपनी जांच में पांच उत्पाद समूहों में फुटवियर के अर्जेन्टीना के खंड में किए जाने के संबंध में (कार्य-निष्पादन स्पोटर्स फुटवियर, गैर निष्पादन स्पोटर्स फुटवियर, विशेष रूप से महिलाओं के लिए फुटवियर, टाउन और/अथवा कैजुअल फुटवियर और अन्य) (पैरा 8.1112) यूरोपीय समुदाय यह तर्क देते हैं कि इस खंडित दृष्टिकोण को अपनाने के बाद अर्जेन्टीना को इसका पालन अपने क्षति के विश्लेषण के माध्यम से सतत रूप से और सभी खंडों में गंभीर क्षति को प्रमाणित करने के लिए करना था जिसमें रक्षोपाय शुल्क लगाया जाना था। यूरोपीय समुदाय यह दावा करते हैं कि “गंभीर क्षति” को किसी भी चयन किए गए पांच खंडों में नहीं किया गया था और यह कि अर्जेन्टीना में केवल एक अथवा अन्य क्षेत्र के आंकड़ों का उपयोग किया क्योंकि इसने अपने उद्देश्य के लिए उपयुक्त माना। यूरोपीय समुदाय विशेष रूप से यह तर्क देते हैं कि आयात की प्रवृत्तियों, बाजार हिस्से, लाभ और हानि और रोजगार से संबंधित कारकों की जांच प्रत्येक बाजार खंड के लिए नहीं की गई थी। हालांकि इसके साथ ही यूरोपीय समुदाय यह भी उल्लेख करता है कि यह समान अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी उत्पादों अर्थात् सभी फुटवियर की एकमात्र श्रेणी का अर्जेन्टीना की परिभाषा को चुनौती नहीं देता है।
- 1.2 अर्जेन्टीना का उत्तर यह है कि यूरोपीय समुदाय संपूर्ण फुटवियर उद्योग का सीएनसीई का क्षति विश्लेषण को भ्रमित कर रहा है जिसमें उत्पाद की वे श्रेणियां हैं जिनका सीएनसीई में संगत सूचना

प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रश्नावली में उपयोग किया है। अर्जेन्टीना के दृष्टिकोण से एक सिंगल “समान अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी” उत्पाद और एक सिंगल राष्ट्रीय उद्योग इस मामले में मुद्दा नहीं है क्योंकि एक सिंगल फुटवियर बाजार के सभी अलग-अलग खंडों के बीच आपूर्ति और मांग की ओर प्रतिस्थापन के लिए पर्याप्त लचीलापन है। इस कारण से, अर्जेन्टीना यह तर्क देता है कि समग्र रूप में फुटवियर उद्योग के संबंध में क्षति संबंधी विश्लेषण सीएनसीई ने किया। परिणामस्वरूप उत्पाद श्रेणियों के संबंध में सभी अलग-अलग क्षति कारकों पर अलग-अलग रूप में विचार किए जाने की आवश्यकता नहीं थी।

- 1.3 हम यूरोपीय समुदाय से सहमत नहीं हैं कि अर्जेन्टीना को अलग-अलग आधार पर अपनी क्षति और कार्य संबंध विश्लेषण करना अपेक्षित है। हमारे दृष्टिकोण से क्योंकि इस मामले में समान अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी उत्पाद की परिभाषा को चुनौती नहीं दी गई है अतः यह परिभाषा है जो अनुच्छेद 4.1(ग) के अभिप्राय से “घरेलू उद्योग” की परिभाषा को नियन्त्रित करता है तथा उस तरीके से जिसमें इन आंकड़ों का विश्लेषण किसी जांच में अवश्य किया जाना चाहिए। जबकि अर्जेन्टीना को अलग-अलग आधार पर विचार किया जा सकता था (और वास्तव में कुछ मामलों में वैसा किया गया) हमारे दृष्टिकोण से, वैसा किया जाना अपेक्षित नहीं था। इसके बजाय, समान अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी उत्पाद की निर्विवाद परिभाषा को देखते हुए, अर्जेन्टीना से यह अपेक्षित था कि वह सभी फुटवियर के संबंध में प्रत्येक क्षतिकारक पर विचार करे। [1] उसी संकेत के द्वारा यूरोपीय समुदाय का समान उत्पाद परिभाषा के अर्जेन्टीना के परिभाषा को स्वीकार करने के बाद अलग-अलग आधार पर विश्लेषण पर टिके रहने की कोई आवश्यकता नहीं है जिसमें क्षति और कार्य-संबंध को प्रत्येक अलग-अलग उत्पाद खंड के संबंध में प्रमाणित किया जाना चाहिए। [2] इस प्रकार से, क्षति के परिणाम की हमारी समीक्षा में, हम इसकी समग्रता में फुटवियर उद्योग से संबंधित विश्लेषण और निष्कर्षों पर विचार करेंगे। (बल दिया गया)

30. प्राधिकारी ने दिनांक 23 सितंबर, 2019 की जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना के पैरा 2 में यथा-परिभाषित विभिन्न ग्रेडों के पीयूसी को परिभाषित किया है। उपर्युक्त विधि-शास्त्र से, स्पष्ट है कि रक्षोपाय जांच में, इस तरह के उत्पाद का विश्लेषण किया जाना है और न कि उत्पाद खंडों का विश्लेषण किया जाना है। इसके अलावा, ग्रेडवार विश्लेषण तब अतिरिक्त हो जाता है जब आयात किए गए उत्पादों का उत्पाद बास्केट उन उत्पादों के समान है जिसकी बिक्री घरेलू उद्योग द्वारा की गई थी। घरेलू उद्योग के आयात आंकड़ों तथा घरेलू बिक्री का विश्लेषण यह दर्शाता है कि दोनों मामलों में उत्पादों का ग्रेड मिश्रण समान है। इस प्रकार से आयातों और गंभीर क्षति के मानदंडों का प्रत्येक ग्रेड के लिए पृथक रूप से विश्लेषण करने का कोई औचित्य नहीं है। इस कारण से मैं इसे उपर्युक्त मानता हूँ कि नॉन-डिस्पर्सन शिफ्टड फाइबर (जी.652) जैसे जी655, जी657 आदि को छोड़कर ग्रेडों को बाहर किए जाने के संबंध में कुछ हितबद्ध पक्षकारों के तर्क पर विचार करूँ।

31. इस आधार ग्रेड जी654 को बाहर किए जाने के लिए की गई स्वीकार्योंकि के संबंध में कि इस निर्माण घरेलू उद्योग द्वारा क्षति की अवधि के दौरान नहीं किया गया है, यह नोट किया जाता है कि उक्त ग्रेड का निर्माण न तो घरेलू उद्योग द्वारा क्षति की अवधि के दौरान किया गया है और न ही उसका भारत में आयात किया गया है। घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए रिकॉर्ड पर साक्ष्य रखा है कि इसके पास भारत में उक्त ग्रेड का निर्माण करने की क्षमता है। उनका अनुरोध यह है कि चूंकि भारत में उक्त ग्रेड की कोई मांग नहीं है अतः न तो उसका आयात और न ही उसकी बिक्री घरेलू उद्योग द्वारा की गई है।

32. रिकॉर्ड पर उपलब्ध आंकड़ों से, यह देखा गया है कि जांच की अवधि के दौरान भारत में ग्रेड जी654 का आयात नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने प्रत्यक्ष संबंधी अनुरोधों में बीएसएनएल और एनईसी टेक्नोलॉजिज इंडिया प्रा. लि. (“एनईसीटीआई”) के बीच एसईआई लि. द्वारा संविदा के बारे में लिया गया संदर्भ प्रथम दृश्या “आप्टिकल फाइबर केबल्स” के लिए न कि “एसएमओएफ” के लिए संविदा है। इस संबंध में घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उक्त संविदा आप्टिकल फाइबर केबल के लिए और न कि पीयूसी के लिए है अतः रक्षोपाय शुल्क

उक्त संविदा के अंतर्गत किए गए आयातों पर लागू नहीं होगा। उन्होंने आगे यह अनुरोध किया है कि इन केबलों में खपत की गई फाइबर की मात्रा बहुत कम अथवा लगभग 18 केएफकेएम है। घरेलू उद्योग के अनुरोधों को स्वीकार करना आवश्यक है क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा निर्माण किए जा रहे “समान उत्पाद” की उपलब्धता नहीं होने के आधार पर उक्त भेद को बाहर रखने का समर्थन नहीं किया जा सकता है जब भारत में ऐसी श्रेणी के लिए कोई मांग नहीं है। इस महानिदेशालय की यह स्थापित कार्य-पद्धति है कि केवल ऐसे ग्रेडों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर किया जाए जिसका आयात भारत में किया गया है लेकिन जिसके लिए घरेलू उद्योग द्वारा “समान उत्पाद” का कोई निर्माण नहीं किया जा रहा है। हालांकि, इस प्रकार से बाहर करना न्यायोचित हो सकता है जब जांच की अवधि के दौरान भारत में इस प्रकार की श्रेणी का आयात नहीं किया गया हो क्योंकि इसकी आपूर्ति करने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता को स्थापित नहीं किया जा सकता है। चीन जन.गण और इजरायल के लोकतांत्रिक गणराज्य के मूल के अथवा वहां निर्यात किए गए सिन्क्रोनेस डिजिटल हरारकी ट्रांसमिशन इक्यूपमेंट (एसडीएच इक्यूपमेंट) के आयात के संबंध में पाठनरोधी शुल्क जांच में जारी किए गए दिनांक 12.01.2012 के अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से उत्पाद के किसी विशेष प्रकार को बाहर करने से इंकार किया था क्योंकि उसका निर्यात संगत अवधि के दौरान भारत को नहीं किया गया था। संगत पैरा को फिर से प्रस्तुत किया गया है:

**“ प्राधिकारी यह देखते हैं कि किसी विशेष प्रकार को बाहर किए जाने के लिए दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता है यदि उसका निर्यात भारत को संगत अवधि के दौरान नहीं किया गया हो क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु की आपूर्ति न करने के तथ्य को तब तक स्थापित नहीं किया जा सकता है जब तक इस प्रकार का निर्यात भारत को नहीं किया गया है और उसकी अनुमति भारत में उपयोग किए जाने के लिए नहीं दी गई हो। प्राधिकारी यह मानते हैं कि एसटीम-256 को बाहर करने को न्यायोचित ठहराने के लिए कोई आधार नहीं दिया गया है।”**

33. इस प्रकार से पीयूसी के क्षेत्र के संबंध में रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों तथा निर्धारित विधि-शास्त्र की जांच करने पर यह नोट किया गया है कि पीयूसी के ग्रेडों/प्रकारों को बाहर करने के संबंध में कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए दावे के अनुसार वर्तमान मामले में न्यायोचित नहीं हैं।

#### (ख) घरेलू उद्योग (डीआई)

34. सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 जिसे वित्त अधिनियम 2020 द्वारा संशोधित किया गया है की धारा 8 (ख) की उप धारा (11) के खंड (ख) में घरेलू उद्योग की परिभाषा नीचे दी गई है:

(ख) “घरेलू उद्योग” से तात्पर्य ऐसे उत्पादों से है जो –

- भारत में समूची समान वस्तु अथवा एक प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तु; अथवा
- जिसका भारत में समान वस्तु अथवा एक प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तु का साझा आउटपुट मिलाकर भारत में उस वस्तु के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा होता है।

आवेदकों ने यह दावा किया है कि उनका साझा उत्पादन भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा होता है और इस प्रकार से आवेदन विचाराधीन उत्पाद के कुल भारतीय उत्पादन के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। अतः आवेदकों को घरेलू उद्योग माना जा सकता है। घरेलू उद्योग को नीचे दी गई तालिका में दिए गए अनुसार माना जाना चाहिए।

| केएफकेएम                                     | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | जन. से जून 2019 | जन. से जून 2019<br>(वर्षिकीकृत) |
|--|---------|---------|---------|-----------------|---------------------------------|
| कुल भारतीय उत्पादन                           | ***     | ***     | ***     | ***             | ***                             |
| प्रवृत्ति                                    | 100     | 112     | 118     | 105             | 105                             |
| कुल उत्पादन में घरेलू उद्योग के उत्पादन का % | ***     | ***     | ***     | ***             | ***                             |

35. आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि उनके पास अन्य घरेलू निर्माताओं के उत्पादन संबंधी आंकड़े नहीं हैं। तथापि, एसपीएल को छोड़कर अन्य सभी घरेलू निर्माता आयातित पूर्व निर्मित उत्पाद से उत्पादन करते हैं (जिसे किसी अन्य ज्ञात प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता) तदनुसार, कुल उद्योग उत्पाद का अनुमान घरेलू उद्योग द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें मानक उद्योग मानदंड का पालन किया गया है कि 37 एफकेएम फाइबर 1 किग्रा. पूर्व निर्मित उत्पाद ~90% आफ्टर- ड्रॉ- यील्ड के साथ निर्मित किया जा सकता है। तदनुसार, आवेदकों ने कुल भारतीय उत्पादन की गणना करने के लिए आवेदकों द्वारा पूर्व निर्मित उत्पाद के आयातों को छोड़कर साइबेक्स एग्जिम सोल्यूसंस प्रा. लि. (“सी ई एस पी एल”, संक्षिप्तता के लिए) से प्राप्त पूर्व निर्मित आंकड़ों के साथ उपरोक्त परिवर्तन अनुपात को प्रयुक्त किया गया है।

36. तदोपरांत, महानिदेशक को मैसर्स फिनोलेक्स केबल लि. (“फिनोलेक्स”, संक्षिप्तता के लिए) से दिनांक 30.09.2019 का पत्र प्राप्त हुआ है, जो विचाराधीन उत्पाद का एक घरेलू उत्पादक भी है, जिसने जांच शुरू करने का समर्थन किया है और अनंतिम शुल्क लगाने के लिए अनुरोध किया है। उन्होंने वर्ष 2016-17 से 2018-19 और अप्रैल, 2019 से सितंबर, 2019 तक के उनके उत्पाद, क्षमता, बिक्री और वस्तुसूची की सूचना भी प्रस्तुत की है। इसके बाद एक अन्य घरेलू उत्पादक अर्थात कार्निंग टेक्नोलॉजिज इंडिया प्रा. लि. ने भी इस याचिका के समर्थन में दिनांक 5 नवंबर, 2019 का अपना पत्र प्रस्तुत किया था। इस प्रकार से 6 में 4 घरेलू उत्पादकों ने इस याचिका का समर्थन किया है।

37. इस तथ्य के साथ रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर कि कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने पीयूसी के कुल उत्पादन में अपने हिस्से अथवा घरेलू उद्योग के रूप में अपनी स्थिति के बारे में आवेदकों के दावे पर आपत्ति की है अथवा उसका खंडन करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है, मैं यह मानता हूँ कि इन आवेदकों का उत्पादन भारत में उक्त उत्पादों के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है और उसे सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ब्र की उपधारा (6) के खंड (ख) के संबंध में घरेलू उद्योग के रूप में माना गया है।

38. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह उल्लेख किया कि एसटीएल जो घरेलू उद्योग के घटकों में से एक है, अपने आप में पीयूसी का एक आयातक है अतः उसे घरेलू उद्योग के रूप में नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में, यह नोट किया जाता है कि पाठनरोधी से संबंधित कानूनों जिसमें विशेष रूप से घरेलू उद्योग के क्षेत्राधिकार से आयातकों को बाहर करने का प्रावधान है, के विपरीत, सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 अथवा उसके अंतर्गत बनाई गई रक्षोपाय नियमावली में इस प्रकार से बाहर किए जाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अतः, घरेलू उद्योग की स्थिति का निर्धारण करने के उद्देश्य से, यह कार्रवाई कि एसटीएल ने जांच की अवधि के दौरान पीयूसी का आयात किया है, संगत नहीं है।

#### (ग) जांच की अवधि (पीओआई)

39. सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और उक्त नियमावली तथा रक्षोपाय संबंधी करार और जीएटीटी के अनुच्छेद XIX में जांच की अवधि परिभाषित नहीं की गई है। तथापि, यह स्पष्ट है कि जांच की अवधि समुचित रूप से लंबी और पर्याप्त रूप से हाल की होनी चाहिए ताकि विभिन्न संगत कारकों, जैसे घरेलू बाजार की स्थिति, घरेलू उद्योग का निष्पादन आदि के आधार पर एक तर्कसंगत निष्कर्ष निकाला जा सके कि क्या निर्यातों में वृद्धि के कारण वास्तव में घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हो रही अथवा गंभीर क्षति होने का खतरा उत्पन्न हो रहा है अथवा नहीं और इसीलिए रक्षोपाय शुल्क लगाने की जरूरत को स्पष्ट किया जाए। इस आधार पर, वर्तमान मामले के तथ्यों में, इसे तर्कसंगत माना गया है और 2016-17 से 2018-19 एवं 2019-20 (जून, 2019 तक) के रूप में जांच की अवधि (पीओआई) का केवल निर्धारण करने के लिए, जांच की अवधि अर्थात जनवरी, 2019 से जून, 2019 में निहित बिल्कुल हाल की अवधि का विशेषण गंभीर क्षति की सीमा, गंभीर क्षति के खतरे और नाजुक परिस्थितियों के मौजूद रहने की जांच करने के लिए किया गया है।

40. इसके अलावा, प्रस्तुत किए गए आंकड़ों की प्रवृत्तियों, सबसे हाल की अवधि अर्थात् जनवरी-जून, 2019 के लिए वार्षिक आंकड़ों को बेहतर तरीके से समझने के लिए जांच की समग्र अवधि के लिए वास्तविक आंकड़ों के साथ विचार किया गया।

### (घ) सूचना का स्रोत

41. प्रारंभ में आवेदन में 2015-16 से 2018-19 और अप्रैल, 2019 से मई, 2019 तक की अवधि के आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे। तदोपरांत, इन्हें अद्यतन कर जून, 2019 तक के आंकड़े शामिल किए गए हैं।

42. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के लिए सौदा- वार आयात संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, जो कि वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस), वाणिज्य विभाग, भारत सरकार से 2016-17 से 2018-19 तक की अवधि के लिए प्राप्त किए गए थे। वर्ष 2019-20 की प्रथम तिमाही के लिए घरेलू उद्योग ने प्रारंभ में एक द्वितीय स्रोत से सौदा- वार आंकड़े प्रस्तुत किए थे। तथापि, बाद में प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस से 2019-20 की प्रथम तिमाही के आंकड़े प्राप्त किए हैं जिन पर विश्लेषण के लिए विचार किया गया है।

43. इसके बाद, जांच की प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग ने डीजीसीआईएंडएस से उनके द्वारा लिए गए 2019-20 की दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही के लिए आयात संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किए हैं और उसे महानिदेशक को उपलब्ध कराया गया है जिसे डीजीटीआर द्वारा भी वैध ठहराया गया है। डीजीटीआर ने आगे डीजी सिस्टम से 2019-20 की चौथी तिमाही के लिए आंकड़े प्राप्त किए हैं।

44. घरेलू उद्योग के संबंध में वर्ष 2016-17 से 2018-19 और 2019-20 (जून, 2019) की अवधि के लिए ही क्षति मापदंड से संबंधित इसी तरह के आंकड़े आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। जिस पर आयात और परिणामी गंभीर चोट विश्लेषण के लिए विचार किया गया है।

### (इ.) प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता

45. घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन में गोपनीय आधार पर कुछ सूचना प्रदान की है और यह अनुरोध किया है कि इसे गोपनीय माना जाए। घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन का एक अगोपनीय अंश भी प्रदान किया है, जो महानिदेशक (रक्षोपाय) जारी फाइल सं. डी- 22011/75/2009 के तहत जारी व्यापार नोटिस दिनांक 21.12.2019 के साथ पठित नियमावली के नियम 7 के तहत अपेक्षित है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने इस सूचना की गोपनीयता के अपने दावे को स्पष्ट करते हुए कारण प्रस्तुत किए हैं।

46. कथित नियमावली के नियम 7 के तहत आवेदक ऐसी सूचना को प्रकट न करने का चयन कर सकता है, जो कि गोपनीय प्रकृति की हो और तस्वीरधी अगोपनीय सारांश प्रदान किया गया हो। घरेलू उद्योग ने सूचना की गोपनीयता का दावा करने के कारणों का सारांश प्रस्तुत किया है और गोपनीय आधार पर दाखिल की गई सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत किया है। चूंकि ये कारण कथित नियमावली के नियम 7 की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, इसीलिए आवेदक द्वारा किए गए गोपनीयता के दावे को एतद्वारा प्रदान किया जाता है।

### 47. स्वतंत्र रूप में आयातों में वृद्धि

47.1.1 विचाराधीन उत्पाद का आयात भारत में चीन जन.गण., जापान, यूएसए और कोरिया गणराज्य सहित विभिन्न देशों से किया जा रहा है। विचाराधीन उत्पाद का अधिक मात्रा में आयात चीन जन.गण से हो रहा है। आवेदकों ने यह दावा किया है कि 2018-19 में आयातों में अचानक, तीव्र और बहुत अधिक वृद्धि हुई है जो सबसे हाल की अवधि, जनवरी, 2019 से जून, 2019 में भी उच्च स्तरों पर होना जारी रहा है। विचाराधीन उत्पाद की आयात की मात्रा में घरेलू उद्योग के आयातों को शामिल करते हुए 1903 केएफकेएम अर्थात् 2016-17 से घरेलू उद्योग के आयातों को शामिल करते हुए और घरेलू उद्योग के 7706 केएफकेएम आयातों को बाहर रखते हुए 9918 केएफकेएम तक वृद्धि हुई है।

47.1.2 चूंकि घरेलू उद्योग द्वारा आयातों को शामिल करना आयातों की वास्तविक मात्रा को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता है, इस कारण से आयातों में अचानक वृद्धि और गंभीर क्षति का विश्लेषण करने के लिए, घरेलू उद्योग द्वारा किए

गए आयातों को कुल आयातों से बाहर रखा गया है और नीचे दी गई तालिका के अनुसार केवल गैर-घरेलू उद्योग के आयातों पर विचार करते हुए जांच की गई है।

| केएफकेएम में            | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | जनवरी'19-<br>जून'19 | जनवरी'19- जून'19<br>(वार्षिकीकृत) |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------------------|-----------------------------------|
| आयात (कुल)              | 1903    | 2469    | 9918    | 4,268               | 8,536                             |
| प्रवृत्ति               | 100     | 130     | 521     | 449                 | 449                               |
| आयात (गैर-घरेलू उद्योग) | 1,903   | 2,469   | 7,066   | 3,267               | 6,534                             |
| प्रवृत्ति               | 100     | 130     | 371     | 343                 | 343                               |

47.1.3 आयातों (गैर घरेलू उद्योग) में 2016-17 में 1,903 केएफकेएम से 2018-19 में 7066 केएफकेएम तक वृद्धि हुई है और यह सबसे हाल की अवधि में बढ़े हुए स्तरों पर (वार्षिकीकृत आंकड़ा 3,267 केएफकेएम) जारी रहा है। आधार वर्ष 2016-17 की तुलना में 2018-19 में 271 प्रतिशत और जनवरी, 2019 से जून, 2019 में 243 प्रतिशत तक उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

47.1.4 पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 के प्रत्येक तिमाही और 2019-20 के तिमाही 1 में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जैसा कि नीचे बताया गया है। हालाँकि, यह वृद्धि 2018-19 के तिमाही 2 में बहुत अधिक थी। 2018-19 के क्यू 3 और क्यू 4 में कम आयात और 2019-20 के क्यू 1 को इस परिप्रेक्ष्य में सराहा जा सकता है। 2018-19 में आयात और हाल की अवधि स्पष्ट रूप से उच्च स्तर पर जारी रही है।

| (गैर-घरेलू उद्योग आयात) केएफकेएम | पहली तिमाही | दूसरी तिमाही | तीसरी तिमाही | चौथी तिमाही |
|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 2016-17                          | 420         | 353          | 598          | 531         |
| 2017-18                          | 769         | 545          | 540          | 615         |
| 2018-19                          | 1244        | 2797         | 1436         | 1589        |
| 2019-20                          | 1678        |              |              |             |

## 47.2 सापेक्ष रूप में बढ़ता हुआ आयात

47.2.1 घरेलू उत्पादन की तुलना में, विचाराधीन उत्पाद के आयात के संबंध में पाया गया है कि इसमें 2016-17 से 2018-19 के बीच तथा जनवरी-जून, 2019 के बीच सतत रूप से वृद्धि हुई है और यह पूर्व के वर्ष के स्तर तथा आधार वर्ष से तिगुना से अधिक हो गया है।

| केएफकेएम में            | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | जनवरी'19-<br>जून'19* | जनवरी'19-<br>जून'19<br>(वार्षिकीकृत) |
|-------------------------|---------|---------|---------|----------------------|--------------------------------------|
| आयात (गैर-घरेलू उद्योग) | 1,903   | 2,469   | 7,066   | 3,267                | 6,534                                |
| प्रवृत्ति               | 100     | 130     | 371     | 343                  | 343                                  |
| घरेलू उद्योग का उत्पादन | 25641   | 29290   | 30652   | 13253                | 26506                                |

| प्रवृत्ति  | 100 | 114 | 120 | 103 | 103 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| घरेलू उद्योग के उत्पादन की प्रतिशत प्रवृत्ति के रूप में आयात | 7%  | 8%  | 23% | 25% | 25% |
| प्रवृत्ति  | 100 | 114 | 329 | 286 | 286 |

#### 47.3 जांच की अवधि के बाद की अवधि में आयात

47.3.1 जांच अवधि की प्रासंगिकता पर कार्बन ब्लैक फाइनल दिनांक 1.7.1998 के मामले में DG-Safeguards ने पाया कि “उनके आवेदन में घरेलू उत्पादकों ने सितंबर, 1997 तक के आंकड़े प्रस्तुत किए थे और जाँच शुरू करने का निर्णय लिया गया था। इस डेटा के आधार पर। अब इस संदर्भ अवधि को बदलना उचित नहीं होगा क्योंकि विभिन्न इच्छुक पक्ष इस अवधि के दौरान उपलब्ध तथ्यों के संदर्भ में जांच का जवाब देते हैं।” हालांकि, बाद के निष्कर्षों में उदा कास्टिक सोडा फाइनल फाइंडिंग नंबर 22011/47-2009 दिनांक 09.04.2010, DG-Safeguards ने भी अर्जेंटीना फूटवियर में अपीलीय निकाय रिपोर्ट के साथ और मुख्य रूप से सार्वजनिक हित का मूल्यांकन करने के लिए सूचित POI से परे डेटा का विश्लेषण किया। आगे की, विधि-शास्त्र में पर्याप्त रूप से लंबी जांच अवधि के दौरान किए गए जाने वाले बढ़े हुए आयातों का विश्लेषण अपेक्षित है जिसे जांच की शुरुआत के समय परिभाषित किया जाता है। तुलनात्मक रूप से लंबी अवधि के दौरान आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है जिससे कि कोई अस्थाई अंतर अथवा मौसमी प्रभाव बराबर हो जाए। इस कारण से प्राधिकारी का यह सामान्य कार्य-पद्धति है कि वे कम-से-कम तीन वर्षों की संगत सूचना प्राप्त करें और उसकी जांच करें। एक अथवा दो तिमाही के आंकड़ों को अलग-अलग रूप में विचार करना ‘बढ़े हुए आयातों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण की अनुमति नहीं देगा। हालांकि चूंकि अनेक हितबद्ध पक्षकारों ने जांच की अवधि की बाद की अवधि में आयातों में गिरावट के संबंध में अनुरोध किया है अतः जुलाई-दिसंबर, 2019 अर्थात् 2019 की तिमाही दो और तिमाही तीन के लिए आयात संबंधी आंकड़ों पर भी विचार और उसकी जांच इसमें नीचे किया गया है।

47.3.2 जांच की अवधि के बाद के आयात डेटा से, यह देखा गया है कि 2019-20 की तिमाही 2 और तिमाही 3 में आयात पिछली तिमाही की तुलना में गिरावट आई है, यानी 2019-20 की Q1 नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

| वित्तीय वर्ष 2019-20   | पहली तिमाही | जांच की अवधि के बाद की अवधि की दूसरी तिमाही | जांच की अवधि के बाद की अवधि की तीसरी तिमाही | जांच की अवधि के बाद की अवधि की दूसरी और तीसरी तिमाही |
|--|-------------|---|---|--|
| आयात (गैर-घरेलू उद्योग) (केएफकेएम)                             | 1678        | 655   | 320   | 975  |
| आयात कीमत (सीआईएफ) रु./एफकेएम                                  | 328         | 306   | 313   | 308  |
| आयात (गैर-घरेलू उद्योग) का घरेलू उद्योग का उत्पादन (%) (Trend) | 100         | 48  | 22  | 33   |

47.3.3 दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही में आयातों के संबंध में यह दावा किया गया है कि वे 23.9.2019 को वर्तमान जांच की शुरुआत और दिनांक 6.11.2019 को प्रारंभिक जांच परिणाम के जारी हाने जिसमें अनंतिम रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश की गई है, के कारण घरेलू उद्योग द्वारा बहुत अधिक कम हुई है। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि 2019-20 की तीसरी तिमाही के दौरान, घरेलू बिक्री आयातों को प्रतिस्थापित करने

में सक्षम नहीं थी क्योंकि अनंतिम शुल्क उठाने के खतरे लेने के बचने के उद्देश्य से आयातकों ने घरेलू उद्योग से खरीद करना आरंभ कर दिया था। हालांकि यद्यपि घरेलू उद्योग कीविक्री में 2019-20 की तीसरी तिमाही में वृद्धि हुई अतः उनका खतरा आगे और अधिक बढ़ गया था क्योंकि इस प्रकार की विक्री उन कीमतों पर हुई थी जो आयात की कीमतों से तुलनीय हैं।

47.3.4 जांच की अवधि की बाद की अवधि के आयातों (2019-20 के तिमाही 2 और Q3 के डेटा) के विश्लेषण को दर्शाया गया है, और पिछले जांच की अवधि भी:

|   | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 (पहली और दूसरी तिमाही वार्षिकीकृत) | दूसरी तिमाही 2019-20 | दूसरी तीसरी तिमाही और |
|---|---------|---------|---------|--|----------------------|-----------------------|
| आयात (गैर-घरेलू उद्योग)                           | 1,903   | 2,469   | 7066    | 4666                                       | 655                  | 975                   |
| प्रवृत्ति   | 100     | 130     | 371     | 245  | -                    | -                     |
| घरेलू उद्योग का उत्पादन                           | ***     | ***     | ***     | ***  | ***                  | ***                   |
| प्रवृत्ति   | 100     | 114     | 120     | 89   | -                    | -                     |
| घरेलू उद्योग के उत्पादन की तुलना में आयात (Trend) | 100     | 114     | 328     | 285  | 185                  | 128                   |
| प्रवृत्ति   | 100     | 114     | 329     | 286  | -                    | -                     |

यह नोट किया जाता है कि यद्यपि 2019-20 की दूसरी और तीसरी तिमाही में आयातों में गिरावट हुई है, वे घरेलू उद्योग के उत्पादन की तुलना में 2016-17 और 2017-18 से तुलना किए जाने पर तुलनीय स्तर पर लगातार होते रहे हैं।

47.3.5 जैसा कि कुछ इच्छुक पार्टियों द्वारा उठाए गए विवाद के संबंध में है कि "बढ़े हुए आयात" की आवश्यकता वर्तमान मामले में पूरी नहीं हुई है, क्योंकि आयात में हाल के दिनों में गिरावट आई है, संदर्भ निम्न अभ्यास / न्यायशास्त्र के लिए तैयार है। विश्व व्यापार संगठन में पैनल के निर्णय का। इस संबंध में रक्षोपाय नियमावली के नियम 2(ग) की ओर ध्यान आकर्षिक किया जाता है जो "बढ़ी हुई मात्रा" को या तो स्वतंत्र रूप में या घरेलू उत्पादन की तुलना में आयातों में वृद्धि को शामिल करने के लिए परिभाषित करता है। ट्यूब्स, पाईप्स और होलो प्रोफाइल्स, सीमलेस ऑफ आयरल, अलाय अथवा नॉन-अलाय स्टील के आयातों के संबंध में रक्षोपायशुल्क संबंधी जांचों में जारीकिए गए दिनांक 11.03.2014 के अंतिम जांच परिणामों में यह माना गया था कि:

**"अभिव्यक्ति" बढ़ी हुई मात्रा" को सम्मालित रूप में परिभाषित किया गया है और यह परिभाषा दो मानदंडों अर्थात् स्वतंत्र रूप में आयातों की वृद्धि और घरेलू उत्पादन की तुलना में आयातों की वृद्धि को शामिल करता है। यह भी देखा गया है कि इन दोनों मानदंडों को एकसाथ होने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ी हुई मात्रा की माप या तो स्वतंत्र रूप में अथवा घरेलू उत्पादन की तुलना में किया जाना है। एक मानदंड की संतुष्टि/भौजूदगी कानूनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है"**

कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए इस तर्क के संबंध में कि “बढ़ा हुआ आयात” की आवश्यकता को वर्तमान मामले में पूरा नहीं किया गया है क्योंकि आयातों में सबसे अधिक हाल की अवधि में गिरावट आई है, विश्व व्यापार संगठन ने पैनल के निम्नलिखित निर्णय की ओर संदर्भ आकर्षित किया जाता है:

- यूस-लाइन पाइप, ने पैनल ने यह माना है कि “इस निर्धारण की कोई आवश्यकता नहीं है कि आयात वर्तमान में अभी भी बढ़ रहे हैं। बल्कि आयातों में बिल्कुल हाल की अवधि में “वृद्धि” हो सकती थी लेकिन जांच की अवधि के अंत तक अथवा निर्धारण के तत्काल पूर्व तक आवश्यक रूप से वृद्धि नहीं हो रही है”(इस पर बल दिया गया है)
- इसके अलावा, अर्जेन्टीना-फुटवियर रक्षोपाय में अपीलीय निकाय की रिपोर्ट द्वारा यथा वर्णित “आयातों में हाल की, अचानक, तीव्र और बहुत अधिक वृद्धि” की आवश्यकता की व्याख्या करते हुए पैनल यह निष्कर्ष पर पहुंचा था कि “हालिया” शब्द का आशय “बहुत पीछे नहीं: जो हाल में हुआ हो, प्रतीत हुआ हो, मौजूद होना शुरू हुआ और मौजूद हुआ” है। अन्य शब्दों में “हालिया” शब्द का अर्थ इस प्रकार का पश्चयगामी विश्लेषण से होता है। यह प्राधिकारी के निर्णय के तत्काल पूर्व की स्थितियों के विश्लेषण को सूचित नहीं करता है। न ही इसका यह अर्थ है कि यह विश्लेषण जांच की अवधि के अंत में अनन्य रूप से स्थितियों पर ध्यान केन्द्रित करे।
- यूस-स्टील रक्षोपाय, ने पैनल ने अपीलीय निकाय द्वारा सही ठहराए गए जांच परिणामों में इस पश्च का समाधान किया गया है कि इस प्रकार से हाल के आयातों में वृद्धि हुई होगी और यूस-लाइन पाइप में पैनल के दृष्टिकोण से नीचे दिए गए अनुसार सहमत हुआ:

“जैसाकि यूस-लाइन पाइप में पैनल द्वारा फैसला लिया गया कि रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 2.1 में उस उत्पाद के बारे में बताया गया है जिसका “इस प्रकार की बढ़ी हुई मात्राओं में आयात किया जा रहा है”。 इस प्रकार से निर्धारण के समय आयातों में वृद्धि होने की आवश्यकता नहीं है: जो आवश्यक है कि यदि उत्पाद (ऐसी) बढ़ी हुई मात्राओं में “आयात किया जाना” जारी हो तब आयातों में वृद्धि हुई है। इस कारण से पैनल यूस-लाइन पाइप पैनल के दृष्टिकोण से सहमत है कि इस तथ्य की आयातों में वृद्धि “हाल की” होनी चाहिए का अभिप्राय यह नहीं है कि इसे जांच करने वाले प्राधिकारी के निर्धारण के तत्काल पूर्व की अवधि तक और न ही जांच की अवधि के अंत तक जारी रहना चाहिए। जैसाकि यूएस-लाइन पाइप ने पैनल द्वारा बताया गया है, सबसे अधिक हाल के आंकड़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए लेकिन उसे जांच की अवधि के कम हाल के हिस्से के संबंध में आंकड़ों से अलग-अलग रूप में विचार नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, जैसाकि वर्तमान में जारी “किया जा रहा है” दर्शाया गया है एक उलझन यह है कि वर्तमान में आयात अपेक्षाकृत अधिक (अर्थात बढ़े हुए) स्तरों पर है।

चाहे अलग-अलग मामले में जांच की अवधि के अंत में आयातों में वृद्धि रक्षोपाय शुल्क संबंधी करार के अनुच्छेद 2.1 के अर्थ में बढ़े हुए आयातों की जांच परिणाम को रोकता है, इस कारण से चाहे आयातों में कमी होने के बावजूद पर निर्भर करेगा, इसके बावजूद पूर्व में वृद्धि के परिणामस्वरूप “(ऐसी) बढ़ी हुई मात्राओं में आयात किया जाना (अभी भी) उत्पाद का होना है”。 इस मूल्यांकन में उन कारकों पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए जो जांच की संगत अवधि के अंत में कमी की मात्रा और प्रकृति उदाहरण के लिए पहले से ही हुई वृद्धि की तीव्रता और सीमा है(इस पर जोर दिया गया है)

यह भी ध्यान दिया जाता है कि POI के अंतिम वर्ष में आयात में मामूली गिरावट के बावजूद पिछले रक्षोपाय मामलों में (चूब, पाइप और खोखले प्रोफाइल, लोहा, मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु इस्पात, मिथाइल ऐसीटैसेटेट और सोडा ऐश)। रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश की गई थी।

47.3.6 उपर्युक्त के अलावा, एक अन्य संगत पहलू जिसकी जांच इस प्रकार के मामले में की भी जानी चाहिए, यह है कि क्या आयातों में गिरावट अस्थाई घटना है अथवा मांग के पैटर्न में दीर्घ अवधि परिवर्तन को दर्शाता है (संदर्भ : अर्जेंटीना-फुटवियर में अपीलीय निकाय की रिपोर्ट) घरेलू उद्योग ने अर्जेंटीना में पैनल शासन का उल्लेख किया है - जूते (ईसी), साथ ही डोमिनिकन गणराज्य में- ठ्यूबलर कपड़े और पॉलीप्रोपाइलीन बैग पर सुरक्षा उपाय, जहां जांच की अवधि के अंतिम वर्ष में आयात में गिरावट पर विचार करते हुए, पैनल बढ़े हुए आयात की खोज को बनाए रखते हुए, यह माना जाता है कि किसी भी अस्थायी गिरावट को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, जब तक कि प्रतिस्पर्धी पार्टियां यह दिखाने के लिए सबूत जोड़ने में सक्षम न हों कि ऐसी गिरावट अस्थायी नहीं है। प्रासंगिक पैरा नीचे निकाला गया है:

“7.233 पैनल शिकायतकर्ताओं के तर्क पर विचार नहीं करता है। पैनल इस संभावना को बाहर नहीं करता है कि कुछ उत्पादों की मांग स्थिर रह सकती है और इसलिए आयात में समग्र गिरावट से अप्रभावित है। हालांकि, शिकायतकर्ताओं ने कोई भी तर्क नहीं दिया है और न ही कोई सबूत सामने रखा है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि यह मामला उत्पादों के संबंध में था। हालांकि डीईआई ने स्पष्ट रूप से यह नहीं दिखाया कि अवधि के अंत में आयात में कमी अस्थायी थी, शिकायतकर्ताओं ने इसके विपरीत कोई सबूत पेश नहीं किया है। विशेष रूप से, शिकायतकर्ताओं ने यह प्रदर्शित नहीं किया है कि आयात में कमी (या आयात में समग्र कमी) एक स्थायी या दीर्घकालिक परिवर्तन को दर्शाती है।”

47.3.7. इस संदर्भ में, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि 2019-20 की दूसरी तिमाही में आयातों में गिरावट अन्य बातों के साथ-साथ बाजार की मांग में अस्थाई गिरावट के कारण हुई थी जिसका कारण निम्नलिखित था; भारतीय दूरसंचार उद्योग की संकटग्रस्त स्थिति, लम्बा मानसून और अनेक स्थानों पर बाढ़ा, नई भारत नेट परियोजनाओं को आरंभ करने में विलंब, आयातकों द्वारा भंडार इकट्ठाकरना; और रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने की मांग करते हुए वर्तमान याचिका दायर करना।

47.3.8 चूंकि एसएमओएफ आज की दुनिया में दूरसंचार नेटवर्क और डिजिटल अवसंरचना के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि भारत में एसएमओएफ की मांग निकट भविष्य में संभवतः बढ़ेगी अर्थात् नई भारतनेट परियोजनाओं की घोषणा की जा रही है इस कारण से मांग में वृद्धि के लिए बहुत अधिक संभावना उपलब्ध कराते हुए भारत में बहुत कम एफटीटीएच की पहुंच (चीन में 78 प्रतिशत की तुलना में 0.7 प्रतिशत), रिलायंस जियो द्वारा हाल में किया गया निवेश, अन्य के साथ-साथ वोडाफोन आईडिया ने गूगल द्वारा संभावित रूप से स्टेक खरीदने के साथ-साथ एयरटेल में अमेजोन के संभावित निवेश के बारे में चर्चा के कारण मांग में वृद्धि होने की संभावना है। इस प्रकार से निकट भविष्य में भारतीय मांग में वृद्धि होने की संभावना है।

47.3.9. दूरसंचार क्षेत्र की स्थिति और मानसून के फलस्वरूप मांग में गिरावट आई और तदनुसार, आयातों एवं घरेलू बिक्री पर प्रभाव पड़ा। इस कारण से, उत्पादन की तुलना में आयातों की जांच 2019-20 की दूसरी और तीसरी तिमाही के लिए किया गया है जिसका उल्लेख ऊपर में किया गया है।

47.3.10. उपर्युक्त विधि-शास्त्र और आयात संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि यद्यपि 2019-20 की दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही अर्थात् जांच की अवधि की बाद की अवधि में आयातों में गिरावट हुई है, घरेलू उद्योग के उत्पादन की तुलना में आयातों में उन स्तरों जो 2016-17 और 2017-18 में मौजूद थी, पर होना जारी रहा है। इस प्रकार से, जांच की बाद की अवधि में मांग और इसके फलस्वरूप आयातों में गिरावट एक अस्थाई घटना हो सकती है और इस प्रकार की गिरावट जिसकी पुष्टि एक लंबे समय तक चलने वाली घटना के रूप में नहीं हो सकती है और इसके आगे यह आयातों में पूर्व में हुई वृद्धि को समाप्त नहीं कर सकता है।

#### 48. अप्रत्याशित घटनाक्रम

- 48.1 जबकि सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख और न ही उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली महानिदेशक (रक्षोपाय) पर अप्रत्याशित घटनाक्रमों के फलस्वरूप बढ़े हुए आयात हुए हैं, पर कोई जिम्मेदारी डालता है, गैट के अनुच्छेद XIX के साथ पठित रक्षोपाय संबंधी करार राष्ट्रीय प्राधिकारियों को “अप्रत्याशित घटनाक्रम” इसके फलस्वरूप आयातों में वृद्धि और घरेलू उद्योग को परिणामी गंभीर क्षति हुई है, की जांच करने की जिम्मेदारी डालता है।
- 48.2 उपर्युक्त आवश्यकता को देखते हुए महानिदेशक सतत रूप से अपनी जांचों में “अप्रत्याशित घटनाक्रमों” के मुद्दे की जांच करते रहे हैं। इस कारण से, वर्तमान मामले में भी अप्रत्याशित घटनाक्रमों जिसके फलस्वरूप जांच की अवधि के दौरान पीयूसी के आयातों में तीव्र वृद्धि हुई है, की जांच करने के लिए उपर्युक्त माना जाता है।
- 48.3 अर्जेन्टीना-फुटवियर (ईसी)<sup>1</sup> मामले में विश्व व्यापार संगठन का अपीलीय निकाय ने यह माना कि इस प्रकार से बढ़ी हुई मात्राओं में और ऐसी स्थितियों में जिसके कारण घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति होती हो अथवा होने का खतरा हो, आयात “अप्रत्याशित” होना चाहिए था। इस मामले में यह भी माना गया था कि बढ़े हुए आयातों का घटनाक्रम “अप्रत्याशित घटनाक्रमों” के कारण होना चाहिए था। संगत पैरा अपीलीय निकाय की जांच परिणामों का आधार बनता है जिसे नीचे दिया गया है:
- “91. अनुच्छेद XIX:1 के उप पैरा (क) में नियम “अप्रत्याशित घटनाक्रमों के परिणाम और प्रशुल्क रियायतों सहित इस करार के अंतर्गत सदस्य द्वारा उठाए गए भार के परिणाम के आशय का निर्धारण करने के लिए, हमे इन शब्दों की उनके संदर्भ में उनके सामान्य अर्थ में तथा अनुच्छेद XIX के उद्देश्य को देखते हुए जांच करनी चाहिए। हमें सबसे पहले इन शब्दों के सामान्य अर्थ को देखना चाहिए। “अप्रत्याशित घटनाक्रमों” के आशय के संबंध में, हम नोट करते हैं कि “अप्रत्याशित” की शब्दकोश की परिभाषा, विशेष रूप से जब इसका संबंध “घटनाक्रम” शब्द से हो, “अप्रत्याशित” के अनुरूप है। दूसरी ओर “अप्रत्याशित की परिभाषा शब्दकोशों में “पूर्व में बताए जाने योग्य नहीं” अथवा “अनुमान न लगाए जाने, पूर्व में नहीं बताए जाने अथवा प्रत्याशा नहीं किए जाने” के आशय के रूप में दी गई है। इस प्रकार से हमें ऐसा लगता है कि “अप्रत्याशित घटनाक्रम के परिणाम के रूप में” वाक्यांश के सामान्य अर्थ में उन घटनाक्रमों को शामिल किया जाना है अपेक्षित जिसके फलस्वरूप इस प्रकार की बढ़ी हुई मात्राओं में और ऐसी स्थितियों में जिसके कारण घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति होती हो अथवा होने का खतरा हो, हुई है “अप्रत्याशित” होनी चाहिए थी। “प्रशुल्क रियायतों सहित इस करार के अंतर्गत किसी सदस्य द्वारा उठाए गए भार के प्रभाव को” वाक्यांश के संबंध में हम यह विश्वास करते हैं कि इस वाक्यांश का सामान्य तौर पर यह अर्थ है कि इसे अवश्य दर्शाया जाना चाहिए, वास्तव में यह कि प्रशुल्क रियायतों सहित गैर 1994 के अंतर्गत आयात करने वाले सदस्य ने भार उठाया है। यहां हम नोट करते हैं कि जीएटीटी 1994 से अनुबंधित अनुसूचियों को गैट 1994 के अनुच्छेद II के पैरा 7 के अनुसरण में इस करार के भाग I का अभिन्न हिस्सा बनाया गया है। इस कारण से सदस्य की अनुसूची में कोई रियायत अथवा प्रतिबद्धता गैट 1994 के अनुच्छेद II में निहित दायित्वों के अध्यधीन है।” (इस पर जोर दिया गया है)
- 48.4 इस प्रकार से, अनुच्छेद XIX में आयातक सदस्य जिसने गैट के अंतर्गत भार उठाया है, से यह अपेक्षित है कि वे उन घटनाक्रमों की जांच करें जिसे इसने “पूर्व में देखा” अथवा “जिसकी आशा” नहीं की थी जब इसने उस दायित्व को उठाया था जिसके फलस्वरूप आयातों में वृद्धि हुई।

<sup>1</sup>अपीलीय निकाय की रिपोर्ट, अर्जेन्टीना-फुटवियर (ईसी), पैरा 90

48.5 उसी प्रकार से, कोरिया-डेयरी<sup>2</sup> में विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय में यह माना गया थाकि अप्रत्याशित घटनाक्रम वे घटनाक्रम हैं जिन्हें पूर्व में देखा नहीं अथवा जिनकी आशा नहीं की गई है जब सदस्य ने उस भार को उठाया था। इस मामले में, यह भी माना गया था कि अप्रत्याशित घटनाक्रम वे परिस्थितियां हैं जिसे वास्तव में दर्शाया ही जाना चाहिए। एक अन्य मामले में यूस-स्टील रक्षोपाय<sup>3</sup> के संबंध में पैनल इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि अनेक घटनाक्रमों का मेल अप्रत्याशित घटनाक्रम का आधार बनने के लिए एक साथ हो सकते हैं। संदर्भ की सुविधा के लिए संगत पैरा यहां नीचे फिर से दिया गया है।

“10.99 अनुच्छेद XIX अनेक घटनाक्रमों के मेल को “अप्रत्याशित घटनाक्रमों” के रूप में विचार किए जाने से नहीं रोकता है। तदनुसार पैनल का यह विश्वास है कि घटनाक्रमों का मेल गैर 1994 के अनुच्छेद XIX के उद्देश्यों से “अप्रत्याशित घटनाक्रमों” का आधार बन सकता है। इस कारण से पैनल का यह मत है कि यह प्रत्येक सदस्य को दर्शाना होगा कि परिस्थितियों का मेल जिसे यह मानता हो, उस समय अप्रत्याशित थी जब इसने अपने प्रशुल्क समझौतों के फलस्वरूप गंभीर क्षति उत्पन्न करने वाले आयातों की बढ़ी हुई मात्रा हुई थी, के निष्कर्ष पर पहुंचा।”

48.6 पैनल के उपर्युक्त तर्क पर माननीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 16-7-2018 के सोलर सेल के संबंध में रक्षोपाय जांचों में जारी किए गए अंतिम जांच-परिणामों में विश्वास किया गया है।

48.7 वर्तमान जांच में, आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि 2018-19 और जांच की अवधि में आयातों में अचानक वृद्धि वैश्विक बाजार में अनेक अप्रत्याशित घटनाक्रमों जैसे फाइबर उद्योग में वैश्विक स्तर पर बहुत अधिक क्षमता, फाइबर के अधिकांश निर्माता देशों के विरुद्ध चीन द्वारा व्यापार शुल्क लगाया जाना/उसका विस्तार करना, यूएसए, आस्ट्रेलिया जैसे देशों द्वारा चीन से दूरसंचार उपकरण/संघटकों के आयात पर लगाया गया नीतिगत प्रतिबंध और चीन निर्मित फाइबर के विरुद्ध प्रमुख दूरसंचार आपरेटरों द्वारा (विशेषकर पश्चिमी यूरोप और यूएसए में दूरसंचार ऑपरेटरों) द्वारा लगाया गया अन्य गैर-रोजकोषीय/गैर विनियामक प्रतिबंधों के मेल का नतीजा था जिसके फलस्वरूप भारत में अचानक आयातों का विपठन हुआ है। इन में से कुछ घटनाक्रमों की चर्चा विस्तार से इसमें नीचे किया गया है:

#### 48.7.1 वैश्विक स्तर पर अत्यधिक क्षमता 2018-19 में वैश्विक मांग से बहुत अधिक हो गई।

क. आवेदकों द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि इस बात का अनुमान लगाना कि एसएमओएफ के लिए वैश्विक मांग योजनाबद्ध 5जी के आरंभ किए जाने, एफटीटीएच की तैनाती, डिजिटलीकरण में बढ़े हुए निवेश आदि के कारण प्राथमिक रूप से बहुत तेजी से बढ़ने जा रही है, अधिकांश एसएमओएफ तथा प्रीफोर्म निर्माताओं ने अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में अत्यधिक निवेश किए थे। इसके परिणामस्वरूप, 2018-19 और 2019-20 में वैश्विक एसएमओएफ निर्माण क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई अर्थात् इसमें 2016-17 की तुलना में लगभग 220 मिलियन एफकेएम तक वृद्धि हुई। इस वृद्धि की भायावहता इस तथ्य से और अधिक स्पष्ट है कि भारत में कुल मांगजो एसएमओएफ का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, 2018-19 में केवल 35 मिलियन एफकेएम था।

ख. इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त के अलावा, एफटीटीएच तैनाती और डिजिटाइजेशन परियोजनाओं में अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि के साथ 5जी को आरंभ करने की योजनाओं में अप्रत्याशित विलंब के कारण, वैश्विक मांग में वैश्विक क्षमता में वृद्धि के समानुपात में वृद्धि नहीं हुई और उसका कारण से बहुत अधिक मात्रा में क्षमताएं निष्क्रिय रह गई। वास्तव में, 2018-19 के लिए आंकड़ों का विश्लेषण यह

<sup>2</sup>अपीलीय निकाय की रिपोर्ट, कोरिया-डेयरी, पैरा 85 और 89

<sup>3</sup>यूएस-स्टील रक्षोपाय, पैरा 315

[[https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/248\\_259\\_abr\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/248_259_abr_e.pdf)]

दर्शाता है कि विश्व की 753 मिलियन एफकेएम की संचयी एसएमओएफ ड्रा क्षमता के विरुद्ध, 2018-19 में वैश्विक मांग केवल 554 मिलियन एफकेएम था।

- ग. इस प्रकार से, कम हुई मांग के साथ 2018-19 में सृजित अत्यधिक क्षमता में एसएमओएफ निर्माताओं को अपना अत्यधिक उत्पादन खपाने के लिए नए मार्गों की तलाश करने हेतु एसएमओएफ निर्माताओं को मजबूर कर दिया। इसके साथ ही रिलायंस जियो द्वारा एफटीटीएच सेवाओं को आरंभ करने की घोषणा के साथ भारत में व्यापक डिजिटाइजेशन पर ध्यान देते हुए भारत सरकार द्वारा नई डिजिटल संचार नीति 2018 की घोषणा के कारण भारत में मांग की बहुत अधिक संभावना उत्पन्न हो गई जिसके कारण यह 2018-19 के दौरान एक बहुत आकर्षक निर्यात लक्ष्य बन गया।
- घ. उपर्युक्त के अलावा, 2018-19 में विशेष रूप से चीन में जो एसएमओएफ का सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक है, में आशा से कम वृद्धि के कारण चीन के तथा अन्य निर्माताओं द्वारा सामना की जा रही अत्यधिक क्षमता और अधिक सुस्पष्ट हो गई। जनवरी-जून, 2018 के दौरान चीन में एसएमओएफ के लिए आशा से कम मांग के फलस्वरूप न केवल चीन में बल्कि अन्य अधिकार क्षेत्रों में भी मांग-सूची में वृद्धि हुई जिसने उन्हें बढ़ते हुए बाजारों जैसे भारत को निर्यात करने के लिए विवरण कर दिया। घरेलू उद्योग ने उस अवधि के दौरान जब आयातों में अचानक वृद्धि हुई थी, वैश्विक एसएमओएफ उद्योग की बदलती हुई गतिशीलता पर कब्जा करने के लिए विभिन्न सीआरयू-रिपोर्ट से अंशों का संदर्भ लिया है जिसे यहां नीचे फिर से प्रस्तुत किया जाता है:

#### **सीआरयू -सितंबर, 2018 रिपोर्ट-**

“परिणामस्वरूप हम फाइबर उद्योग को 2017 में प्रिफोर्म क्षमता में गिरावट से परिवर्तित होकर 2018 में प्रिफोर्म क्षमता की अधिकता में जाते हुए देखते हैं। यह परिवर्तन और अधिक स्पष्ट हो गया है जैसे ही 2018 का समय बीता है। अन्य शब्दों में, इस वर्ष के बाद के महीनों में और अधिक क्षमता रही है। इसका कारण यह है कि अनेक प्रमुख आपूर्तिकर्ता वर्ष के बीतने के साथ और अधिक नई प्रिफोर्म क्षमता लाते रहे हैं।”

#### **सीआरयू -नवंबर, 2018 रिपोर्ट-**

“चीन के बाजार बराबर हो जाती है।

2018 की पहली छमाही में विश्व आपूर्तिकल केवल संस्थापना 245 मिलियन फाइबर-किलो मीटर तक पहुंच गई। यह आंकड़ा कुछ सीमा से उस सीमा जिसकी सूचना हमने इस रिपोर्ट के अंतिम अंक में पहली छमाही 2018 के लिए दी थी (सितंबर 2018 ओएफसी मानिटर) से 20 मिलियन फाइबर किलोमीटर कम है। नीचे की ओर संशोधन चीन में आशा से कमजोर आदेशों के बारे में नई सूचना दर्शाती है।

..... कुछ बाजारों, जैसे चीन ने अत्यधिक क्षमता निर्यात बाजारों में अधिक आक्रामक होने के लिए कुछ फाइबर निर्माताओं पर दबाव भी डाल रहा है”

- इसके अलावा, चीन की टेलीकॉम क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी, चाइना मोबाइल (सीएम) द्वारा जनवरी-जून, 2018 के दौरान घोषणा से कम खरीद के कारण वैश्विक मंदी शुरू हो गई। इस मंदी का प्रभाव अधिकांश एसएमओएफ का उत्पादन करने वाले देशों में स्पष्ट है जिसें अनेक देश मालसूची के स्तर के समुचित होने की सूचना दे रहे हैं। **सीआरयू-नवंबर, 2018 रिपोर्ट** का संबंधित पैरा नीचे दिए गए अनुसार है:

अन्य शब्दों में, एक ग्राहक, जिसका विश्व के 2017 आपूर्तिकल केवल खपत का 28 प्रतिशत था ने 2018 में उतना केवल नहीं खरीदा जितना इसने अपने निविदा दस्तावेजों में दर्शाया था। इस प्रकार से, सीएम (चाइना मोबाइल) पृष्ठ एक पर सारांश में सूचित किए गए बाजार मंदी का प्रमुख अंशदान करने वाला था।

निविदा दस्तावेज जिसे सीएम ने 2017 की चौथी तिमाही में जारी किया, में यह कहा गया था कि 2018 की पहली छमाही में मानक (लूजट्ट्यूब, जी.6523.डी) केबल के लिए इसकी मांग 110 मिलियन फाइबर-केएम होगी। छह महीने के दौरान, यह मात्रा प्रति माह औसत 18.3 मिलियन फाइबर-केएम होगी। लेकिन हाल की रिपोर्ट यह दर्शाती है कि सीएम ने 2017 के अंत में केबल की नगण्य से अधिक मालसूची जमा कर ली थी और इस मात्रा के फलस्वरूप 2018 के आरंभिक महीनों में आशा से कम ऑर्डर प्राप्त हुए। जैसे-जैसे वर्ष बीतता गया, सीएम के ऑर्डरों में 2017 के ऑर्डरों की तुलना में कोई वृद्धि नहीं हुई। हाल की टिप्पणियां यह संकेत देती हैं कि तीन तिमाहियों के माध्यम से सीएम का मानक केबल ऑर्डर मुश्किल से 110 मिलियन फाइबर-केएम पहुंच गया था।“

“इसके अलावा, चीनी कंपनियों ने यह कहा है कि मालसूची संचित होना जारी रहा है, जिसमें कीमतों पर नीचे की ओर दबाव बनाने में योगदान किया। चीन के पास उत्पादन और खपत दोनों मामले में विश्व के आप्टिकल केबल का आधा से अधिक है। चीन के निर्माताओं ने भी अंतर्राष्ट्रीय बिक्रीबढ़ा दी है जिसके फलस्वरूप चीन फाइबर और केबल का एक बड़ा निर्यातक हो गया है। इस प्रकार चीन के घरेलू बाजार घटनाक्रमों जैसे अपेक्षाकृत अधिक माल सूची भी अन्य देशों और क्षेत्रों में कीमतों और बिक्री को प्रभावित कर रही है।

उदाहरण के लिए, हम यह नोट करते हैं कि जापान में आप्टिकल केबल की माल सूची जैसा कि जापान के आर्थिक, व्यापार और उद्योग मंत्रालय (एमईटीआई) से मासिक आंकड़ों में दर्शाया गया है, में इस वर्ष वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, सितंबर, 2018 में जापान की मालसूची सितंबर, 2017 की तुलना में 71 प्रतिशत अधिक थी”

च. इस प्रकार से, उपर्युक्त चर्चाओं से यह स्पष्ट है कि विभिन्न कारकों जैसे विलंबित 5जी रॉल आउट, एफटीटीएच की तैनाती में अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि और डिजिटाइजेशन परियोजनाओं में धीमी वृद्धि के साथ-साथ चीन के बाजार में मंदी के द्वारा उत्पन्न वैश्विक अत्यधिक क्षमता ने अंतर्राष्ट्रीय एसएमओएफ बाजार को नष्ट कर दिया है। इस गिरावट ने उत्पादकों को विभिन्न अधिकार क्षेत्र में अन्य अर्थक्षम व्यापार बाजारों की तलाश करने के लिए विवश कर दिया है। ऐसी परिस्थितियों में, आप्टिकल फाइबर केबल के एक बहुत बड़े उपभोक्ता होने के कारण भारत में आयातों में अचानक वृद्धि देखनी पड़ी।

48.7.2 घरेलू उद्योग ने आगे यह दावा किया है कि एक दूसरे के विरुद्ध एसएमओएफ उत्पादक देशों द्वारा लगाए गए विभिन्न व्यापार अवरोधों/प्रतिबंधों ने भारत जैसे खुले बाजारों को निर्यात के लिए एक प्राथमिक लक्ष्य बना दिया है। उदाहरण के लिए:

- क. चीन की एमओएफसीओएम ने बहुत हद तक यूएस और जापान से एसएमओएफ के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क बढ़ा दिया है। यूएस और जापान से फाइबर के आयातों के संबंध में यूरेशियन यूनियन द्वारा पाटनरोधी शुल्क संबंधी जांच की शुरुआत की गई।
- ख. मार्च, 2018 में, यूरेशियन आर्थिक आयोग (ईसीई) की आंतरिक बाजार के संरक्षण के लिए विभाग ने यूएस और जापान से यूरेशियन इकॉनॉमिक यूनियन को सिंग मोड आप्टिकल फाइबर के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी जांच की शुरुआत की।
- ग. चीन ने भारत से एसएमओएफ के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क बढ़ा दिया है।

48.7.3 घरेलू उद्योग द्वारा आगे यह अनुरोध किया गया है कि अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रमुख बाजारों द्वारा लगाए गए व्यापार अवरोधों ने भारत जैसे खुले बाजार को निर्यात के लिए एक आसान लक्ष्य बनाकर छोड़ दिया है। इसके अलावा, चीन ने भारत, जापान और यूएसए सहित अधिकांश आप्टिकल फाइबर निर्माता देशों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क लगाया है। इसके फलस्वरूप, चीन के बाजार जो संबद्ध वस्तुओं का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, अन्य देशों से निर्यातकों के लिए गैर-अर्थक्षम विकल्प हो गया है। इन

कारकों ने चीन तथा अन्य देशों के निर्यातकों को अन्य अर्थक्षम निर्यात विकल्पों की तलाश करने के लिए विवरण कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2018-19 में विभिन्न देशों से निर्यातों का भारत की ओर अभूतपूर्व विपठन देखा है जिसने भारतीय घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से को प्रतिस्थापित कर दिया है। कुछ इस्पात उत्पादों पर निश्चयात्मक रक्षोपाय शुल्क (उपर्युक्त) लगाते हुए यूरोपीय कमीशन ने नीचे दिए गए अनुसार “अप्रत्याशित घटनाक्रम” के रूप में व्यापार प्रतिबंधात्मक उपायों पर विचार किया था।

“(56) यह आयोग इस तथ्य के रूप में कि व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई विश्व व्यापार संगठन के नियमावली के ढांच के भीतर ली जाती है, के रूप में ऐसे दावों से सहमत नहीं हैं, का आशय यह नहीं होता है कि उन्हें एक अप्रत्याशित घटनाक्रम के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह आयोग विश्व व्यापार संगठन के संगत नियमावली के अनुसार पाटनरोधी अथवा संस्कीर्तीरोधी उपायों को करने के लिए देशों के अधिकार का विरोध नहीं करता है। हालांकि वर्तमान में मुहा तीसरे देशों द्वारा किए गए ऐसे उपायों कि अभूतपूर्व और बड़ी हुई संख्या है जिसके कारण व्यापार में विपठन हुआ है और जिसके फलस्वरूप यूरोपीय यूनियन में आयातों में वृद्धि हुई है”

#### 48.7.4 यूएसए और यूरोप के अधिकारां देशों सहित कई पश्चिमी देशों में चीन में निर्मित ऑप्टिकल फाइबर की बिक्री/उपयोग पर प्रतिबंध।

घरेलू उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि चूंकि एसएमओएफ डिजिटल अवसंरचना में डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रमुख उत्पादों में से एक है अतः पश्चिमी/विकसित देशों में अनेक टेलीकॉम ऑपरेटरों ने अपने नेटवर्क में चीन में निर्मित ऑप्टिकल फाइबर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसी प्रकार से, चीन के उत्पादों पर गैर-विनियामक और गैर-राजकोषीय अवरोधों को आस्ट्रेलिया सहित विभिन्न देशों द्वारा लागू किया गया है। चीन के निर्यातों के आक्रमण तथा आंकड़ों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं के लिए अपने आप को बचाने के उद्देश्य से पश्चिमी यूरोप ने उस पर प्रतिबंध लगाया है। इस कारण से चीन के निर्माताओं का एक प्रतिबंधित अंतर्राष्ट्रीय बाजार है और वे भारत जैसे पास के बढ़ते हुए बाजारों में अपने उत्पादन को खपाने के लिए विवश हैं।

#### 48.7.5 भारत की मांग 2018-19 में विश्व की लगभग 220 मिलियन एफकेएम की क्षमता की तुलना में लगभग 35 मिलियन एफकेएम है। अनेक देशों द्वारा अपने घरेलू उद्योग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रशुल्क/गैर प्रशुल्क अथवा नियामक उपाय करने के साथ निर्यातों का भारत जैसे खुले बाजारों वाले देशों में विपठन हुआ है। ऐसे कारकों को पहले से ही नहीं देखा गया था अथवा उसकी आशा नहीं की गई थी जब भारत को गैट के अंतर्गत दायित्व लेना पड़ा और इस कारण से मेरा यह मानना है कि अप्रत्याशित घटनाक्रमों की स्थिति जिसके कारण आयातों में वृद्धि हुई, को वर्तमान मामले में पूरा नहीं किया गया है।

#### 48.7.6 कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि ये अप्रत्याशित घटनाक्रम प्राथमिक रूप से चीन से संबंधित हैं और इस कारण से यह वैश्विक कार्यवाही को न्यायोनित नहीं ठहराते हैं। चीन का वैश्विक एसएमओएफ के उत्पादन तथा खपत का लगभग 60 प्रतिशत है और इस कारण से चीन के बाजार में योजना की स्थिति अधिकांश एसएमओएफ उत्पादकों को वैश्विक रूप से प्रभावित करेगा। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने चीन में यह उल्लेख किया है कि वह बाजार प्रमुख रूप से चाइना मोबाइल द्वारा प्रभावित होता है जिसका 2017-18 में विश्व के फाइबर के खपत का लगभग 30 प्रतिशत था। इस प्रकार से, चीन के बाजारों की बदली हुई गतिशीलता विशेष रूप से चाइना मोबाइल के खपत पैटर्न में परिवर्तन का काफी हद तक वैश्विक एसएमओएफ ट्रेड पैटर्न पर प्रभाव पड़ता है। इस संदर्भ में घरेलू उद्योग में नीचे दी गई सीआरयू-सितंबर, 2018 की रिपोर्ट से वैश्विक स्तर पर चाइना मोबाइल (सीएम) के प्रभाव को दर्शाते हुए उद्धरण पर विश्वास किया गया है-

“चाइना मोबाइल की मांग की यह छानबीन आवश्यक है क्योंकि 2017 में कंपनी का ऑर्डर विश्व की आधिकल केबल की खपत का 29 प्रतिशत था। 2018 के पूर्वानुमान में, यह आता है कि चाइना मोबाइल का ऑर्डर विश्व के कुल फाइबर संस्थापनाओं का 32 प्रतिशत होगा। इस प्रकार से यदि चाइना मोबाइल का ऑर्डर आशा से कम है अर्थात् 10 प्रतिशत तक है तब विश्व का बाजार आशा से 3 प्रतिशत कम होगा।

**यह स्थिति जिसमें एक ग्राहक के पास विश्व के आॅप्टिकल केबल के बाजार में ऐसी प्रभावशाली भूमिका हो, असामान्य है। एफआईओएस एफटीटीपी के इसके कार्यक्रम के लिए फाइबर की संस्थापनाओं का उद्धतम मांग वाला वर्ष अर्थात् 2006 में, वेरिजोन का विश्व के आॅप्टिकल केबल के बाजार में 9 प्रतिशत हिस्सा था। 2001 में जब एनटीटी ईस्ट और वेस्ट ने एक साथ लगभग 11 मिलियन फाइबर-केम को संस्थापित किया था, दो सहयोगी कंपनियों की खपत विश्व के आॅप्टिकल केबल की खपत का 11 प्रतिशत था।**

48.7.7 इस कारण से चीन के सबसे बड़े उत्पादक होने के साथ और एसएमओएफ का सबसे बड़ा उपभोक्ता होने के साथ भी, इसके पास ग्लोबल एसएमओएफ व्यापार की गतिशीलता को प्रभावित करने की क्षमता है। चीन तथा अन्य देशों द्वारा लगाए गए व्यापार अवरोधन के साथ-साथ चीन के बाजारों की मंदी में भारत जैसे खुले बाजारों को अत्यधिक उत्पादन को खपाने के लिए एक आसान लक्ष्य बना दिया है। ऊपर में दर्शाए गए कारकों से, यह नोट किया जाता है कि विभिन्न उपर्युक्त कारकों के मेल के फलस्वरूप भारत में आयातों में अचानक वृद्धि हुई है, बहुत अधिक क्षमता, वैश्विक मांग में गिरावट और अन्य अधिकार क्षेत्रों में मालसूची जमा हुई है।

48.7.8 इस संदर्भ में, भारत-स्टील रक्षोपाय, में पैनल के निर्णय का भी संदर्भ लिया जाता है जिसमें इसमें भारत के इस दावे को स्वीकार किया था कि अन्य कारकों के साथ-साथ मांग में गिरावट के साथ वैश्विक उत्पादन की क्षमता में अत्यधिक वृद्धि “अप्रत्याशित घटनाक्रम” थी जिसके कारण आयातों में वृद्धि हुई। उक्त रिपोर्ट के संगत पैरा का कुछ अंश नीचे संदर्भ के लिए लिया गया है:

“7.97. हमारे दृष्टिकोण से, भारतीय सक्षम प्राधिकारी के लिए यह पता लगाना तर्क संगत था कि भारत में अपेक्षाकृत अधिक घरेलू मांग, अनेक प्रमुख बाजारों में घटी मांग के साथ-साथ उत्पादन क्षमता में इस सीमा तक वृद्धि और यह कि रूस और यूक्रेन में मुद्रा का अवमूल्यन अप्रत्याशित घटनाक्रम था, हम यह मानते हैं कि इन समझौतों के कारण तर्क-संगत रूप से घटनाओं के इस मेल की आशा नहीं हो सकती थी जब भारत ने अपने प्रशुल्क रियायतों के बारे में समझौता किया। उपर्युक्त कारणों को देखते हुए, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारतीय सक्षम प्राधिकारी ने इस तथ्य के संबंध में कि क्या पहचान किए गए घटनाक्रम अप्रत्याशित थे, तर्क संगत और समुचित व्याख्या उपलब्ध कराईं।”

48.7.9 गैट 1994 के अंतर्गत “लिए गए दायित्वों के प्रभाव” के संबंध में, भारत की रियायत अनुसूची के अनुसार, संबंधित उत्पाद पर निर्धारित दर 40 प्रतिशत यथा-मूल्य है। भारत ने जांच की अवधि के दौरान 10 प्रतिशत (जुलाई, 2019 से आगे 15 प्रतिशत) संबंधित उत्पाद पर लागू दर होने के साथ एसएमओएफ सहित अनेक क्षेत्रों में उत्पादों पर अपने लागू दरों को कम किया। इस प्रकार से, जांच की अवधि के दौरान और सबसे अधिक हाल की अवधि में आयातों में वृद्धि को उपर्युक्त अप्रत्याशित घटनाक्रम और लिए गए दायित्व के प्रभाव के संदर्भ में समझा जा सकता है।

#### 49. गंभीर क्षति और उसके खतरे

- 49.1 इस तथ्य का निर्धारण करने के लिए कि क्या विचाराधीन उत्पादन के बढ़े हुए आयातों के कारण समान अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी उत्पादों के घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है और/अथवा होने का खतरा हो रहा है। घरेलू उद्योग का उत्पादन में हिस्सा, क्षमता उपयोग और कीमत मानदंडों सहित विभिन्न मानदंडों का विश्लेषण दिनांक 6-11-2019 के प्रारंभिक जांच परिणाम में किया गया था। जो बाद की जांच के संबंध में दाखिल किए गए सबमिशन की जाँच के बाद नीचे दिए गए हैं।
- 49.2 “गंभीर क्षति” परिभाषित शब्द को वित्त अधिनियम 2020 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम की धारा 8व्ह की उप धारा (11) (ग) में एक क्षति के रूप में परिभाषित किया गया है जो घरेलू उद्योग की स्थिति में अत्यधिक समग्र हानि पहुंचा रहा हो। “गंभीर क्षति के खतरे” को गंभीर क्षति के एक स्पष्ट और आसन्न खतरे के रूप में धारा 8व्ह की उप धारा 11(घ) में परिभाषित किया गया है।

49.3 रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 4.2 (क) और सीमा प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 8 के अनुबंध में तकनीकी रूप से यह अपेक्षित है कि कुछ सूचीबद्ध कारकों तथा अन्य संगत कारकों का मूल्यांकन अवश्य ही गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे का निर्धारण करने के लिए किया जाना चाहिए। हालांकि ये प्रावधान इसको नहीं सूचित करते हैं कि क्या इस प्रकार का मूल्यांकन दर्शाएगा। इस संबंध में, अर्जेन्टीना-फुटवियर (ईसी),<sup>4</sup> के निर्णय का हवाला लिया जा सकता है जिसमें अपीलीय निकाय ने अनुच्छेद 4.1(क) में “गंभीर क्षति” की परिभाषा और अनुच्छेद 4.2(क) में “सभी संगत कारकों” के मूल्यांकन की आवश्यकता के बीच संबंध पर चर्चा की:

“[...] जब घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन किया जाता हो तब उन सभी संगत कारकों जिनका उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो, के आलोक में यह निर्धारित किया जा सकता है कि क्या उस उद्योग की स्थिति में “बहुत अधिक समग्र हानि हुई है। यद्यपि, अनुच्छेद 4.2(क) में तकनीकी रूप से यह अपेक्षित है कि कुछ सूचीबद्ध कारकों का मूल्यांकन किया ही जाना चाहिए और यह कि सभी अन्य संगत कारकों का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए, वह प्रावधान यह उल्लेख नहीं करता है कि इस प्रकार का मूल्यांकन क्या दर्शाएगा। स्पष्ट रूप से, इस प्रकार का कोई मूल्यांकन किसी विशेष मामले के तथ्यों और संबंधित उद्योग की स्थिति के आधार पर अलग-अलग मामलों में अलग-अलग उद्योगों के लिए अलग-अलग होगा। प्रत्येक सूचीबद्ध कारक का मूल्यांकन आवश्यक रूप से यह नहीं दर्शाएगा कि इस प्रकार का प्रत्येक कारक में “हास” हो रहा है। एक मामले में, उदाहरण के लिए बिक्री, रोजगार और उत्पादकता में बहुत अधिक गिरावट हो सकती है जो उद्योग की स्थिति में “बहुत अधिक समग्र हानि” को दर्शाएगा और इस कारण से गंभीर क्षति के जांच परिणाम को न्यायोचित ठहराएगा। एक अन्य मामले में, किसी कारक में हास नहीं हो सकता है परंतु उसके बावजूद भी समग्र तस्वीर इस उद्योग की “बहुत अधिक समग्र हानि” को दर्शा सकता है। इस प्रकार से, इस तथ्य की क्या किसी विशेष मामले में सक्षम प्राधिकारियों ने सभी सूचीबद्ध कारकों और किसी अन्य संगत कारकों का मूल्यांकन किया है कि तकनीकी जांच के अलावा हमारा यह विश्वास है कि पैनल के लिए “गंभीर क्षति” के किसी निर्धारण की अपनी समीक्षा में रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 4.1(क) में “गंभीर क्षति” की परिभाषा पर विचार करना आवश्यक है।”

49.4 इसके अलावा यूएस - ब्हीट ग्लुटन<sup>5</sup> में पैनल में एक जांच परिणाम में जिसे अपीलीय निकाय द्वारा सही ठहराया गया था, “गंभीर क्षति” पारिभाषिक शब्द के अर्थ के बारे में विस्तार से चर्चा की थी।

“[क] इस प्रकार के “बहुत अधिक समग्र” हानि के होने के संबंध में निर्धारण उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत कारकों के आलोक में घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर ही किया जा सकता है।

----

[डब्ल्यू] हम यह नहीं मानते हैं कि प्रत्येक कारक जिसकी जांच की गई है में नकारात्मक प्रवृत्ति किसी उद्योग के बहुत अधिक समग्र हानि की स्थिति में होने के लिए आवश्यक है। बल्कि प्रवृत्तियों और उनके बातचीत की समग्रता में यह है कि उस पर गंभीर क्षति के निर्धारण के संबंध में विचार किया जाना चाहिए। इस प्रकार से ऐसा अनेक कारकों में परिवर्तन गंभीर क्षति के निर्धारण को आवश्यक रूप से नहीं रोकेगा। यह जांच प्राधिकारियों के लिए है कि वे अपने समक्ष साक्ष्य का आंकलन करें और इस तथ्य का एक समुचित, तर्क संगत और उचित व्याख्या करें कि किस प्रकार से ये तथ्य किए गए निर्धारण का समर्थन करता है।”

<sup>4</sup> अपीलीय निकाय की रिपोर्ट, अर्जेन्टीना-फुटवियर (ईसी), पैरा. 139

<sup>5</sup> पैनल रिपोर्ट, यूएस-ब्हीट ग्लुटन, पैरा. 8.80 और 8.85

49.5 तदनुसार, गंभीर क्षति और गंभीर क्षति का विश्लेषण करने में वे कारक जिनका उल्लेख इस नियमावली में किया गया है और गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे के निर्धारण के लिए संगत हैं, पर भी विचार किया जाना चाहिए जिसकी चर्चा नीचे की गई है।

**क. बिक्री के स्तर में परिवर्तन:**

घरेलू बाजार में आवेदकों की बिक्री को खंडों में: (i) स्वतंत्र ग्राहकों को बिक्री, (ii) कैप्टिव/संबंधित पक्षकारों को बिक्री में बाटा जा सकता है। घरेलू उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि आयातों में अचानक वृद्धि का कैप्टिव/संबंधित पक्षकारों को उनकी बिक्री पर प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि आयात कैप्टिव/संबंधित पक्षकार खंड में उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं करता है। हालांकि, स्वतंत्र ग्राहकों को उनकी घरेलू बिक्री में पिछले वर्षों की तुलना में काफी हद तक गिरावट आई है और इस खंड में घरेलू उद्योग की बिक्री को आयातों के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। आयातों के विरुद्ध घरेलू उद्योग द्वारा की गई बिक्री का विश्लेषण नीचे दिए गए अनुसार है:

| (केएफकेएम)   | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | जनवरी'19<br>से जून'19 | जनवरी'19 से जून'19<br>(वार्षिकीकृत) |
|--|---------|---------|---------|-----------------------|-------------------------------------|
| घरेलू उद्योग की बिक्री (कैप्टि<br>व/संबंधित)             | ***     | ***     | ***     | ***                   | ***                                 |
| प्रवृत्ति  | 100     | 188     | 213     | 171                   | 171                                 |
| घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री<br>(गैर-कैप्टि/गैर-संबंधित) | ***     | ***     | ***     | ***                   | ***                                 |
| प्रवृत्ति  | 100     | 65      | 48      | 31                    | 31                                  |
| आयात (गैर-घरेलू उद्योग)                                  | 1,903   | 2,469   | 7,066   | 3,267                 | 6,534                               |
| प्रवृत्ति  | 100     | 130     | 371     | 343                   | 343                                 |

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाती है कि 2016-17 में आयात 1903 केएफकेएम था और घरेलू उद्योग की बिक्री \*\*\* केएफकेएम थी। यह स्थिति आयातों के \*\*\* केएफकेएम तक बढ़ने तथा घरेलू उद्योग की बिक्री \*\*\* केएफकेएम तक कम होने के साथ सबसे हाल की अवधि में विपरीत हो गई है। घरेलू उद्योग द्वारा खोए गए बाजार के हिस्से को बढ़े हुए आयातों के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। इसके अलावा, कैप्टिव/संबंधित पक्षकार को घरेलू उद्योग की बिक्री को मिलाकर आयातों में अचानक वृद्धि के द्वारा अप्रभावित नहीं है।

**ख. घरेलू मांग में आयातों और घरेलू उत्पादकों का बाजार हिस्सा**

आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि उनकी अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री के आंकड़ों तक पहुंच नहीं है और इस कारण से भारतीय खपत की कुल संख्या को सीआरयू की तिमाही रिपोर्ट से लिया गया है, यह वह निकाय है जिसे आप्टिकल फाइबर बाजार सहित कोकोडिटी बाजारों का अध्ययन करने और उसका विश्लेषण करने में विशेषज्ञता प्राप्त है। तदनुसार, सीआरयू में प्रकाशित आंकड़ों के संबंध में परिकलित भारतीय मांग की प्रारंभिक जांच परिणामों में विचार किया गया था। चूंकि किसी भी हितबद्ध पक्षकारों ने सीआरयू रिपोर्ट से मांग की गणना पर कोई आपत्ति नहीं की है अथवा भारतीय मांग पर सूचना के किसी वैकल्पित स्रोत को प्रस्तुत नहीं किया है, अतः सीआरयू के संबंध में परिकलित मांग पर विचार अंतिम निर्धारण में भी किया जा रहा है।

स्वतंत्र उपभोक्ताओं के लिए बाजार में हिस्से का विश्लेषण करने के लिए, घरेलू उद्योग द्वारा पीयूसी की खपत (या तो कैप्टिव/संबंधित पक्षकार की विक्री अथवा आयातों के द्वारा) को सीआरयू में सूचित किए गए अनुसार कुल भारतीय खपत से बाहर रखा गया है और भारत में इस प्रतिशत हिस्से को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

आंकड़े: केएफकेएम में

|   | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | जनवरी'19<br>सेजून'19 | जनवरी'19 से<br>जून'19<br>(वार्षिकीकृत) |
|---|---------|---------|---------|----------------------|--|
| प्रति सीआरयू के अनुसार भारतीय खपत   | 27062   | 32186   | 35197   | 17547                | 35094                                  |
| स्वतंत्र ग्राहकों के लिए भारतीय खपत (घरेलू उद्योग के कैप्टिव/संबंधित पक्षकार की विक्री और घरेलू उद्योग के आयातों को छोड़कर)                                   | 17,971  | 15,057  | 12,948  | 8,763                | 17526                                  |
| आयात (गैर-घरेलू देश)  | 1,903   | 2,469   | 7,066   | 3,267                | 6534                                   |
| स्वतंत्र ग्राहकों के लिए मांग में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा  | ***     | ***     | ***     | ***                  | ***                                    |
| घरेलू उद्योग की घरेलू विक्री(प्रवृत्ति)   | 100     | 65      | 48      | 31                   | 31                                     |
| स्वतंत्र ग्राहकों के लिए मांग में आयातों (गैर-घरेलू उद्योग) का हिस्सा (घरेलू उद्योग के कैप्टिव/संबंधित पक्षकार की विक्री और घरेलू उद्योग के आयातों को छोड़कर) | 11%     | 16%     | 55%     | 37%                  | 37%                                    |
| स्वतंत्र ग्राहकों के लिए मांग में घरेलू उद्योग के हिस्से की प्रवृत्ति (घरेलू उद्योग की कैप्टिव खपत और संबंधित पक्षकार की विक्री को छोड़कर)                    | 100     | 77      | 67      | 31                   | 31                                     |

#### ग. उत्पादन के स्तर में परिवर्तन:

सबसे अधिक हाल की अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन में 2017-18 और 2018-19 की तुलना में बहुत अधिक ह्रदतक गिरावट आई है यद्यपि मांग में बहुत अधिक ह्रदतक वृद्धि हुई है।

| उत्पाद<br>(केएफकेएम)       | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | जनवरी'19 से जून'19 | जनवरी'19 से जून'19<br>(वार्षिकीकृत) |
|----------------------------|---------|---------|---------|--------------------|-------------------------------------|
| एसटीएल                     | 100     | 115     | 123     | 117                | 117                                 |
| बीएफएल                     | 100     | 111     | 109     | 62                 | 62                                  |
| घरेलू उद्योग का कुल उत्पाद | 100     | 114     | 120     | 103                | 103                                 |

### घ. क्षमता का उपयोग

घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग नीचे दिया गया है:

| क्षमता उपयोग                                | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | जनवरी'19 से जून'19 | जनवरी'19 से जून'19 (वार्षिकीकृत) |
|---|---------|---------|---------|--------------------|----------------------------------|
| घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता (केएफकेएम) | ***     | ***     | ***     | ***                | ***                              |
| प्रवृत्ति (Trend)                           | 100     | 112     | 135     | 143                | 143                              |
| घरेलू उद्योग का उत्पादन (केएफकेएम)          | ***     | ***     | ***     | ***                | ***                              |
| प्रवृत्ति (Trend)                           | 100     | 114     | 120     | 103                | 103                              |
| घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग                | ***     | ***     | ***     | ***                | ***                              |
| प्रवृत्ति (Trend)                           | 100     | 103     | 86      | 73                 | 73                               |

घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग में 2017-18 में \*\*\* प्रतिशत से सबसे हाल के अवधि में \*\*\* प्रतिशत तक गिरावट आई है।

आवेदकों ने यह दावा किया है कि इस उद्योग के लिए आदर्शतम क्षमता उपयोग लगभग 95-100 प्रतिशत है क्योंकि उत्पादन को कम करने अथवा संयंत्र को फिर से शुरू करने के साथ जुड़ी हुई लागत बहुत अधिक है। घरेलू उद्योग ने आगे यह दावा किया है कि क्षमता उपयोग पिछले वर्षों के स्तरों से कम हो रहा है और विचाराधीन उत्पाद की मांग में किसी गिरावट के बिना 95 प्रतिशत से कम से लेकर 100 प्रतिशत तक रहा है।

आवेदक ने यह भी अनुरोध किया है कि भारतीय मांग में वृद्धि का अनुमान करते हुए, आवेदकों ने अपने उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करने के लिए बहुत अधिक निवेश किए थे और यह कि एसटीएल घरेलू बाजार में ऑर्डर के न होने के कारण अपनी 11000 केएफकेएम की नई क्षमता (जिस पर उपर्युक्त तालिका में विचार नहीं किया गया है) को आरंभ करने में विलंब करने के लिए बाध्य था। हालांकि इस क्षमता को आरंभ कर दिया गया है और यह अगस्त, 2019 से उपयोग में है जिसके कारण आगे जांच की बाद की अवधि में क्षति पर दबाव पड़ा है और क्षमता के उपयोग में कमी आई है।

### ड. रोजगार

आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि जांच की अवधि के दौरान रोजगार के अवसरों में कोई अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है।

| स्थान                                    | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | जनवरी-जून'19 |
|--|---------|---------|---------|--------------|
| एसटीएल, वालुज (प्रवृत्ति)                | 100     | 110     | 110     | 107          |
| एसटीएल, शेन्दा (प्रवृत्ति)               | 100     | 201     | 167     | 153          |
| बीएफएल (प्रवृत्ति)                       | 100     | 112     | 112     | 110          |
| घरेलू उद्योग के कुल कर्मचारी (प्रवृत्ति) | 100     | 125     | 120     | 115          |

हालांकि कम होता हुआ बाजार हिस्सा और क्षमता के उपयोग को देखते हुए, आवेदकों ने यह दावा किया है कि उन्होंने 2019-20 की दूसरी तिमाही (जुलाई, 2019 से सितंबर 2019) में उन्होंने अपनी निर्माण क्षमता के एक हिस्से को बंद कर दिया है और उन्हें अपने कुछ कार्य-बलों की छटनी करनी पड़ी थी।

### च. उत्पादकता

उत्पादकता में सबसे हाल की अवधि में उत्पादन में गिरावट के कारण आंशिक रूप से गिरावट आई है।

| उत्पादकता               | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | जनवरी-जून'19 |
|-------------------------|---------|---------|---------|--------------|
| घरेलू उद्योग का उत्पादन | ***     | ***     | ***     | ***          |
| प्रवृत्ति               | 100     | 114     | 120     | 103          |
| कर्मचारी                | ***     | ***     | ***     | ***          |
| प्रवृत्ति               | 100     | 125     | 120     | 115          |
| उत्पादकता               | ***     | ***     | ***     | ***          |
| प्रवृत्ति               | 100     | 90      | 99      | 89           |

### छ. लाभ/हानि

घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में पिछले वर्ष 2017-18 की तुलना में 2018-19 में सबसे हाल की अवधि में हानि के साथ गिरावट आई है। इतनी कम कीमतों पर हो रहे आयातों के कारण, घरेलू उद्योग उचित लाभ/आय अर्जित करने में सक्षम नहीं है। जांच की अवधि के दौरान लाभ/हानि की प्रवृत्ति नीचे दिए गए अनुसार है:

आंकड़े: प्रवृत्ति में

|  | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | जनवरी-जून'19 |
|--|---------|---------|---------|--------------|
| घरेलू उद्योग विना औसत इकाई विक्री कीमत के (गैर-कैप्टिव/असंबंधित) | 100     | 117     | 121     | 82           |
| घरेलू उद्योग विना औसत विक्री लागत के                             | 100     | 103     | 112     | 118          |
| घरेलू उद्योग लाभ/हानि  | 100     | 173     | 158     | (65)         |

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाती है कि सबसे हाल की अवधि के दौरान, आवेदकों को सबसे अधिक हाल की अवधि विशेषकर 2019-20 की पहली तिमाही में बहुत कम कीमतों पर हो रहे आयातों के कारण अपनी विक्री की लागत से बहुत अधिक कम कीमतों पर विक्री करना पड़ा और उसे हानि हुई। पिछली चार तिमाहियों के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता का तिमाही विश्लेषण नीचे दिए गए अनुसार है:

| लाभ/हानि            | वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही' 18-19 | वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही' 18-19 | वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही' 18-19 | वित्तीय वर्ष की चारी तिमाही' 18-19 | वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही' 19-20 |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| एसटीएल (रु./एफकेएम) | ***                                | ***                                 | ***                                 | ***                                | ***                                |
| प्रवृत्ति           | 100                                | 80                                  | 79                                  | 9                                  | (48)                               |
| वीएफएल(रु./एफकेएम)  | ***                                | ***                                 | ***                                 | ***                                | ***                                |
| प्रवृत्ति           | 100                                | 95.80                               | (35)                                | (138)                              | (192)                              |

**ज. कम कीमत पर बिक्री, कीमत में कटौती और कीमत न्यूनीकरण**

कम कीमत पर बिक्री, कीमत में कटौती और कीमत न्यूनीकरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

आंकड़े: रु./केएफकेएम में

| प्रति इकाई                                     | जनवरी- जून 2019 |
|--|-----------------|
| घरेलू उद्योग-भारित औसत इकाई बिक्री कीमत (एसपी) | ***             |
| भारित औसत उचित बिक्री कीमत (एफएसपी)            | ***             |
| पहुंच मूल्य (रु./केएफकेएम)                     | 411             |
| कीमत में कटौती (एसपी-एलवी)                     | (***)           |
| कम कीमत पर बिक्री (एफएसपी (एलवी)               | ***             |
| कीमत न्यूनीकरण                                 | ***             |

सबसे अधिक हाल की अवधि में, संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की उचित बिक्री कीमत से बहुत अधिक कम है जिसके कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ रहा है।

कीमत में नकारात्मक कटौती के बिंदु पर, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि ये निर्यातक आयातकों को अपेक्षाकृत अधिक लम्बी क्रेडिट अवधि अथवा भारी मात्रा में छूट देती रही है।

महानिदेशक यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग \*\*\* रु. प्रति एफकेएम की बिक्री कीमत प्राप्त करने में सक्षम रहा है जो विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग के लिए स्थापित उचित बिक्री कीमत और बिक्री की लागत से बहुत कम है। इस प्रकार से, कीमत में नकारात्मक कटौती यह दर्शाती है कि आयात कीमतों के फलस्वरूप कीमतों पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है। इस प्रकार, इस कीमत के नकारात्मक मूल्य को इस पृष्ठभूमि में सराहा जाना चाहिए कि आयात की कीमतें इस हद तक महत्वपूर्ण मूल्य दमन की ओर ले गई हैं कि इसने बाजार में बने रहने के लिए आयात के उतरे हुए मूल्य से भी नीचे घरेलू उद्योग के NSR को खींच लिया है।

**क. मालसूची**

नीचे दी गई तालिका मालसूची के स्तरों को दर्शाती है जिसमें जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक वृद्धि देखी गई है।

आंकड़े: प्रवृत्ति में

| वित्तीय वर्ष /तिमाही | मालसूची (एसटीएल) | मालसूची (बीएफएल) | कुल घरेलू उद्योग |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2016-17              | 100              | 100              | 100              |
| 2017-18              | 79               | 67               | 73               |
| 2018-19              | 567              | 171              | 356              |
| जन.'19 to जून'19     | 588              | 193              | 377              |

आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि सामान्य तौर पर वे अनुमानित विक्री के अनुरूप उत्पादन बनाए रखते हैं जिससे कि अधिक मालसूची बनाए रखने से जुड़ी लागतों से बचा जा सके। इसके परिणामस्वरूप, सामान्य तौर पर इसके पास सीमित भंडार उपलब्ध रहेगा। हालांकि आयातों के बहुत अधिक मात्रा में होने के कारण, आवेदकों के कई ग्राहकों ने अपनी संविदाओं का पालन करने से इंकार किया है जिसके फलस्वरूप बहुत अधिक मालसूची जमा हो गई है। इसके अलावा, उत्पादन में कमी के फलस्वरूप बीएफएल के पास बहुत अधिक कच्चा माल (प्रिफॉर्म) भंडार जमा हो गया है।

49.7 ऊपरयुक्त विश्लेषण से यह नोट किया जाता है कि वर्तमान मामले में सभी प्रमुख संगत मानदंड घरेलू उद्योग की स्थिति में गिरावट को दर्शाते हैं और इस प्रकार से गंभीर क्षति और उसका खतरा सिद्ध होता है।

## 50. बढ़े हुए आयात और गंभीर क्षति/ गंभीर क्षति के खतरे के बीच कारणात्मक संबंध

50.1 कोरिया-डेयरी संबंधी विश्व व्यापार संगठन के पैनल ने “कारणीय संबंध” का निर्धारण करने के लिए मूल दृष्टिकोण नीचे दिए गए अनुसार निर्दिष्ट किया:

“अपने कारणात्मक संबंध का आंकलन करने में, हमारा यह दृष्टिकोण है कि राष्ट्रीय प्राधिकारी को इस तथ्य का विश्लेषण और निर्धारण करने की आवश्यकता है कि क्या राष्ट्रीय प्राधिकारी द्वारा गंभीर क्षति को दर्शाने के लिए विचार किए गए इस उद्योग में घटनाक्रम बढ़े हुए आयातों के कारण हुई है। अपने कारण संबंध के आंकलन में, राष्ट्रीय प्राधिकारी का यह दायित्व है कि वे उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले वस्तुनिष्ठ और मात्रा बताने योग्य प्रकृति के सभी संगत कारकों का मूल्यांकन करें। इसके साथ ही, यदि राष्ट्रीय प्राधिकारी ने बढ़े हुए आयातों जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, को घोड़कर अन्य कारकों की पहचान की है तब यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार के कारकों के कारण हुई किसी क्षति पर विचार बढ़े हुए आयातों के कारण हुई क्षति के रूप में नहीं किया गया है। कारणात्मक संबंध स्थापित करने के लिए, कोरिया को यह दर्शाना है कि इसके घरेलू उद्योग को क्षति बढ़े हुए आयातों के परिणामस्वरूप होती है। अन्य शब्दों में, कोरिया को यह दर्शाना है कि एसएमपीपी के आयातों के कारण घरेलू उद्योग जो दूध के पाउडर और अपरिष्कृत दूध का उत्पादन करते हैं, को क्षति होती है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की स्थिति का विश्लेषण करने के बाद, कोरिया के प्राधिकारी का यह दायित्व है कि वह अन्य कारकों के कारण हुई किसी क्षति का कारण बढ़े हुए आयातों को नहीं माने।”

50.2 व्हीट ग्लुटोन मामले में विश्व व्यापार संगठन कि अपीलीय निकाय की रिपोर्ट में यह माना गया है:

“हम अनुच्छेद 4.2(ख) के पहले वाक्य से अपना तर्क शुरू करते हैं। उस वाक्य में यह प्रावधान है कि जब तक “यह जांच बढ़े हुए आयातों और उसके गंभीर खतरे अथवा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का होना नहीं दर्शाता हो तब निर्धारण किया जाएगा” (इस पर बल दिया गया है)। इस प्रकार से अनुच्छेद 4.2 (क) के अंतर्गत निर्धारण के लिए आवश्यकता यह है कि “कारणात्मक संबंध” बना हुआ है। ‘कारणात्मक’ शब्द का आशय “कारण अथवा कारणों से संबंधित” है जबकि “कारण शब्द बाद में कम से कम दो कारकों जिसके द्वारा पहला कारक कुछ अर्थों में दूसरे कारक (1) के मौजूद रहने के बारे में “दर्शाया हो”; “प्रस्तुत” किया हो अथवा “आरंभ” किया है के बीच संबंध को दर्शाता है। “संबंध” शब्द केवल यह दर्शाता है कि बढ़े हुए आयातों ने गंभीर क्षति उत्पन्न करते हुए उसमें एक भूमिका निभाई है अथवा उसमें योगदान किया है ताकि इन दो कारकों के बीच कारणात्मक “संबंध” (2) अथवा “सांठगांठ” है। इन शब्दों को एक साथ लेते हुए, “कारणात्मक संबंध” पारिभाषिक शब्द हमारे दृष्टिकोण से कारण और प्रभाव के संबंध को इस प्रकार से दर्शाता है कि बढ़े हुए

**आयातों का गंभीर क्षति “उत्पन्न करने”, “लाने” अथवा “आरंभ करने” में योगदान है। यद्यपि वह अंशदान पर्यामि रूप से स्पष्ट होना चाहिए जिससे अपेक्षित “कारणात्मक संबंध” के होने को सिद्ध किया जा सके, अनुच्छेद 4.2(ब) के पहले वाक्य में भाषा इस तथ्य का संकेत नहीं देता है कि बढ़ा हुआ आयात गंभीर क्षति का एकमात्र कारण है अथवा यह कि क्षति पहुंचाने वाले “अन्य कारकों” को गंभीर क्षति के निर्धारण से बाहर किया ही जाना चाहिए। इसके विपरीत, कुल मिलाकर अनुच्छेद 4.2(ब) की भाषा इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि बढ़े हुए आयातों और गंभीर क्षति के बीच “कारणात्मक संबंध” हो सकता है यद्यपि अन्य कारकों का भी घरेलू उद्योग की स्थिति में “साथ-साथ” योगदान हो रहा है।**

- 50.3 उपरोक्त विधि-शास्त्र को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच यह देखने के लिए की जाती है कि क्या आयातों और गंभीर क्षति अथवा घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही गंभीर क्षति के खतरे के बीच कारणात्मक संबंध है। 2016-17 से लेकर 2018-19 और जनवरी-जून, 2019 की अवधि के लिए आंकड़ों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि विचाराधीन उत्पाद के आयात 2018-19 की पहली तिमाही से सबसे अधिक हाल की अवधि तक बहुत हद तक उच्च स्तरों पर बना हुआ है और यह भी कि विचाराधीन उत्पाद की आयात कीमतों में सबसे हाल की अवधि में बहुत अधिक हद तक कमी आई है। इसके फलस्वरूप, घरेलू उद्योग को सबसे अधिक हाल की अवधि में अपनी कीमतों को नीचे की ओर संशोधित करना पड़ा है और उसके परिणामस्वरूप हानि हुई है। इसके फलस्वरूप, घरेलू उद्योग की निबल बिक्री प्राप्ति में पिछली तिमाहियों और आधार वर्ष तथा पिछले वर्ष से तुलना की जाने पर तेजी से कमी आई है।
- 50.4 ऊपर में उल्लेख किए गए मानदंडों का व्यापक मूल्यांकन यह दर्शाता है कि गंभीर क्षति घरेलू उद्योग को जांच की अवधि और विशेषकर 2018-19 की पहली तिमाही से 2019-20 की पहली तिमाही के दौरान विचाराधीन उत्पाद के बहुत अधिक हद तक बढ़े हुए आयातों के कारण हुई है। उपर्युक्त परिस्थितियों में यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि आयातों में अचानक तीव्र वृद्धि और क्षति (और उसका खतरा) जो घरेलू उद्योग को हो रही है के बीच कारणात्मक संबंध मौजूद है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में, विक्री (मात्रा और कीमत), क्षमता का उपयोग और लाभप्रदता आदि में गिरावट की अवधि सीधे तौर पर उसी अवधि के दौरान हुई है जब आयातों में अचानक और बहुत अधिक वृद्धि हुई थी।

#### **घरेलू उद्योग के लिए अधिक उपयुक्त उपाय होने के लिए पाटनरोधी शुल्क के बारे में प्रस्तुतियाँ हैं:**

- 50.5 कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग को क्षति चीन से कम कीमत पर आयातों में अचानक वृद्धि के कारण हुई है और इस कारण से वर्तमान मामले में उपयुक्त उपचार “पाटनरोधी शुल्क” और न कि रक्षोपाय संबंधी कार्रवाई हुई होती। इस कारण से उन्होंने इस नियमावली के अनुबंधों के पैरा 2 के संबंध में वर्तमान जांच को समाप्त करने का अनुरोध किया है।
- 50.6 हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट किया जाता है कि विभिन्न व्यापार उपाय, यानी एंटी-डंपिंग, काउंटरवैलिंग ड्यूटी या सेफगार्ड पारस्परिक रूप से निर्णायक नहीं होते हैं और इनफैक्ट को समर्ती लागू किया जा सकता है, साथ ही यदि कोई उपाय करने से संबंधित शर्तें संतुष्ट हैं। इस जांच में, प्रासंगिक अधिनियम / नियमों के अनुसार एक सुरक्षा उपाय के लिए विश्लेषण किया गया है और बाद में पैरा में आयात में वृद्धि के कारण उचित मात्रा और कार्यकाल के उपाय पर विचार किया गया है।

#### **व्यक्तिगत देशों के आयात**

- 50.7 इसके अलावा, एसईआई लिमिटेड, जो हितबद्ध पक्षकारों में से एक है ने यह अनुरोध किया है कि कुल आयातों में जापान के हिस्से में 2018-19 और सबसे अधिक हाल की अवधि में काफी हद तक गिरावट आई है और इस कारण से जापान पर रक्षोपाय शुल्क लगाना आवश्यक नहीं है। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि न तो सीमा प्रशुल्क अधिनियम और न ही उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली में “बढ़े हुए आयातों” की देशवार जांच का प्रावधान है इस प्रकार से “बढ़े हुए आयातों” का निर्धारण करने के लिए, यह दर्शने के लिए कानून के

अंतर्गत कोई आवश्यकता नहीं है कि सभी शुल्कों से आयातों में वृद्धि हुई है। इस संदर्भ में यह नोट करना आवश्यक है कि रक्षोपाय कानून के अंतर्गत अधिदेश घरेलू उद्योग को आयातों में अचानक वृद्धि के प्रभाव से संरक्षण प्रदान करना है। अतः देशवार आयात का विशेषण रक्षोपाय जांचों में विकासशील देशों से न्यूनतम से कम आयातों का निर्धारण करने को छोड़कर अपेक्षित नहीं है। इस प्रकार से, आयातों में प्रत्येक देश के हिस्से को कोई महत्व दिए जाने की आवश्यकता नहीं है।

- 50.8 भारत में **डायोकिटल फिथलेट** के आयातों के संबंध में रक्षोपाय जांच में जारी किए गए दिनांक 16.11.2012 के अंतिम जांच परिणामों में समान तर्क के बारे में बताते समय, प्राधिकारी ने नीचे दिए गए अनुसार माना:

“जहां तक इन तर्कों का पश्च है कि कोरिया का निर्यात 2011 में उक्त अवधि में 11924 मी.टन से गिरकर 3382 मी.टन हो गया है, यह नोट किया जाता है कि आयातों में अलग अलग देश का संचलन रक्षोपाय जांचों के अंतर्गत पूर्ण रूप से असंगत है क्योंकि विभिन्न लोगों से संचयी आयातों पर विचार आयातों में तीव्र वृद्धि के लिए नहीं किया गया है”

- 50.9 इस प्रकार से विधान तथा इस निदेशालय की विगत कार्य-पद्धति के उद्देश्य को ध्यान में रखकर, वर्तमान जांच को समाप्त करना आवश्यक नहीं है।

## 51. समायोजन योजना

- 51.1 रक्षोपाय संबंधी विश्व व्यापार संगठन के करार की आवश्यक विशेषताओं में से एक विशेषता घरेलू उद्योग द्वारा समायोजन है।

- 51.2 इसके अलावा, रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 5.1 में यह प्रावधान है कि सदस्य रक्षोपाय शुल्कों को उसी सीमा तक लागू करेंगे जिस सीमा तक गंभीर क्षति को रोकने अथवा उसका उपचार करने तथा समायोजन को आसान बनाने के लिए आवश्यक हो। रक्षोपाय शुल्क संबंधी करार के अनुच्छेद 7.1 में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश को यह अधिकार दिया गया है कि वे केवल उसी समय अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क को लागू करेंगे जो गंभीर क्षति को रोकने अथवा उसका उपचार करने तथा समायोजन को आसान बनाने के लिए आवश्यक हो सकता है। अनुच्छेद 7.4 यह अधिकार देता है कि उस स्थिति में जब अनुच्छेद 12 के पैरा 1 के प्रावधानों के अंतर्गत तथा अधिसूचित रक्षोपाय शुल्क की प्रत्याशित अवधि एक वर्ष से अधिक हो, समायोजन को आसान बनाने के लिए, शुल्क लगाने वाले सदस्य इसके लगाए जाने की अवधि के दौरान नियमित अंतरालों पर इसे प्रगामी रूप से उदार बनाएंगे। ये प्रावधान रक्षोपाय नियमावली (4) (ii), 11(2), 11(3), 12(1), 16(1) का प्रतुक और 16(2) का परंतुक के साथ एक ही विषय से संबंधित हैं। इसके अलावा, रक्षोपाय नियमावली के नियम 5(2) में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

“(2) उप नियम (1) के अंतर्गत आवेदन उस रूप में होगा जिसका उल्लेख महानिदेशक द्वारा इस संबंध में किया जाएगा और इस प्रकार के आवेदन के समर्थन में निम्नलिखित संलग्न किया जाएगा-

(ख) आयात संबंधी प्रतिस्पर्धा के प्रति सकारात्मक समायोजन करने के लिए किए जा रहे, अथवा किए जाने के लिए योजनाबद्ध अथवा दोनों के वास्ते प्रयासों के संबंध में विवरण”।

- 51.3 घरेलू उद्योग ने योजना का विस्तृत विवरण जो उन्होंने आयातों के प्रति अपने आप को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए किया है अथवा करेंगे, का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। इस योजना में कच्चे मालों/खपत की जाने वाली वस्तुओं के बेहतर उपयोग के द्वारा अपनी लागतों में कमी आने तथा अपनी कार्य-क्षमता में सुधार लाने के प्रति तथा बैकवर्ड एकीकरण के माध्यम से उठाए गए कदम शामिल हैं। घरेलू उद्योग ने पहले ही अपने कच्चे माल से बेहतर परिणाम प्राप्त करने, कुछ कच्चे मालों जिसके लिए वे अन्य प्रकार से आयात पर निर्भर थे, का इन हाउस उत्पादन के द्वारा लागत में कमी लाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। दोनों कंपनियां जो घरेलू उद्योग हैं, को उनकी अलग-अलीग योजनाएं/परियोजनाएं दी हैं, जिस पर वे आयातों के बढ़े हुए स्तर के प्रति समायोजन

करने के लिए विचार कर रहे हैं। उन्होंने बचत का विवरण भी उपलब्ध कराया है जो उनकी योजना के सफल कार्यान्वयन पर होगा।

- 51.4 रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने का विरोध करने वाले कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने अपनी समायोजन योजना के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। यह नोट किया जाता है कि अगोपनीय सार में, घरेलू उद्योग ने यह संकेत दिया है कि उन्होंने उन परियोजनाओं को शुरू किया है जो कच्चे माल का बेहतर उपयोग, कच्चे माल की खरीद की लागत में कमी और उत्पादन की प्रक्रिया में अवरोधों को हटाकर अपेक्षाकृत अधिक लागत कार्यक्षम उन्हें प्राप्त करने में मदद करेगा। घरेलू उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि उनके द्वारा शुरू की जा रही परियोजनाओं में ब्रांड युक्त प्रौद्योगिकी का विकास करना शामिल है जिसके संबंध में सूचना सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है और वह व्यापार संवेदनशील है।
- 51.5 यह देखा गया है कि रक्षोपाय नियमावली का नियम 5(2) समायोजन योजनाओं के रूप में संदर्भित समायोजन विवरण के लिए प्रपत्र उपलब्ध नहीं कराता है। रक्षोपाय शुल्क संबंधी करार में भी कोई मार्गदर्शन नहीं दिया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा उठाए जाने के लिए योजनाबद्ध प्रयासों के विवरण जिसे इस याचिका में उपलब्ध कराया गया है, की जांच की गई है। इसके अलावा, चूंकि यह एक प्रौद्योगिकी गहन उद्योग है जिसमें सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपनाई जा रही पेटेंट की गई अनेक प्रक्रिया निहित हैं, घरेलू उद्योग का उनके समायोजन संबंधी योजना के बारे में गोपनीयता के लिए दावा स्वीकार किया गया है।
- 51.6 यह देखा गया है कि एसटीएल ने पांच अलग अलग परियोजनाओं का संकेत दिया है जिसे उनके द्वारा शुरू किया गया है जो काफी हद तक उनके कच्चे माल की कीमतों को कम करेगा और उनकी कार्य-क्षमता में सुधार लाएगा। इसके अलावा, बीएफएल ने अपनी कार्यवाही योजना भी प्रस्तुत की है जो उन्हें अपनी लागत 8-10 प्रतिशत तक कम करने में मदद करेगा।
- 51.7 कोरिया-डेयरी मामले (डब्ल्यूटी/डी598) में पैनल की रिपोर्ट ने समायोजन योजना के संबंध में निम्नलिखित को माना:
- “हम इसे स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम अनुच्छेद 5.1 की व्याख्या इन प्राधिकारियों द्वारा एक समायोजन योजना पर विचार किए जाने की आवश्यकता होने के रूप में नहीं करते हैं जैसा कि यूरोपीय समुदाय दृढ़तापूर्वक कहता है। यह पैनल कोई विशिष्ट आवश्यकता को नहीं पाता है कि इस प्रकार की समायोजन योजना के संबंध में अनुरोध और उस पर विचार रक्षोपाय संबंधी करार के संदर्भ में किया ही जाना चाहिए। यद्यपि इसके दो प्रावधानों में उद्योग के समायोजन का संदर्भ है फिर भी रक्षोपाय संबंधी करार के पाठ में कोई भी तथ्य इस बात का संकेत नहीं देता है कि विशिष्ट समायोजना पर विचार किया जाना शुल्क को अपनाए जा सकने के पूर्व अपेक्षित है। बल्कि, हमारा यह विश्वास है कि गंभीर क्षति को रोकने अथवा उसका उपचार करने के प्रश्न के साथ समायोजन का प्रश्न प्राधिकारियों के इस शुल्क के तर्क-संगत व्याख्या का भाग होना चाहिए जो इसने लागू करने के लिए चुना है। फिर भी, हम नोट करते हैं कि रक्षोपाय शुल्क को लगाने के संदर्भ के भीतर समायोजन योजना की जांच मजबूत साक्ष्य होगा कि प्राधिकारियों ने इस तथ्य पर विचार किया है कि क्या यह शुल्क गंभीर क्षति को रोकने अथवा उसका उपचार करने और समायोजन को आसान बनाने के उद्देश्य का समानुपाती था।”
- 51.8 अतः, उपर्युक्त और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई समायोजन योजना को देखते हुए, यह पाया गया है कि दी गई पारिस्थितिकी में घरेलू उद्योग द्वारा विचार की गई समायोजन योजना तर्कसंगत और व्यावहारिक प्रतीत होता है। इसका उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि चूंकि रक्षोपाय शुल्क के अंतर्गत राहत आपातकालीन उपाय के रूप में सीमित समय अवधि के लिए ही है और आयातों में उद्धाल का मुकाबला करने के लिए उद्योग के समायोजन संबंधी प्रयासों को इस नियमावली के प्रावधान के अनुसार प्राथमिक रूप से देखे जाने की आवश्यकता है।

## 52. जनहित

- 52.1 इस तथ्य का विश्लेषण करने की आवश्यकता कि क्या रक्षोपाय शुल्क लगाया जाना जनहित में होगा, रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 3.1 में निहित है जिसमें नीचे दिए गए अनुसार उल्लेख है:

“सदस्य पूर्व में स्थापित और गैर 1994 के अनुच्छेद X के अनुरूप सार्वजनिक किया गया, के अनुसरण में उस सदस्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जांच का पालन करने के बाद ही रक्षोपाय शुल्क लगा सकते हैं। इस जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों को तर्कसंगत आम नोटिस और आम सुनवाई तथा अन्य उपर्युक्त माध्यम शामिल होंगे जिनमें आयात, निर्यातिक और अन्य हितबद्ध पक्षकार साक्ष्य और अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकते हैं जिसमें अन्य पक्षकारों की प्रस्तुतियों का उत्तर देने तथा अन्य बातों के साथ-साथ इस तथ्य के संबंध में कि क्या रक्षोपाय शुल्क को लागू करना जनहित में होगा अथवा नहीं, के संबंध में अवसर दिया जाना शामिल है। सक्षम प्राधिकारी तथ्य और कानून के सभी संगत मुद्दों पर तार्किक रूप से निकाले गए निष्कर्षों और जांच परिणामों का उल्लेख करने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।”

52.2 यद्यपि सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ब और सीमा प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आंकलन) नियमावली, 1997 जनहित की जांच करने पर विचार नहीं करता है, महानिदेशक (रक्षोपाय) ने रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 3.1 के संबंध में निश्चयात्मक रक्षोपाय शुल्क लगाने की सिफारिश करने के पूर्व सतत रूप से जनहित का मूल्यांकन किया है।

52.3 वर्तमान मामले में, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग जांच की अवधि में विशेष रूप से 2018-19 और 2019-20 की पहली तिमाही में आयातों में तीव्र वृद्धि के कारण गंभीर क्षति का सामना कर रहा है। अत्यधिक प्रौद्योगिकी और निवेश गहन क्षेत्र होने के कारण घरेलू उद्योग को संरक्षण की आवश्यकता है।

इसके अलावा, हितबद्ध पक्षकारों में से एक पक्षकार ने यह उल्लेख किया है कि रक्षोपाय शुल्क जनहित में नहीं होगा क्योंकि यह प्रयोक्ता उद्योग को प्रभावित करेगा। यह नोट किया जाता है कि एसएमओएफ केवल आप्टिकल केबल के निर्माण के लिए एक इनपुट है जिसका आगे उपयोग दूरसंचार कंपनियों द्वारा किया जाता है। जनहित का मूल्यांकन करने के दायित्व में आवश्यक रूप से विभिन्न स्टेक होल्डरों पर सिफारिश किए गए रक्षोपाय शुल्क का संभावित प्रभाव अपेक्षित है। इस कारण से मूल्य श्रृंखला के भागीदारों के संबंध में उसकी जांच करना अपेक्षित है।

52.4 मैं नोट करता हूँ कि 1-7-2019 से विचाराधीन उत्पाद पर मूल सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। यह वृद्धि जांच की अवधि जिसके दौरान बढ़े हुए आयातों का विश्लेषण जिसके कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है, करने के लिए किया गया है, उसके समाप्त होने के तत्काल बाद है।

जांच की अवधि की बाद की अवधि के दौरान, आयातों में स्वतंत्र रूप में बहुत हद तक गिरावट आई है यद्यपि वे घरेलू उद्योग के उत्पादन के प्रतिशत के रूप में सापेक्ष रूप में 2016-17 और 2017-18 से तुलनीय स्तर पर है। 2019-20 अर्थात् जांच की अवधि के बाद की अवधि की दूसरी और तीसरी तिमाही में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव नहीं पड़ा है यद्यपि कीमत पर दबाव देखा गया है। जैसाकि रक्षोपाय शुल्क में होता है, आयातों में और न कि आयात की कीमतों में वृद्धि हुई जो सबसे महत्वपूर्ण है, सिफारिश किया गया रक्षोपाय शुल्क आयात में तीव्र वृद्धि के कारण आवश्यकरूप से क्षति की सीमा का समानुपातिक होना चाहिए। जैसाकि ऊपर में उल्लेख किया गया है, घरेलू उद्योग को विभिन्न व्यापार कार्य-पद्धतियों के कारण क्षति उठानी पड़ सकती है जिसमें पाठन, सब्सिडी अथवा आयातों में तीव्र वृद्धि शामिल हो सकती है।

52.5 इस कारण से सभी उपर्युक्त दृष्टिकोणों के आधार पर, उपर्युक्त मात्रा और अवधि के साथ रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश की गई है जो बाद के अनुच्छेदों दो प्रतिस्पर्धी चिंताओं में संतुलन बनाएगा।

### 53. निष्कर्ष

53.1 जांच की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग के कार्य-चालन में समग्र गिरावट आई है जो भविष्य में गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे का द्योतक है। घरेलू उद्योग को विचाराधीन उत्पाद के बढ़े हुए आयातों के कारण हुई गंभीर क्षति के मानदंड-वार निष्कर्ष का सारांश नीचे दिए गए अनुसार है:

- क) विचाराधीन उत्पाद के आयातों की मात्रा में जांच की अवधि के दौरान मुख्य रूप से 2018-19 में और 2019-20 की पहली तिमाही के दौरान बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है।
- ख) 2019-20 की दूसरी और तीसरी तिमाही में आयात उत्पादन के सापेक्ष 2016-17 और 2017-18 के तुलनीय स्तर पर है।
- ग) घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है जबकि आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है।
- घ) विचाराधीन उत्पाद के बढ़े हुए आयातों ने घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से का स्थान ले लिया है।
- ड.) क्षमता के उपयोग में जांच की अवधि में मांग में वृद्धि के बावजूद काफी हद तक कमी आई है।
- च) घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में सबसे हाल की अवधि के दौरान बहुत अधिक हद तक गिरावट आई है और उनके खोए हुए बाजार का स्थान आयातों के द्वारा ले लिया गया है।
- छ) घरेलू उद्योग 2017-18 में लाभ अर्जित कर रहा था और इसे 2018-19 तथा जांच की अवधि की बाद की अवधि के दौरान बहुत अधिक हानि हुई है।
- ज) विचाराधीन उत्पाद की मालसूची में काफी हद तक वृद्धि हुई है।
- झ) विचाराधीन उत्पाद के आयातों के कारण कम कीमत पर बिक्री और कीमत में ह्रास हुआ है।
- ट) समग्र आधार पर, घरेलू उद्योग को बढ़े हुए आयातों के कारण जांच की अवधि के दौरान गंभीर क्षति उठानी पड़ी है।

### (च) विकासशील देश

54. सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ख(1) के परंतुक में यह प्रावधान है कि जब तक विकासशील देश के आयात का हिस्सा उस वस्तु के कुल आयातों का 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होता हो तब तक उस देश के मूल की वस्तु पर रक्षोपाय शुल्क नहीं लगाया जाएगा अथवा जहां वस्तु का मूल देश एक से अधिक विकासशील देश हो तब वहां इस प्रकार के सभी विकासशील देशों से आयातों के सकल योग जिसमें प्रत्येक देश का 3 प्रतिशत से कम आयात हिस्से को एकसाथ लिया गया हो, उस वस्तु के कुल आयातों का 9 प्रतिशत से अधिक नहीं हो, उस पर रक्षोपाय शुल्क नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा, दिनांक 5 फरवरी, 2016 की अधिसूचना सं. 19/2016-सीमा(एनटी), इस प्रावधान के उद्देश्य से विकासशील देशों का उल्लेख करता है। वर्तमान मामले में जांच की अवधि की सबसे अधिक हाल की अवधि के दौरान उपलब्ध आंकड़ों के प्रति उक्त अधिसूचना के साथ पठित इस कानूनी प्रावधान को लागू करने पर, यह नोट किया जाता है कि भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातों के रूप में, चीन जन.गण. से आयात उस देश विशिष्ट के आधार पर 3 प्रतिशत से अधिक है जबकि प्रत्येक अन्य विकासशील देश का हिस्सा अलग-अलग देश के रूप में 3 प्रतिशत से कम है। चूंकि सबसे अधिक हाल की अवधि के आंकड़ों पर विचार किया गया है, अतः घरेलू उद्योग का इंडोनेशिया द्वारा 3 प्रतिशत के मानदंड को पूरा न करने के कारण विचार करने का दावा न्यायोचित नहीं है और इस पर विचार नहीं किया गया है। इसके साथ ही, विकासशील देशों जिसका अलग-अलग हिस्सा 3 प्रतिशत से कम है, का सामूहिक हिस्सा, भारत ने विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातों का 9 प्रतिशत से अधिक नहीं है। इस कारण से यह माना गया है कि विकासशील देशों (चीन जन.गण. को छोड़कर) के मूल के विचाराधीन उत्पाद के आयात पर सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ख(1) के संबंध में रक्षोपाय शुल्क नहीं लगेगा।

## 55. (छ) सिफारिशें

55.1 उपर्युक्त विश्लेषण को देखते हुए, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि;

- i. विचाराधीन उत्पाद अर्थात् “सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर” का आयात भारत में इस प्रकार की बढ़ी हुई मात्राओं में और ऐसी परिस्थितियों में किया जा रहा है जिससे समान अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी उत्पादों का निर्माण करने वाली घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होगी अथवा होने का खतरा होगा।
- ii. इसके अलावा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि घरेलू उद्योग को आगे गंभीर क्षति, जिसे ठीक करना मुश्किल हो सकता है, से संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से रक्षोपाय शुल्क लगाने को मौजूदा परिस्थितियां न्यायोचित ठहराती हैं।

55.2 तदनुसार, निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं:

- i. इस पर विचार करते हुए कि बीसीटी को दिनांक 1-7-2019 को 5 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है और जांच की अवधि की बाद की अवधि में आयातों में सभी स्टेक होल्डरों के प्रतिस्पर्धी हितों पर विचार करने के बाद उपर्युक्त माने गए अनुसार लाभ एवं लागत के आधार पर परिकलित घरेलू शुल्क की भारित औसत उचित विक्री कीमत (एफएसपी) में कटौती की गई है। एफएसपी की तुलना सबसे हाल की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के आयातों के पहुंच मूल्य से की गई है जिसके फलस्वरूप \*\*\* प्रतिशत की क्षति मार्जिन हुई है।
- ii. सभी परिस्थितियों और गंभीर क्षति की सीमा पर विचार करते हुए, 10 प्रतिशत का रक्षोपाय शुल्क नीचे दिए गए उपबंध (iii) में दर्शाए गए विकासशील देशों को छोड़कर सभी देशों से सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की सीमा प्रशुल्क मद 9001 10 00 के अंतर्गत आने वाले विचाराधीन उत्पाद अर्थात् “सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर” के आयातों पर सीआईएफ कीमत पर यथा मूल्य लगाए जाने का प्रस्ताव है। इसमें उल्लिखित प्रशुल्क मद सांकेतिक मात्र है और आयात की गई वस्तुओं का विवरण रक्षोपाय शुल्क की प्रयोज्यता का निर्धारण करेगा।
- iii. चूंकि चीन जन.गण को छोड़कर दिनांक 5 फरवरी, 2016 की अधिसूचना सं. 19/2016-सीमा शुल्क (एनटी) में सूचीबद्ध विकासशील देशों से आयात अलग-अलग रूप में 3 प्रतिशत और सामूहिक रूप से 9 प्रतिशत से अधिक नहीं है अतः ऐसे विकासशील देशों (चीन जन.गण. को छोड़कर) के मूल के “सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर” के आयातों पर सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख(1) के पहले परन्तुक के संबंध में रक्षोपाय शुल्क नहीं लगेगा।
- iv. उक्त उत्पाद के आयात पर रक्षोपाय शुल्क, जिसका उल्लेख ऊपर में किया गया है, को एक वर्ष की अवधि के लिए लगाए जाने का प्रस्ताव किया जाता है। चूंकि रक्षोपाय शुल्क को केवल एक वर्ष के लिए लगाए जाने का प्रस्ताव किया जाता है अतः किसी प्रगामी उदारीकरण की सिफारिश नहीं की जाती है।
- v. इन जांच परिणामों के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले आदेशों के विरुद्ध अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

विद्युत बिहारी स्वैन, विशेष सचिव एवं महानिदेशक (रक्षोपाय)

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(Directorate General of Trade Remedies)****NOTIFICATION**New Delhi, the 21<sup>st</sup> August, 2020**Case No. (SG) 05/2019**

**Subject: Safeguard investigation concerning imports of “Single Mode Optical fibre” in to India - Final Findings – Proceedings under Customs Tariff Act, 1975 and the Custom Tariff (identification and Assessment of Safeguard) Rules, 1997- Reg.**

**F. No. 22/5/2019-DGTR.—A. Introduction**

1. An application dated 18.07.2019 has been filed before the Director General (Safeguard) under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 (hereinafter also referred to as the “said Rules”) by M/s Sterlite Technologies Limited (‘STL’) and M/s Birla Furukawa Fibre Optics Private Limited (‘BFL’) (hereinafter also referred to as the “Applicants”) in terms of Section 8B of Customs Tariff Act, 1975 (for brevity, “the Act”) read with Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 (for brevity, “the Rules”), seeking imposition of Safeguard Duty on imports of “Single Mode Optical Fibre” (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or “PUC”) into India to safeguard the Domestic Industry (‘DI’) of like or, directly competitive products from serious injury or threat of serious injury caused by increased imports. The applicants have submitted that imports of subject goods has increased significantly in 2018-19 and has continued to be at increased levels in the most recent period, i.e. January’ 2019 to June’ 2019. The applicants have claimed that they are not able to compete with the imports and regain their market share, thereby forcing them to close down or keep part of their production facilities idle, and requested for imposition of provisional Safeguard Duty to mitigate their injury. The Authority also issued Preliminary Findings dated 6<sup>th</sup> November, 2019 which was not notified by the Central Government.

**B. Procedure Followed**

2. An examination of the application and the evidence/details/documents submitted therewith led to the conclusion that the application satisfies the requirements of Rule 5 of the said Rules. Therefore, a Safeguard investigation against imports of the PUC into India was initiated vide notification published in the Gazette of India, Extraordinary dated 23.09.2019 vide GSR No.293 (E).
3. In accordance with sub-rules (2) and (3) of Rule 6 of the said Rules, a copy of the initiation notification dated 23.09.2019 and a copy of a Non-confidential Version (NCV) of the application filed by the Domestic Industry were forwarded to the Central Government in the Ministry of Commerce & Industry and Ministry of Finance, the Governments of major exporting countries through their Embassies in India, and the interested parties mentioned in the said application. Further, the questionnaire to be answered by the exporters / importers / domestic producers, as prescribed under Rule 6(4) of the said Rules, was forwarded to the known interested parties with a request to make their views known in writing within 30 days from the date of issue of the NOI.
4. In the meantime, the request made by the Applicants for imposition of provisional safeguard duty was examined and it was *prima facie* found that there existed critical circumstances wherein delay in imposition of Provisional Safeguard duty would cause irreparable damage to the domestic industry. The submissions of other interested parties filed till date was also taken into consideration.
5. Accordingly, the Preliminary Findings for Provisional safeguard duty was issued under Rule 9 (2) of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 on 6<sup>th</sup> November, 2019 and was published in the Gazette of India on the same day. However, the recommended Provisional Safeguard duty was not been notified by the Central Government.
6. Subsequently, on the request made by some of the interested parties, the time limit for filing Questionnaire Response was extended till 15<sup>th</sup> November, 2019. The submissions and questionnaire responses were received from the following interested parties:
- i. Corning Technologies India Pvt. Ltd.
  - ii. Corning Finolex Optical Fibre Pvt. Ltd.
  - iii. Finolex Cable Ltd.

- iv. HFCL Ltd., India
- v. WestcoastOptilinks
- vi. Fibrehome India Pvt. Ltd.
- vii. Sumitomo Electric Industries Ltd. ('SEI'), Japan
- viii. SWCC Showa Cable Systems Co. Ltd., Japan
- ix. Fujikura Ltd., Japan
- x. Pt. ZTT Cable, Indonesia
- xi. Pt. Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk, Indonesia
- xii. Pt. Voksel Electric Tbk., Indonesia
- xiii. Pt. Yangtze Optical Fibre, Indonesia
- xiv. Pt. Communication Cable Systems, Indonesia

7. In addition to the above, Paramount Cables Limited, Orient Cables India Pvt. Ltd. and Om Optel Industries Pvt. Ltd had also filed their submissions subsequently after the expiry of the extended time period. However the same submissions were given by them during the first oral hearing. The submissions made by all interested parties either in public hearing or otherwise have been appropriately examined and addressed under relevant paras. As many issues are repetitive, they have been collectively addressed.

8. In view of the travel restrictions imposed because of Covid-19 pandemic and consequent lockdown, the Public hearing was held through Digital Video Conferencing on 12.05.2020. In the meantime there was a change in Director General (Safeguards), therefore, a second Public hearing was held by the present Director General through Digital Video Conference on 17.07.2020.

9. During both the public hearings, the interested parties, along with the Domestic Industry were given adequate opportunity to make their oral submissions. In terms of sub rule (6) of rule 6 of the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, all the interested parties who participated in the public hearing were requested to file written submission of the views presented orally.

10. Copies of written submissions filed subsequent to both the Public hearings by the domestic Industry as also other interested parties were made available to all the interested parties. Interested parties were also given an opportunity to file rejoinders, if any, to the written submissions of other interested parties.

11. All the views expressed by the interested parties in their written submissions, pursuant to the public hearings held on 12.05.2020 and 17.07.2020 were examined and have been taken into account in making appropriate determination. The non-confidential version of the information received or acquired has been kept in the public file. Thereafter, rejoinders to the written submissions filed subsequent to both hearings by DI and other interested parties were also considered.

12. The desk verification of the data submitted by the DI was carried out through digital video conferencing wherein DI shared their system's screen displaying relevant data for verification.

#### **Post initiation submissions**

13. The submissions received in response to the initiation notice but prior to the Public Hearing are summarized as under:

##### **13.1 Finolex Cables Ltd.**

Finolex Cables Ltd. is one of the six producers of PUC in India. They have supported the DI's petition for levy of safeguard duty on imports of PUC into India. They have submitted their Products, Sales, Capacity utilization and Inventory information for the POI. Accordingly, they have claimed that the sudden surge in imports have caused and is threatening to cause serious injury to domestic producers.

##### **13.2 Corning Technologies India Pvt. Ltd. and Corning Finolex Optical Fibre Pvt. Ltd.**

13.2.1 Technologies India Pvt. Ltd. is a producer of PUC in India and Corning Finolex Optical Fibre Pvt. Ltd. is a joint venture between Corning SAS and Finolex Cables Ltd., engaged in sales of products manufactured by Corning Technologies India Pvt. Ltd. (hereinafter collectively referred to as "Corning"). Corning has supported the petition filed by the domestic industry for levy of safeguard duty.

- 13.2.2 They have submitted that the recent, sudden, significant, and sharp increase in imports has caused and is threatening to cause serious injury to domestic producers. It was also submitted that they have faced significant price depression and price suppression, particularly in January – June' 2019, due to low priced imports.
- 13.2.3 Corning has not been able maintain its Selling price commensurately with the change in cost of sales during the POI.
- 13.2.4 They had also shared the concern raised by Domestic industry that the actual price of imported goods is significantly lower than the prices reflected in import statistics, on account of considerable post-invoicing discounts given by exporters.
- 13.2.5 They have also submitted that the following “unforeseen developments” have led to sudden surge in imports:
  - a. Decline in demand in the Chinese Optical Fibre market
  - b. Anti-dumping duty imposed by China PR on optical fibre imported from US and Japan
  - c. Global overcapacity
  - d. Investment in Optical Fibre preform
  - e. Tariff imposed by US on optical fibre imports from China

### **13.3 HFCL Ltd.**

They are one of the importers of PUC in India. They have mainly objected to the inclusion of grades other than grade G652 under the scope of PUC. It has been submitted by them that Indian demand is primarily of Non dispersion Shifted Fibre i.e. G 652 grade. Fibre Cable and other products manufactured using grades other than G652 are majorly exported out of India rather than being used in India because of lack of demand and market. Thus, there is no adverse impact on the domestic industry from imports of grades other than G652, therefore, all such grades should be excluded from the scope of Product under investigation.

### **13.4 Government of Mexico**

There has not been any imports of PUC from Mexico to India during January 1, 2016 to June 30, 2019. Therefore, in terms of Article 9.1 of the Agreement on Safeguards of the World Trade Organization and due to the fact that Mexico is a developing country member of the WTO, the exports of PUC from Mexico to India should be excluded from the purview of any safeguard measure derived from the present investigation.

## **14. Post preliminary findings submissions**

The following submissions have been received from interested parties after issuance of Preliminary findings:

### **14.1 Sumitomo Electric Industries Ltd., Japan**

14.1.1 There are no critical circumstances warranting imposition of Preliminary Safeguard Duty. They have submitted that while there was a surge in imports in Quarter 2' 2018-19, the imports thereafter have substantially declined.

14.1.2 The computation of profit and loss of DI has been made by comparing cost of sales of Domestic Industry with the selling price to independent customer. Exclusion of selling price to related/captive parties has distorted the figures.

14.1.3 Annualised data for January – June' 2019 cannot be used for analysis of injury parameters in absence of any explanation of the need for such annualisation. In this regard, they have placed reliance on the findings of Panel in *India- Steel Safeguards*.

14.1.4 Insufficiency in showing increased imports, as imports from all countries including Japan does not show an increasing trend. The injury, if any, being caused to the Domestic industry is only on account of surge in imports from China.

14.1.5 It is submitted that exclusion of imports of only STL (DI) on account of being imported under advance licensing scheme is unfair in data analysis as a similar exclusion should have been done for all the import of the PUC undertaken under advance licensing scheme.

14.1.6 Analysis of the DI's data does not indicate existence of serious injury. Further analysis carried out after excluding captive/related party sales does not give the correct picture of the condition of the domestic industry.

14.1.7 Further, it was submitted that the increase in imports was not on account of any "unforeseen developments", as such the requirement of Article XIX of GATT is not met in the present case.

- a. In this regard, it has submitted that global overcapacity should have resulted in the PUC being imported in increased quantity from all sources. However, in the present case the majority of imports (approx. 84%) has come from China and imports from other countries such as Japan is minor (8% in 2018-19).
- b. Imposition of trade remedies by China should have resulted in increased imports from those countries.
- c. It is undisputed that low priced imports of the PUC from China PR have led to price undercutting in India. In this light, they have submitted that the only source of injury, albeit not 'serious injury', to the DI is on account of low priced imports from China.

14.1.8 DI is suffering from an unfair trade practice like low priced imports from China, and therefore the remedy lies under the anti-dumping provisions and not safeguard provisions. Accordingly, the present investigations ought to be terminated in terms of paragraph 2 of Annexure to the said Rules.

14.1.9 The DI has failed to make a claim with respect of the "obligation incurred under GATT 1994" as required under Article XIX, in their petition and moreover, even in the preliminary findings there has been no analysis on this issue.

14.1.10 The exporter has further claimed that grade G654 should be excluded from the scope of PUC as it is not produced by the Domestic Industry.

14.1.11 Grades G652, G655 and G657 manufactured by the Exporter should also be excluded as there is significant difference between the products manufactured by the DI and those of SEI, in terms of quality, time delivery, customer support and packaging etc.

14.1.12 DI has claimed excessive confidentiality without giving any meaningful summarization of various factors in their Petition.

#### **14.2 Paramount Cable Limited, Orient Cable Industries Ltd. and Om Optel Industries Pvt. Ltd.**

14.2.1 Even though the aforesaid parties have not registered as "interested parties" during the extended time limited provided, their submissions have been taken on record for consideration.

14.2.2 The said parties are importers of the subject goods. They have objected to the initiation of the investigation, and have submitted that no injury has been caused to the domestic producers of PUC.

14.2.3 It has been submitted by them that all Indian producers of PUC, other than STL, merely convert imported Preform into Optical Fibre and therefore, they cannot be considered as a manufacturing industry.

14.2.4 Imposition of Safeguard duty would result in significant increase in prices of PUC, thereby forcing MSME Cabling industry to closure.

14.2.5 Further, imposition of Safeguard duty on Optical Fibre would result in significant increase in import Optical Fibre Cable, leading to closure of cable manufacturing units who would not be able to compete with imports.

14.2.6 Imports of the DI has substantially increased in 2018-19 as compared to the previous years. The claims made by STL that imports made by them are of grades which are not ordinarily manufactured by them appears to be false. The DI be put on strict proof of their claims regarding imports made by them.

#### **14.3 Opti Fibre Systems JSC, Russia**

14.3.1 They are the sole producers of Optical Fibre in Russian Federation with an installed capacity of about 7-8% of India's total installed capacity. As such, their sales to India is insignificant.

14.3.2 Thus, imports from Russian Federation has never caused any damage to Indian producers, as such, no Safeguard duty should be levied on exports from Russian Federation.

**15. Written submissions filed post Public hearing held on 12.05.2020****15.1 Domestic Industry- STL and BFL**

15.1.1 The Product under consideration ('PUC') is "Single Mode Optical Fibre" ('SMOF'), classifiable under CTH 9001 1000. The product and its grades are defined in terms of the International Telecommunication Union (ITU-T) standards. These products are used for manufacturing Optical Fibre Cable, which are primarily used in telecommunication operations, CATV, FTTH etc. There is a complete substitutability between the domestic and imported products. The product manufactured by the Domestic industry is technically and commercially identical to the product being imported. The Petitioners, being the producers of a major share (approximately 60%) of the total production of the "like article" in India, qualifies as "domestic industry".

15.1.2 More than 95% of the Indian demand is of G652 grade fibre. From the data for 2018-19, it can be seen that 97% of both imports as well as domestic sales of the DI constituted of G652 fibre, and the remaining 3% was of other grades. Therefore, as the grade mix of the domestic product is identical to the grade mix of imported products, there is no need for grade wise analysis in a Safeguard Investigation. In this context, they had placed reliance on the Appellate Body findings in *Argentina Footwear and European Commission Regulation in Safeguard investigation concerning Certain Steel products*.

15.1.3 They have also submitted that the DI has the technology and capacity to manufacture all grades of SMOF. G-654 grade is neither imported into India nor sold by domestic industry, as there is no demand for the said product in India. Therefore, the exclusion of G-654 from the scope of PUC is not warranted. In this context, they have relied on the Final Findings issued in the *Anti-Dumping Duty investigation in respect of import of Synchronous Digital Hierarchy Transmission Equipment (SDH Equipment)*, originating in or exported from the People's Republic of China PR and Israel, dated 12.01.2012, wherein it was held that a claim for exclusion of a particular type cannot be entertained unless the same has been exported to India during the relevant period.

15.1.4 The imports of subject goods into India have significantly increased in 2018-19 as compared to 2016-17 and 2017-18. As compared to base year, there has been a 271% increase in 2018-19. They have further submitted that even from the quarter on quarter analysis, it is evident that imports in each quarter of 2018-19 and Quarter 1 of 2019-20 were significantly higher than previous years' quarters of 2016-17 and 2017-18.

15.1.5 Further, it has been submitted that under Section 8B (1) and Article XIX of GATT, read with jurisprudence laid down by Panel in *US- Line Pipe and US- Steel Safeguards*, amongst others, it is evident that the requirement of law is of "increased imports" and not of "increasing imports", therefore, a decline at the end of POI does not undo the previous increase.

15.1.6 Domestic industry is suffering serious injury caused by the sudden increase in imports. All the relevant parameters as mentioned in Annexure to the Rules show a considerable decline in the condition of the Domestic industry. The period of such decline directly coincides with the period of surge in imports. As such the requirement of serious injury and causation is met in the present case.

15.1.7 Further, the DI has submitted that a confluence of several unforeseen developments that has occurred over past years, particularly 2016-17 and 2017-18, has led to a significant surge in imports to India. These factors include global over-capacity built in Fibre industry because of delay in planned 5G rollouts, slower digitization, lower than expected demand in Chinese market, setting up of new drawing facilities in various nations which were earlier import dependent, imposition of trade measures by China against most of the Fibre manufacturing countries, policy restrictions imposed by countries like USA, Australia etc. on import of telecom equipment/components from China and other non-fiscal/ non – regulatory restrictions imposed by major telecom operators (especially telecom operators in western Europe and USA) against China made Fibre, which have resulted in sudden diversion of imports to India.

15.1.8 As regards decline in imports in post POI period, it has been submitted that the law requires the Authority to examine "increased imports" only with reference to the Period of Investigation and not for a period thereafter. However, without prejudice to the above, it has also been submitted that if there is any decline in imports, it has to be examined whether the decline in imports, if any, is a temporary phenomenon or not (*Ref- Appellate Body in Argentina Footwear and Panel in Dominican Republic-Tubular bags & polypropylene bags*).

15.1.9 Since decline in imports in Quarter 2 of 2019-20 was because of temporary decline in Indian demand caused by troubled telecom sector, exceptionally heavy monsoon, liquidity crunch being faced by PSUs, delay in announcement of Bharatnet projects etc, therefore, it should not be taken in consideration for examining "increased imports". Further, the decline in imports in Quarter 3 of 2019-20 as compared to Quarter 2 is mainly on account of domestic sales substituting imports, as the importers wanted to avoid

running the risk of 25% Provisional Safeguard duty. However, such sales had to be made at a price comparable to the import prices, consequently, the injury of Domestic industry has further accentuated during the post POI period. Almost all the parameters of serious injury has further deteriorated in the post POI period and the domestic industry is on the brink of closure.

15.1.10 It has further been submitted thatinspite of decline in imports in Quarter 2 of 2019-20, the imports have continued to be at a significantly high levels in 2019-20 (annualized on basis of Q1 and Q2' 19-20) as compared to base year, in absolute terms as well as relative to domestic production. Further, on standalone basis also, the increase in imports relative to domestic production has remained at significantly high level in Quarter 2' 2019-20, as compared to 2016-17 and 2017-18 levels. Thus, the imports have continued to be at increased level even in Quarter 2' 2019-20.

15.1.11 It was also submitted that the present case is not fit for anti-dumping duty, as there is no evidence of imports coming at dumped prices during the POI. Further, the prices from all major exporting nations are in the same range, with Japan being lower than China. Moreover, most of SMOF manufacturers have a presence, either through fully owned plants or through JVs, in various countries. Therefore, imposition of country specific ADD would not give adequate protection to the Domestic Industry.

15.1.12 The imposition of duties is in Public interest, as without such protection DI would not be able to survive. Further, in Petitioners' opinion the impact of duties on Telecom operators (user industry) is less than 1% of their cost. Even the cablers would be able to pass on the impact of duties to Telecom operators, as Cable prices are always driven by Fibre prices. Moreover having a dependable domestic industry is in larger interest of the user industry, that is, the cable industry and also the telecom service providers.

15.1.13 They have therefore requested for immediate imposition of safeguard duty to the full extent of injury margin, for preventing or remedying serious injury and to facilitate positive adjustment.

## **15.2 Corning Technologies India Pvt. Ltd and Corning Finolex Optical Fibre Private Limited (“Corning”)**

### **15.2.1 Increase in imports in absolute terms**

- a. Total imports of SMOF have increased significantly by more than five times in 2018-19 as compared to 2016-17 and are continuing to come at an increasing level thereafter.
- b. Imports of SMOF after excluding imports made by domestic industry have also increased by more than 3 times during 2018-19 and January to June 2019 (Annualised) as compared to 2016-17.

### **15.2.2 Increase in imports in relative terms**

- a. Relative to domestic production, imports of the PUC (excluding domestic industry imports) have consistently increased during 2016-17 to January- June 2019 and has more than tripled from the base year
- b. Share of imports (excluding domestic industry imports) in Indian demand has also increased by five times in 2018-19 as compared to 2016-17 and has continued to increase thereafter.

### **15.2.3 Increase in imports during POI period**

- a. The decline in imports in the post POI period is not relevant for assessment of increase in imports.
- b. WTO Panel in *US-Line Pipe (Safeguard)*case noted that “recent” increase in imports does not mean that it must continue up to the period immediately preceding the investigating authority's determination, nor up to the very end of the period of investigation.

### **15.2.4 Unforeseen developments**

Tariff imposed by the United States, decline in demand in China, installation of pre-form capacity etc. are unforeseen circumstance that have led to overcapacity in China PR and consequent increase in imports into India.

### **15.2.5 Serious Injury**

- a. There is decline in market share, sales, production, productivity, capacity utilization, profitability, and employment during the period of investigation
- b. Both, domestic industry and Corning are experiencing price pressure due to decline in landed value of imports. Domestic selling price of corning as declined by 22 index points in last six

months of the POI. Domestic producers are not able to maintain selling price commensurately with the change in cost of sales.

#### **15.2.6 Causal link between increased imports and serious injury**

Decline in performance of domestic industry directly coincides with the period in which there was sudden and significant surge in imports. Other factors such as decline in consumption, export performance, technology advancement etc. have not caused injury to domestic industry.

#### **15.3 HFCL Ltd.**

15.3.1 The definition of Product under Consideration as provided in the initiation notification dated 23.09.2019 has covered certain type of optical fibre with their respective codes in the definition of PUC. However, some of these types of optical fibre and more specifically dispersion shifted fibre (G.653), Cut-off shifted single mode optical fibre (G.654), Non Zero Dispersion Shifted Fibre (G.655 & G.656) and Bend insensitive Single Mode Fibre (G.657 A1 & A2) have almost negligible import into India.

15.3.2 It can be further verified that optical fibre cables & other products manufactured by using optical fibre other than Non-dispersion shifted Fibre (G.652) are majorly exported out of India rather than being used in Indian domestic market due to lack of demand and market in India. Therefore, there is no adverse impact on the domestic industry from imports of optical fibre other than Non-dispersion shifted Fibre (G.652).

15.3.3 DI has not even provided any details or bifurcation (grade wise) of their production, sales, exports etc. of their PUC, which is required to be examined by the Authority.

15.3.4 The prices of these grades i.e. dispersion shifted fibre (G.653), Cut-off shifted single mode optical fibre (G.654), Non Zero Dispersion Shifted Fibre (G.655 & G.656) and Bend insensitive Single Mode Fibre (G.657 A1 & A2) is significantly higher than that of G.652. All these grades cannot be compared and treated to be one and the same.

15.3.5 In this context, they have submitted that even for the “Bharatnet Projects”, BSNL, BBNL, Railways, PGCIL, Railtel & other PSUs specifies use of G652 D fibres only. Therefore, other grades of PUC should be excluded from the definition of PUC. They have alleged that the domestic industry wants to create its monopoly by including all types of fibre in PUC.

#### **15.4 Sumitomo Electric Industries Ltd., Japan**

15.4.1 The injury, if any, to the DI is only on account of high-volume of imports from China PR along with price injury, therefore, the appropriate forum to address such injury is through an antidumping investigation as opposed to a safeguards investigation which affects imports from all countries. Thus, the present investigations be terminated.

15.4.2 The DI has failed to bring forth “unforeseen developments” leading to surge in imports, if any. None of the reasons cited by DI in its petition as constituting ‘unforeseen circumstances’ are addressed specifically towards the import of the PUC in the subject investigation. Rather, the DI has alleged a surge in the broad category of ‘optic fibre’. It is submitted that a mere allegation of some unexpected developments in the broad category of the entire ‘optic fibre industry’ is not sufficient to demonstrate a logical link between unforeseen developments and surge in imports of PUC into India.

15.4.3 Analysis of DGCI&S import data for PUC does show a recent, sudden, sharp and significant increase in imports, warranting imposition of Safeguard duty. From import data it is evident that there is no increasing trend of import of the PUC throughout the POI and even on an end-to end analysis, the import volumes have declined significantly.

15.4.4 They have also submitted that import figure for Quarter 1' 2019-20 is incorrect.

15.4.5 Further, as significant time has lapsed since the initiation of the present safeguard investigation and also the identified ‘most recent period’ in the initiation notification, an analysis of data for the Post POI data is warranted in the present case. In this respect, it must be noted that as per the data for Q2 and Q3 of FY 2019-20, the imports of the PUC have declined significantly.

15.4.6 Furthermore, if the import volumes were to be analysed on an end to end basis, it is amply clear that imports have declined from 769 KFKM in Q1 of 2017-18 to 273 KFKM in Q3 of 2019-20, a difference of 496 KFKM.

15.4.7 The overall analysis of the economic and performance parameters shows that the data provide by the DI with respect to its performance and the examination conducted by the Hon'ble DA is neither adequate nor sufficient; and moreover, is based on incorrect figures. Thus, the data provided and relied

upon with respect to the claim of the DI and the preliminary findings thereby of serious injury being caused to the DI does not show a true picture of the domestic market situation with respect to the PUC.

15.4.8 Further, in light of the limited data available in public domain concerning the economic and performance parameters of the DI, these parameters have shown significant improvement. Thus, any claims of injury hinging on analysis of such parameters may kindly be rejected by the Hon'ble DA.

15.4.9 The DI has failed to provide a viable adjustment plan which is an important requirement under the Indian Safeguard laws. The applicants have claimed excessive confidentiality on the entire adjustment plan without providing even a meaningful non-confidential version of the same. They have not provided any good cause with respect to their claims for confidentiality.

15.4.10 Product grade G.654 should be excluded from the scope of PUC in the present investigation, as the same is not manufactured by the DI neither does it have the capability to do so.

15.4.11 Further, product grades G.652.D, G.655 and G.657.A1 should also be excluded from the scope of PUC in the present investigation as there are significant differences with respect to physical properties, consumer preference, quality etc. between the PUC exported by SEI and the product manufactured by the DI.

15.4.12 It was further submitted that, since imports under the Advance Authorization Scheme do not compete with the domestic products, as they are directed towards the export market; and cause no injury to the domestic industry, they should be excluded from the import analysis in the present investigation.

15.4.13 The DI has failed in establishing a causal link between increased imports of PUC and the injury suffered by the DI therefrom.

15.4.14 Lastly, it has been submitted that the DI has failed to demonstrate that imposition of Safeguard duty is in "public interest" as envisaged under Article 3 of the Agreement on Safeguard.

#### **15.5 Fibrehome India Pvt. Ltd.**

15.5.1 They have submitted that the DI has *prima facie* failed to identify "unforeseen developments" that have led to the increased imports of PUC into India. As such, the requirement of Article XIX of GATT is not met in present case.

15.5.2 Further, it has been submitted that as safeguard measure are based on a "no fault principle", therefore recourse to them should be taken only when there is a very strong case on merits and there is no other alternative available.

15.5.3 The standalone financials of STL suggest that they have earned high profits during the POI, therefore, the data submitted by them in the Petition appears to be manipulated.

15.5.4 The domestic production of DI would have grown substantially, had they not imported huge quantities themselves. Thus, the injury, if any, faced by the DI cannot be attributed to independent imports.

15.5.5 The total imports in the most recent period, i.e. Jan- June' 2019 has declined, as such the requirement of increased imports is not met.

15.5.6 The DI has failed to give a viable adjustment plan. In absence of an adjustment plan, the safeguard investigation are required to be terminated. In this regard, reference has been made to the decision of *United Phosphorous v. Director General (Safeguards)*, 2000 (118) E.L.T. 326 (Del.),as well as Final Findings issued by DG Safeguards in application filed by United Phosphorous in 1999.

15.5.7 It was also submitted that the imposition of Safeguard duty in the present case would be against the Public interest, as it will inevitably lead to loss of employment and economic activity in the country, and would also encourage imports of Optical Fibre Cable.

#### **15.6 Paramount Wires and Cables Limited**

They reiterated their submissions made vide letter dated 20.01.2020, which has been discussed above.

#### **15.7 Government of Indonesia, Government of Brazil and Government of Taiwan**

15.7.1 The Government of Indonesia, Government of Brazil and Government of Taiwan have requested for adherence to Article 9.1 of the Agreement on Safeguard, which provides for exclusion of Developing country from where imports are below *de-minimis level*.

15.7.2 It has been submitted that since imports from the aforesaid countries is below 3%, no Safeguard duty should be recommended on their exports of PUC to India.

### **15.8 Government of Russian Federation**

15.8.1 The requirements for proving serious injury under Safeguard investigation is much stricter than that of Anti-dumping investigation. Safeguard measures to be imposed only in special circumstances.

15.8.2 Exports from Russia accounts for 0.2% of total imports of PUC in India, as such no injury is likely to be caused to Domestic producers by imports from Russia.

### **15.9 Government of Japan**

15.9.1 In view of the Penal/AB reports in DS 98 and DS 252, it is imperative for the Authority to determine the ‘unforeseen developments’ that resulted in increased imports and then serious injury to the domestic producers by changing competitive relationship between imported and domestic products.

15.9.2 Global overcapacity is mere a result of long term demand and supply condition and cannot necessarily be regarded as “unforeseen”. Further, imposing import restrictive measure to counteract import restrictive measures imposed by other countries would distort global trade.

15.9.3 Government of India has failed to establish relationship of increased imports with a specific “obligation incurred under GATT”.

15.9.4 As maximum imports of PUC to India are from China, Government of India should clearly confirm the scope of product, whose imports are causing serious injury to Indian domestic producers. Further, as imports are coming from select few countries, it has to be seen if Safeguard measure would be most appropriate.

15.9.5 Imposing Safeguard measures would frustrate India’s digital infrastructure developments projects, as such duties would not be in national interest.

16. The summary of relevant issues filed in the rejoinders by the interested parties to the written submissions of other interested parties filed subsequent to public hearing held on 12.05.2020, areas under:

### **16.1 Domestic Industry – STL and BFL**

#### **16.1.1 Decline in imports in post POI period**

- a. The requirement under Section 8B and the Article XIX of GATT is of “increased imports” and not of “increasing imports”. Thus, every decrease in imports does not prevent determination of “increased imports”, if it can be established that despite the decrease, the imports continue to be at “increased level” as compared to previous year or the base year.
- b. Further, analysis of “increased imports” has to be made for the sufficiently long Period of Investigation (‘POI’), as defined at the time of initiation of the investigation, so as to even out temporary variations and seasonal declines. Analysis of data for a short period post POI would not allow an objective evaluation of “increased imports” as required under law.
- c. The imports in Quarter 2’ 2019-20 (i.e. Post POI) have continued to be at increased levels. Even on standalone basis, imports as a % of production in Quarter 2’ 19-20 was 186% of 2016-17 and 162% of 17-18 level. Therefore, the requirement of “increased imports” is satisfied even in the Post POI period.
- d. The temporary decline in imports in Quarter 2 of 19-20 as compared to Quarter 1 was on account of a temporary contraction of demand for the product caused by certain market factor. It is a trite law that temporary decline and variations in market should not be taken in consideration, while evaluating ‘increased imports’.
- e. In Quarter 3 of 2019-20, the present investigations were initiated and Preliminary findings were issued, thereby distorting the domestic market. Consequently, the domestic industry was able substitute the imports in Quarter 3. However, such sales were made at a price comparable to import prices, therefore, sales realization was very low, accentuating the DI’s serious injury.
- f. It was therefore submitted that the import data for the period post POI cannot be taken into consideration for determining “increased imports”. Without prejudice, even if the same is taken in consideration, with the imports continuing to be at “increased level”, a determination of “increased imports” is required to be made.

#### **16.1.2 Exclusion of certain grades from the scope of PUC**

- a. As regards submissions made for exclusion of certain grade, the DI has submitted that under Safeguard law there is no requirement for carrying out grade-wise analysis, especially in cases where grade mix of imported product is similar to the grade mix of domestic products. (Ref- Appellate

**Body in Argentina Footwear and European Commission regulation in Safeguard investigation concerning imports of certain Steel products)**

- b. In the present case, approximately 95-97% of Indian demand is of G652 grade and 5-3% is of other grades such as G657, G655 etc. The analysis of 2018-19 import data shows that the grade mix of imported products is identical to the grade mix of domestic products. Therefore, there is no requirement for carrying out grade-wise analysis in the present case.
- c. As regards exclusion of Grade G654, it has been submitted that DI has the technology and capacity to manufacture G654 grade. However, as there is no commercial demand of the said grade in India, the same has neither been produced nor imported into India. When the said grade has not been imported into India the question of non-availability of like product, on the ground that DI has not produced the said grade, does not arise.
- d. Further, as the grades of PUC are partially interchangeable and have similar end uses, exclusion of few grades without any cogent reason would defeat the entire purpose of the duty, if imposed. Moreover, all the grades of PUC are visibly identical, are sold through similar channels, have same set of producers/customers and are classifiable under the same CTH 9001 1000. As such, exclusion of grades may lead to circumvention of any safeguard duty that may be imposed.

**16.1.3 Recourse under Anti-dumping measure instead of Safeguard measure**

- a. The import prices from all the major exporting countries have been in the same range during 2018-19 as well as Jan- June' 2019. As such the allegation that injury to domestic industry is on account of low priced imports from China is unfounded. Further, no evidence has been produced by any of the interested parties to show that the imports from China were at dumped prices.
- b. Further the averment that there is increase in imports from China only is incorrect, as analysis of import data clearly shows that imports from several other countries, including USA, Korea, Indonesia etc. had increased during 2018-19 as compared to base year.
- c. Moreover, as most of the SMOF producing companies have a global presence either through fully owned plants or through Joint Ventures in various countries, there is a very high probability that the companies in order to avoid levy of any country specific duty, start exporting through their entities in other jurisdiction.
- d. As Anti-dumping duty is imposed against “dumped imports” and not against “Cheap imports” or “increased imports”, it has been submitted that Anti-dumping duty is not viable option in the present circumstances.

**16.1.4 Unforeseen Developments**

It has been submitted that confluence of various factors has led to the unexpected increase in imports to India. Some of these factors are as below:

- a. Global overcapacity caused by delay in announced 5G roll out plans, slower than expected FTTH deployment and slow paced digitization along with significant decline in Chinese demand, which consumes more than 50% of global SMOF,
- b. Imposition of trade barriers by many countries on import of PUC, thereby changing the dynamics of global trade of PUC
- c. Various non- regulatory/ non -fiscal barriers imposed by telecom operators in most of the western countries putting stringent barriers on entry of Chinese fibre

**16.1.5** The DI has also submitted that a detailed adjustment plan along with expected year wise saving has been provided in the Petition. It may be noted that SMOF industry is a technology intensive industry. Since, the Adjustment plan relates to development of proprietary technology and process/methods which would lead to better utilization of raw material/resources, the Petitioners have claimed confidentiality over it.

**16.1.6** As regards reference made to STL's published financials/balance sheet or statements made at Company level, it has been submitted that along with PUC i.e. Optical Fibre Unit, STL has various other business units such as Optical Fibre Cable, Copper Cable, Services, Software etc. The Company's financials relates to all such business units and therefore same is beyond the scope of present investigation.

16.1.7 As regards the claim that Safeguard duty being a “no fault duty”, the Petitioners have submitted that agreeably, Safeguard duties are “no fault duty” and therefore, are not “punitive measures”. They are imposed only to the extent necessary to prevent or remedy serious injury and to facilitate Domestic producers to adjust to import competition.

### **16.2 Fibrehome India Pvt. Ltd.**

16.2.1 The claim of DI as regards surge in imports and serious injury is unfounded, as is evident from the analysis of data submitted in the Petition.

16.2.2 Further, the imports have declined by about 89% from QII of 2018-19 (2797) to QIII of 2019-20 (305) which is a significant decline. When the imports have declined by 89% between QII of 2018-19 and QIII of 2019-20 which is the most recent period covering the POI, it is totally incorrect to say there was some surge in imports.

16.2.3 The DI has failed to establish serious injury, threat of serious injury or any causal link between injury being faced by them and the imports. As such pre-requisites for imposition of Safeguard duty are not fulfilled in the present case.

16.2.4 As regards submissions that imports in Post POI period is not to be taken in consideration, it is submitted that DI cannot be permitted to selectively rely upon Post POI data for certain parameters and disregard it for others.

16.2.5 Further, the admission of the DI that there was decline in imports coupled with decline in demand, means any temporary correction in performance based on fall in demand cannot be fixed by putting safeguard duties.

### **16.3 Sumitomo Electric Limited, Japan**

16.3.1 As regards submissions made on exclusion of certain grades, it was submitted that as admittedly DI has not produced G654 during the POI, the same has to be excluded from the scope of PUC.

16.3.2 As regards DI’s reliance on Appellate Body report in *Argentine Footwear* on the aspect of desegregated analysis, it was submitted the Appellate Body’s decision was based on the fact that in the said case definition of PUC was not challenged. However, since in the present case, the exporter has questioned the definition of PUC, the reasoning of Appellate Body is not applicable in the present case.

16.3.3 Further, in response to DI’s claim that it has not manufactured this grade because of no demand in India, they have submitted evidence of a contract entered by BSNL with NEC Technologies India Pvt. Ltd. (‘NECTI’) to design, engineer, supply, install, test and implement an optical submarine cable system between Chennai in mainland India and the Andaman and Nicobar Islands.

16.3.4 It was further submitted that the submissions made by DI in respect of temporary decline in imports in Post POI are factually incorrect, as the telecom operators have been in massive stress even prior to Q2 of 2019-20. Further, the report on prolonged monsoon referred to by the DI is only in respect of North eastern states, which accounts for a very minuscule share of Indian market of PUC.

16.3.5 DI has failed to show “unforeseen developments” which has resulted in increase in imports. Reliance of CRU reports specifically relating to decline in demand in China further proves that increase in imports is only from China and not from other countries.

16.3.6 Levy of duty would not be in Public interest as it will adversely impact the user- i.e. the cable manufacturing industry.

17. Thereafter, on account of change in the Director General, the present Director General held a Second Public Hearing on 17.07.2020, wherein Domestic Industry as well as other interested parties made their oral submissions. Subsequently, terms of sub rule (6) of rule 6 of the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, all the interested parties who participated in the public hearing were requested to file written submission of the views presented orally. A summary of the submissions made by the DI And other interested parties is reproduced herein below. As most of the submissions made during the first hearing have been reiterated, for sake of brevity, the same are not being reproduced herein below. A summary of the additional submissions made subsequent to the second hearing are as below:

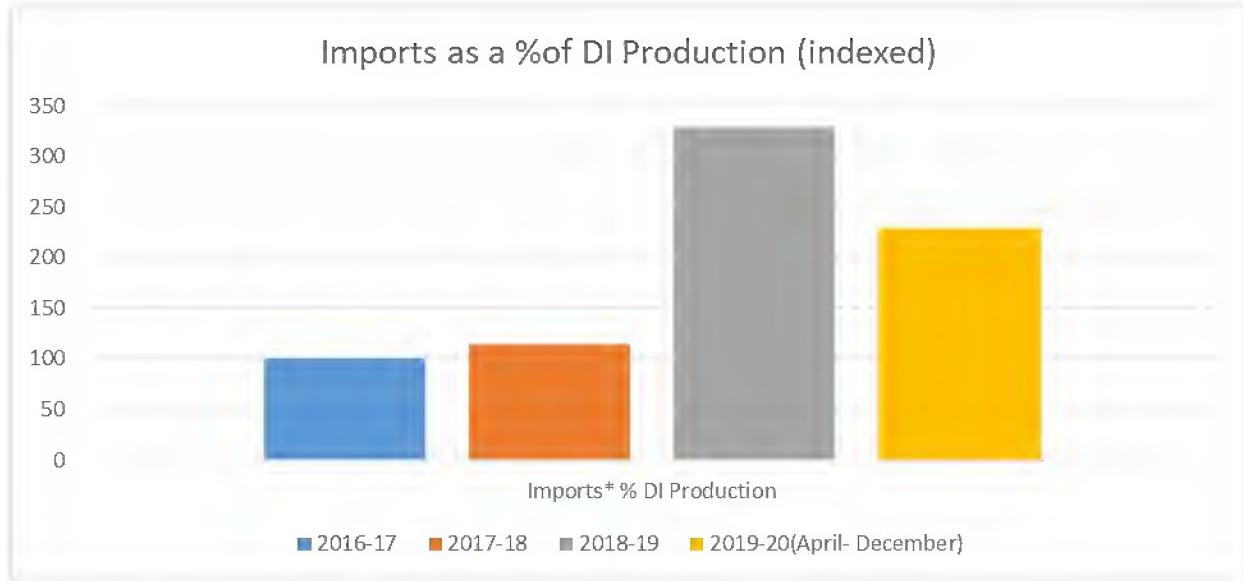
### **17.1 Domestic Industry – STL- BFL**

17.1.1 The Domestic Industry reiterated their earlier submissions *inter alia* in respect of increased imports, serious injury, threat of serious injury, unforeseen developments, public interest.

17.1.2 It was additionally submitted that the imports in relation to Domestic Production has significantly increased in 2018-19 as also the most recent period i.e. January’ 2019 to June’ 2019.

17.1.3 Further, the Domestic industry submitted that the imports as a % of DI production have increased in Post Period of Investigation period as well. It was submitted that the imports in relation to production in Quarter 2' 2019 was \*\*\*% of 2016-17 level and \*\*\*% of 2017-18 level.

17.1.4 Further, the imports in relation to DI production in 2019-20 (April- December' 2019) has continued to be significantly high, and the sharp increase in 2018-19, has not been out done by the decline in 2019-20, which is evident from the below graph:



17.1.5 It has further been submitted that Rule 2(c) of the Safeguard Rules, define "increased quantity" to include increase in imports whether in absolute terms or relative to domestic production. In this regard, they have referred to the Final Findings dated 11.03.2014 issued in investigations concerning imports of **Tubes, Pipes and Hollow Profiles, Seamless of iron, alloy or non-alloy steel**, wherein it was held as under:

#### **"26. Increased Imports:**

*Section 8B of Customs Tariff Act, 1975 deals with the power of the Central Government to impose safeguard duty and provides as follows:*

*"(1) If the Central Government, after conducting such enquiry as it deems fit, is satisfied that any article is imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threatening to cause serious injury to Domestic Industry, then, it may, by notification in the Official Gazette, impose a safeguard duty on that article ."*

*Further, Rule 2 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 defines 'increased quantity' as follows:*

*"Increased quantity" includes increase in imports whether in absolute terms or relative to domestic production."*

*From the above, it is seen that law i.e. Section 8B and the Rules mandate increase in imports as a basic prerequisite for the application of a safeguard measure. Thus, to determine whether imports of the product under consideration have "increased in such quantities" for purposes of applying a safeguard measure, the rules require an analysis of the increase in imports, in absolute terms or in relation to domestic production. It is also seen the expression "increased quantity" has been defined in inclusive terms and the definition includes two parameters i.e. increase of imports in absolute terms and increase of imports in relative terms to domestic production. It is also seen that both these parameters need not exist together. The increased quantity is to be measured either in absolute terms or in relative to domestic production. The satisfaction/existence of one parameter is sufficient to fulfill the legal requirement."*

17.1.6 The Domestic Industry has submitted that in any case, in terms of Appellate Body decision in **Argentina – Footwear**, temporary decline in imports has to be excluded from consideration while determining "increased import". The imports in the Post POI period has gone down on account of temporary decline in domestic demand, caused because of precarious condition of telecom industry, delay in some of the Bharatnet projects, unprecedented rainfall in Quarter 2' 2019-20 etc. However, the current market trends indicate that the demand is likely to increase in near future.

17.1.7 The Domestic industry has also submitted their adjustment plan which they intend to implement to become more competitive to imports. They have submitted that through the various projects being

undertaken by them, they estimate that the cost of production would decrease on account of improved yield from raw material and through reducing their dependence upon imported raw material.

17.1.8 The imports from Indonesia has increased substantially during the Post POI period, being 7% of total imports in Quarter 2' 2019-20. They have further submitted that some of the major Chinese SMOF manufacturing companies, such as ZTE and YOFC, have set up their SMOF Draw plants in Indonesia, and are now routing their exports to India, through Indonesia. They have further submitted that from Quarter 2' 2019-20 onwards, the imports from China attract levy of 15%, whereas the imports from Indonesia attract Nil BCD on account of ASEAN FTA.

## 17.2 Government of Japan, Indonesia, Brazil, Russian Federation and Taiwan

17.2.1 The aforesaid governments through their embassies have reiterated their earlier submissions which have already been reproduced in above.

## 17.3 Government of UAE

17.3.1 The Government of UAE has requested that it may be recognized as a “Developing country” for the purpose of the present investigation. Accordingly, exports from UAE being less than 3% of the total imports into India, UAE be excluded from the purview of any Safeguard duty that may be imposed.

### 17.4 Sumitomo Electric Industries Ltd., Japan

17.4.1 SEI Ltd. has submitted that the injury, if any, to the DI is only on account of high-volume of imports from China PR along with price injury. Therefore, the appropriate forum to address such injury is through an antidumping investigation as opposed to a safeguards investigation which affects imports from all countries and the present investigation deserves to be terminated.

17.4.2 None of the reasons cited by DI in its petition as constituting ‘unforeseen circumstances’ are addressed specifically towards the import of the PUC in the subject investigation. Rather, the DI has alleged a surge in the broad category of ‘optic fibre’. It has been submitted that a mere allegation of some unexpected developments in the broad category of the entire ‘optic fibre industry’ is not sufficient to demonstrate a logical link between unforeseen developments and surge in imports of PUC into India.

17.4.3 For a positive finding necessitating the imposition of a safeguard duty there should be a finding of imports in such increased quantity. Such increase in quantity of imports in a safeguard investigation should be recent, sudden, sharp and significant enough to cause or threaten to cause serious injury. The DGCI&S import data for PUC does not the same and rather establishes that there is no increasing trend of import of the PUC throughout the POI and even on an end-to end analysis, the import volumes have declined significantly.

17.4.4 As per the quarter-wise data provided by the DI, the import volume of non-DI imports of PUC for Q1 of 2019-20 has been reported as 1678 KFKM. However, as per the DGCI&S import data obtained by the respondent, the import volume for total imports of PUC, i.e. inclusive of DI imports, is 1527 KFKM. Thus, the DI appears to be attempting to mislead the Hon’ble DG in the present investigation

17.4.5 The imports in Q2 and Q3 of FY 2019-20 have declined significantly. The imports of PUC have declined from 1527 KFKM in Q1 of 2019-20 to 273 KFKM in Q3 of 2019-20 alone, which is a significant difference of 1254 KFKM.

17.4.6 Furthermore, if the import volumes were to be analysed on an end to end basis, it is amply clear that imports have declined from 769 KFKM in Q1 of 2017-18 to 273 KFKM in Q3 of 2019-20, a difference of 496 KFKM.

17.4.7 The overall analysis of the economic and performance parameters shows that the data provide by the DI with respect to its performance and the examination conducted by the Hon’ble DG is neither adequate nor sufficient; and moreover, is based on incorrect figures. Thus, the data provided and relied upon with respect to the claim of the DI and the preliminary findings thereby of serious injury being caused to the DI does not show a true picture of the domestic market situation with respect to the PUC.

17.4.8 Further, in light of the limited data available to respondent concerning the economic and performance parameters of the DI, these parameters have shown significant improvement. Thus, any claims of injury hinging on analysis of such parameters may kindly be rejected by the Hon’ble DG.

17.4.9 The presence of a viable adjustment plan is an important requirement under the Indian Safeguard laws. The applicants have claimed excessive confidentiality on the entire adjustment plan without providing even a meaningful non-confidential version of the same. They have not provided any good cause with respect to their claims for confidentiality.

17.4.10 They have requested for exclusion of product grade G.654 from the scope of PUC in the present investigation, as the same is not manufactured by the DI neither does it have the capability to do so.

17.4.11 Further, they have requested to exclude the product grades G.652.D, G.655 and G.657.A1 from the scope of PUC as there are significant differences with respect to physical properties, consumer preference, quality etc. between the PUC exported by SEI and the product manufactured by the DI

17.4.12 They have further requested that, since imports under the Advance Authorization Scheme do not compete with the domestic products, as they are directed towards the export market; and cause no injury to the domestic industry, they may be exclude all the imports made under Advance Authorization scheme from the import analysis in the present investigation.

17.4.13 Furthermore, the Domestic industry has failed to establish a causal link between increased imports of PUC and the injury suffered by the DI therefrom.

17.4.14 The DI has failed to make any argument regarding the safeguard duty being in public interest and therefore deserves to be terminated.

### **17.5 HFCL Ltd.**

17.5.1 The importer has submitted that the Indian demand majorly constitute of G652 Fibre. Other specialized Single Mode Optical Fibreviz. Dispersion shifted Fibre (G 653), Cut-off Shifted Fibre (G.654), Non Zero Dispersion Shifted Fibre (G.655 and G.656) and Bend insensitive SMOF (G657 A1 and A2), have a negligible domestic market in India, which is evident from their negligible imports and DI's domestic sales. As such, such specialized grade should be excluded from the purview of the present investigation.

17.5.2 The DI has not submitted a non-confidential version of the adjustment plan. As such, the interested parties are not in a position to comment on the viability of their adjustment plan.

17.5.3 During the on-going pandemic, due to decline in imports, the Domestic Industry has been able to capture the domestic demand, as such no further protection is warranted.

### **17.6 Fibrehome India Pvt. Ltd.**

17.6.1 They have reiterated their earlier submissions *interaliaapropos* absence of increased imports, serious injury, adjustment plan, unforeseen developments and public interest. They have submitted that the increase in imports and injury to the Domestic industry, if any, is primarily on account of their own imports and is therefore, self-inflicted. As such, it has been submitted that the requisites for imposition of Safeguard Duty are not met in the present case.

## **18. Rejoinder Submissions filed subsequent to second Public hearing held on 17.07.2020**

The summary of rejoinder submissions filed by the Domestic industry as also other interested parties are as below. As some of the submissions are repetitive, only the new/additional submissions made in the second rejoinder submissions have been summarized below:

### **18.1 Domestic Industry – STL- BFL**

18.1.1 The Domestic industry has reiterated their submissions in respect of increased imports, injury on account of dumping of goods from China, serious injury, imports under Advance License etc.

18.1.2 In addition, they have denied the allegation of SEI Ltd. in their written submissions that the DI during the second public hearing has accepted that G 654 grade was imported into during the POI. It has been submitted by them that there were no imports of grade G654 into India. However, it was only in response to the exporter's oral submission that the said grade was imported into India, that they have, without prejudice, submitted that even if such import was there, it must not have been any commercial/noticeable quantity. They maintain their categorical stand that said grade has not been imported into India during the POI.

18.1.3 As regards reference made by SEI to the contract between BSNL with NEC Technologies India Pvt. Ltd. ('NECTI'), the Domestic Industry has submitted that the said contract is for Optical Fibre Cable and not for the PUC, as such Safeguard duty would not apply to imports made under the said contact. Without prejudice, they have further submitted that the quantity of Fibre consumed in these cables is minuscule, i.e. around 18KFKM, as such, said imports cannot be considered as commercial imports of G 654 grade in India.

18.1.4 They further submitted that the given the proprietary nature of the research project undertaken by them, the adjustment plan has been kept confidential.

18.1.5 They have submitted that the submissions made by exporters in respect of “increase in imports” is factually and legally incorrect. The imports have continued to be at increased levels in absolute terms as well as relative to domestic production. The submission of the SEI Ltd., that the Appellate body in US-Steel Safeguards has held that “*an examination of surge in imports must demonstrate a clear and uninterrupted upward trend in import volumes*”, is not only incorrect representation of law but a deliberate fabrication of facts as the said sentence quoted by the exporter is not present anywhere in the said report.

### **18.2 Government of Indonesia**

18.2.1 The Government of Indonesia has denied the claim that imports from Indonesia in the post POI period has increased. It has been submitted that in the whole year of 2019 imports from Indonesia have accounted for only 0.14% out of India’s total import from the world. They have further submitted that the Petitioners has incorrectly submitted that import from Indonesia during period of July 2019 - June 2020 accounted for 11% share. It has been submitted that even the whole year of 2019 and 2020 combined only resulted in the amount of 0.2% by volume of India’s import of SMOF from Indonesia.

18.2.2 They have further submitted that the Applicants’ submission that China’s investment in Indonesia would be able to cause export route from China to India via Indonesia is very much exaggerated. Investment of SMOF factories in Indonesia, therefore, should be viewed as there is a sizeable demand in Indonesia which enables investment of SMOF factories took place in the country.

### **18.3 Sumitomo Electric Industries Ltd., Japan**

18.3.1 SEI Ltd. has reiterated its submissions *inter alia* in respect of absence of increased imports, serious injury, causal link, unforeseen development, public interest and adjustment plan. It has submitted that in absence of any evidence of increased imports and serious injury, imposition of Safeguard duty is not warranted.

18.3.2 As regards exclusion of certain grades from the scope of PUC, it has submitted that certain grades as manufactured by SEI are either not manufactured by the DI or are not like or domestically competitive to the DI manufactured products. It is also pertinent to mention herein that each grade of SMOF has a separate end use and are not substitutable or interchangeable. Therefore, such grades require exclusion from the scope of PUC in the present investigation.

18.3.3 The DI has not manufactured and sold G.654 grade of SMOF in the domestic market during the POI, hence, it should be excluded from the scope of PUC in the present investigation. It has further submitted that grades G.652, G.655 and G.657 should also be excluded as these grades manufactured and sold by SEI are different from those manufactured by Domestic Industry on account of the difference in the physical characteristics, customer preference, quality, etc. Further, as each of these grades are different and cannot be substituted with other grades, there is no basis to include these grades, i.e. G.652, G.654, G.655 and G.657, as manufactured by SEI within the scope of the PUC.

18.3.4 DI’s claim that it has the technology to manufacture G.654 fibre is not substantiated by the evidence provided in the petition. The 2012 news report relied upon by the DI does not certify the capabilities of the joint venture Birla Furukawa Fibre Optics Ltd., which is one of the constituents of DI in the present investigation, to manufacture G.654 fibre; but rather that of the Furukawa Electric Group, Japan.

18.3.5 DI’s claim that there is no demand for G.654 in India is incorrect. It should be noted that G.654 is used in the manufacture of submarine cables. As per news article referred in the submission above, BSNL entered into a contract with NECTI to design, engineer, supply, install, test and implement an optical submarine cable system between Chennai in mainland India and the Andaman and Nicobar Islands. Further, as the project was expected to be complete in 2020, it implies the same had been imported to India during POI.

### **18.4 Fibrehome India Pvt. Ltd.**

18.4.1 They have reiterated their earlier submissions *inter alia* in respect of absence of increased imports, serious injury, unforeseen developments, adjustment plan and public interest.

18.4.2 In respect of the claim of the Domestic Industry on threat of serious injury on account of declining prices in China, as evident from China Mobile’s tender in July, 2020, which closed at around Rs. 200/FKM, it was submitted that the said claim is without any basis. The price in India will not be influenced by the said deal and Indian industry is doing well even when the Chinese prices are on the lower side.

18.4.3 The concerns of the Domestic industry appear to be on account of fall in demand, as such imposition of Safeguard duty will not serve any purpose.

### C. EXAMINATION & FINDINGS OF DIRECTOR GENERAL (SAFEGUARDS)

19. Based on the submissions made by various interested parties in response to Initiation, preliminary finding and Public hearing, various primary and secondary records available, Domestic verification was through undertaken DVC, I have examined concerns on various aspects and record my final findings as under:

20. Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 deals with imposition of safeguard duty on imports. Its sub-section (1) provides for imposition of safeguard measures by the Central Government on an article if the article is being imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threaten to cause serious injury to the Domestic Industry.

21. The Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 provide the manner and principles governing investigation.

22. The investigation has been conducted in accordance with the said rules and the final findings are recorded through this notification.

#### a) The Product under Consideration (PUC)

23. In the Notice of Initiation and Preliminary Findings, the Product under consideration has been defined as "Single-mode Optical Fibre" ("SMOF"). SMOF refers to the Optical Fibre which facilitates transmission of a single spatial mode of light as a carrier and is used for signal transmissions within certain bands. The standardized single mode optical Fibre types include the Non-dispersion shifted Fibre (G.652), Dispersion shifted Fibre (G.653), Cut-off shifted single mode optical Fibre (G.654), and Non Zero Dispersion Shifted Fibres (G.655 & G.656) as well as Bend insensitive single mode Fibre (G.657) - as defined by International Telecommunication Union (ITU-T), which is a global standardization body for telecommunication systems and vendors.

24. Single-mode Optical Fibre is used for manufacture of Optical Fibre Cables, including Uni-tube and Multi tube stranded cables, tight buffer cables, Armoured and Un-armoured cables, ADSS & Fig-8 cables, Ribbon cables, Wet core and Dry core cables and etc. Single-mode Optical Fibre is mainly applied to high-data rate, long distance and access network transportation, therefore, is mainly used in long-haul, metro area network, CATV, optical access network (for example FTTH) and even over short distance networks as applicable. Major consumption is driven by 3G/4G/5G rollout by Telco's, Connectivity of Gram Panchayat, Defence (NFS Project) and Data centres.

25. The product concerned is classifiable under Customs Tariff heading 9001 10 00 of the Second Schedule of the Customs Tariff Act, 1975. The customs classification be taken as indicative only, and is not binding on the scope of the product.

26. Some of the interested parties have requested for exclusion of certain grades/types of SMOF from the scope of PUC, which has been considered. It is seen from the submissions made as well as analysis of import and domestic industry's data that the Indian demand is majorly of G.652 grade. However, most of the other grades have also been imported into India as well as sold by the Domestic Industry in the same proportion. It is observed that the grade mix of imported products is similar to that of domestic products. Further, these grades are partially interchangeable and have similar uses. As such there is no justifiable reason to exclude any such grade from the scope of PUC.

27. One of the interested parties, SEI Ltd., Japan has claimed that the grades G652, G655 and G 657 manufactured and sold by SEI are different from those manufactured by Domestic Industry on account of the difference in the physical characteristics, customer preference, quality, etc. In this regard, it is noted that the grades of SMOF are defined by the International Telecommunication Union (ITU-T), which are universally accepted. Further, it has been submitted by the Domestic Industry that their goods compete with those manufactured by SEI Ltd. not only in domestic market but also in international market. It is also not the case of the concerned exporter that grades manufactured by the Domestic industry do not confirm to the technical specification provided by the ITU-T, or that such specifications are vague or incorrect. Thus, in absence of any credible evidence to substantiate SEI Ltd.'s claim that there is any difference or any instance of customer preference in respect of goods manufactured by them over those manufactured by the domestic industry, their argument for exclusion of these grades cannot be accepted.

28. Further, another interested party, HFCL Ltd., has submitted that the Indian demand is primarily of Non dispersion shifter Fibre Grade 652. There is a negligible demand for other grades of SMOF such as G654, G655 and G657 in India market, which is evident from import data as well as domestic sales of the Applicants. In this regard, Domestic Industry has submitted that about 97% of the total imports as well as domestic Sales of the DI in 2018-19 were of G.652 grade fibre. The other grades of SMOF formed only about 3% of the Indian demand. It has

been submitted by them that as grade mix of the imported product is identical to those of domestic sales of the Applicants, the grade –wise analysis is not required in the present case.

29. In this context, the Domestic Industry has submitted the decision of Appellate Body in *Argentina – Footwear* wherein it was held that a disaggregated analysis is not required to be done in a Safeguard duty investigation. The relevant para of the Appellate Body report is reproduced herein below:

“(a) *Product segments*

1.1 *Regarding Argentina's segmentation of footwear into five product groups in its investigation (performance sports footwear, non-performance sports footwear, exclusively women's footwear, town and/or casual footwear, and other) (paras. 8.112), the European Communities argues that having adopted this segmented approach, Argentina was obliged to follow it consistently through its injury analysis and to prove serious injury in all segments in which safeguards were to be imposed. The European Communities claims that "serious injury" was not proven in any of the selected five segments, and that Argentina merely used data of one or another sector as it considered appropriate for its purpose. The European Communities argues in particular that factors relating to import trends, market share, profits and losses and employment were not investigated for each market segment. At the same time, however, the European Communities states that it does not challenge Argentina's definition of a single category of like or directly competitive products, namely all footwear.*

1.2 *Argentina responds that the European Communities is confusing the CNCE's injury analysis of the whole of the footwear industry with the product categories that the CNCE used in the questionnaires for purposes of collecting pertinent information. In Argentina's view, a single "like or directly competitive" product and a single national industry are at issue in this case because there is sufficient elasticity of substitution on the supply and demand sides between all different segments of one single footwear market. Therefore, Argentina argues, the CNCE conducted an injury analysis regarding the footwear industry in its entirety. Consequently, there was no need for a disaggregated consideration of all the different injury factors with respect to the five product categories.*

1.3 *We disagree with the European Communities that Argentina was required to conduct its injury and causation analysis on a disaggregated basis. In our view, since in this case the definition of the like or directly competitive product is not challenged, it is this definition that controls the definition of the "domestic industry" in the sense of Article 4.1(c) as well as the manner in which the data must be analysed in an investigation. While Argentina could have considered the data on a disaggregated basis (and in fact did so in some instances), in our view, it was not required to do so. Rather, given the undisputed definition of the like or directly competitive product as all footwear, Argentina was required at a minimum to consider each injury factor with respect to all footwear.<sup>[1]</sup> By the same token the European Communities, having accepted Argentina's aggregate like product definition, has no basis to insist on a disaggregated analysis in which injury and causation must be proven with respect to each individual product segment.<sup>[2]</sup> Thus, in our review of the injury finding, we will consider the analysis and conclusions pertaining to the footwear industry in its entirety.”* **(emphasis added)**

30. The Authority has defined PUC comprising of various grades as defined in para 2 initiation notification dated 23<sup>rd</sup> September 2019. From the above cited jurisprudence, it is evident that in a Safeguard investigation, analysis of Product as such has to be made, and not of product segments. Further, Grade wise analysis becomes extraneous when the product basket of the imported products is similar to those sold by the Domestic industry. An analysis of the import data as well as the domestic sales of DI shows that the grade mix of the products in both cases is identical. Thus, there is no justification for analyzing imports and serious injury parameters for each grade separately. Therefore, I do not consider it appropriate to consider the contention of some of the interested parties regarding exclusion of grades other than Non-dispersion shifted Fibre (G.652) such as G655, G657 etc.

31. As regards submissions made for exclusion of Grade G654 on the ground that it has not been manufactured by the Domestic Industry during the period of investigation, it is noted that the said grade has neither been manufactured by Domestic Industry nor imported into India during the Period of investigation. The domestic industry has placed evidence on record to show that it has the capacity to manufacture said grade in India. It is their submission that as there is no demand for the said grade in India, the same has neither been imported nor sold by domestic industry.

32. From the data available on record, it is observed that there is no import of grade G654 into India during the POI. The reference made by SEI Ltd. to the contract between BSNL and with NEC Technologies India Pvt. Ltd. ('NECTI') in their rejoinder submissions, *prima facie* appears to be a contract for "Optical Fibre Cables" and not for "SMOF". In this regard, Domestic Industry has submitted that the said contract is for Optical Fibre Cable and not for the PUC, as such Safeguard duty would not apply to imports made under the said contact. They have further submitted that the quantity of Fibre consumed in these cables is minuscule, i.e. around 18 KFKM. It is felt that exclusion of said grade on the ground of non-availability of 'like product' being manufactured by Domestic industry cannot be sustained when there is no demand for such grade in India. The Directorate has been considering to exclude such grades from the scope of PUC which have been imported into India but for which there is no "like product" being manufactured by Domestic Industry. However, no such exclusion can be justified when such grade has not been imported into India during the POI since fact of capability of domestic industry supplying this cannot be established. In Final Findings issued in *Anti-Dumping Duty investigation in respect of import of Synchronous Digital Hierarchy Transmission Equipment (SDH Equipment)*, originating in or exported from the People's Republic of China PR and Israel, dated 12.01.2012, the Authority had refused to exclude a particular type of product from the scope of PUC as the same has not been exported to India during the relevant period. The relevant para is reproduced below:

"...The Authority observes that a claim for exclusion of a particular type can not be entertained unless the same has been exported to India during the relevant period, as the fact of non supply of like article by the domestic industry cannot be established unless the type is exported to India and is permitted to be used in India. The Authority holds that no grounds have been made out justifying exclusion of STM-256.

33. Thus, on examination of information available on record, submissions made by interested parties as well as settled practice in respect of scope of PUC, it is noted that the exclusion of grades/types of PUC, as claimed by some of the interested parties, is not justified in the present case.

#### (b) Domestic Industry (DI)

34. Clause (b) of sub-section (11) of Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975, as amended by Finance Act, 2020, defines Domestic Industry, as follows:

- '(b) "Domestic industry" means the producers –
- i. as a whole of the like article or a directly competitive article in India; or
  - ii. whose collective output of the like article or a directly competitive article in India constitutes a major share of the total production of the said article in India.'

The applicants have claimed that their collective production accounts for more than 50% of the total production of the PUC in India and thus represent a major share of the total Indian production of the PUC and may be treated as the Domestic Industry as given in the table below:

| KFKM  | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | Jan to June 2019 | Jan to June 2019<br>(Annul.) |
|---|---------|---------|---------|------------------|------------------------------|
| <b>Total Indian Production</b>                | ***     | ***     | ***     | ***              | ***                          |
| <b>Trend</b>                                  | 100     | 112     | 118     | 105              | 105                          |
| <b>DI Production as % of Total Production</b> | ***     | ***     | ***     | ***              | ***                          |

35. The applicants have also claimed that they do not have access to production data of other Domestic manufacturers. However, all domestic manufacturers, other than STL, produce PUC from imported preform (which cannot be used for any other known purpose). Accordingly, estimate of total industry production has been made by them adopting the standard industry norm that 37 FKM Fibre can be manufactured from 1 Kg of Preform with ~90% After-Draw-Yield. Thus, on an average, it has been assumed by the Applicants in their application that 1 Kg of Preform will yield 33.3 FKM of Fibre. Accordingly, the Applicants have computed the total Indian Production by applying the aforesaid conversion ratio to the Preform import data obtained from Cybex Exim Solutions Pvt. Ltd. ("CESPL", for brevity) after excluding Preform imports by the Applicants.

36. Subsequently, the Director General has received letter dated 30.09.2019 from M/s Finolex Cable Ltd. ('Finolex', for brevity), who is also a domestic producer of the PUC, supporting initiation of investigation and requesting for imposition of provisional duties. They have also submitted their production, capacity, sales and inventory information for 2016-17 to 2018-19 and April 2019 to September 2019. Thereafter, another domestic producer, i.e. Corning Technologies India Pvt. Ltd. had also filed its letter dated 5<sup>th</sup> November, 2019 in support of the Petition. Thus, 4 out of 6 Domestic producers have supported the petition.

37. On the basis of information available on record along with the fact that none of the interested parties have objected to or produced any evidence to refute the claim of the Applicants regarding their share in total production of PUC or their standing as Domestic Industry, I hold that the production of the applicants constitutes a major share of the total production of the said products in India, and are considered as Domestic Industry in terms of clause (b) of sub-section (6) of Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975.

38. Some of the interested parties stated that STL, one of the constituents of the Domestic Industry, is itself an importer of the PUC, as such cannot be considered as Domestic Industry. In this regard, it is noted that unlike laws relating to Anti-dumping which specifically provide for exclusion of importers from the purview of Domestic industry, no such exclusion has been provided under the Customs Tariff Act, 1975 or Safeguard Rules made thereunder. As such, for the purpose of determining standing of Domestic Industry, the fact that STL has imported the PUC during the Period of investigation is irrelevant.

#### **(c) Period of Investigation (POI)**

39. The Customs Tariff Act, 1975 and the said Rules as well as the Agreement on Safeguards and Article XIX of GATT has not defined the period of investigation. However, it is evident that the investigation period should be adequately long and sufficiently recent in time to allow reasonable conclusions to be drawn on the basis of various relevant factors such as domestic market conditions, performance of DI etc., as to whether or not the increased imports are indeed causing serious injury or threatening to cause serious injury to the DI and therefore justify the need for imposition of Safeguard Duty. On this basis, in the facts of the present case, it is considered reasonable and just to determine the period of investigation (POI) as 2016-17 to 2018-19 and 2019-20 (upto June' 2019). Analysis of most recent period, contained in the POI i.e. January 2019 to June 2019 has been done to examine the extent of serious injury, threat of serious injury.

40. Further, the annualized data for the most recent period, i.e. Jan- June' 2019 has also been considered along with actual data for the entire POI, wherever considered appropriate.

#### **(d) Source of Information**

41. Initially the data in the Application was submitted for the period 2015-16 to 2018-19 and April 2019 to May 2019. Subsequently, it was updated to include data till June 2019.

42. The DI have submitted transaction-wise import data for the PUC, which has been sourced from Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics (DGCI&S), Department of Commerce, Government of India for the period from 2016-17 to 2018-19. For the first quarter of 2019-20, the DI had initially submitted transaction wise import data from a secondary source. However, subsequently the Director General obtained data for first quarter of 2019-20 from DGCI&S which has been considered for analysis, in the investigation.

43. Thereafter, during the course of the investigation, Domestic industry has submitted import data for Quarter 2 and Quarter 3' 2019-20 obtained by them from DGCI &S, and the same has been provided to the DGTR and which has been validated by DGTR as well. DGTR has further obtained import data for Q4 of 2019-20 as well from DG-Systems.

44. The data relating to injury parameters for the period 2016-17 to 2018-19 and 2019-20 (upto June, 2019) in respect of the DI has been submitted by the applicants which has been considered for analysis to establish the fact of increased imports and consequential serious injury.

#### **(e) Confidentiality of Information Submitted**

45. The DI has provided some information in their application on confidential basis and has requested that it be treated as confidential. The DI has also provided a non-confidential version (NCV) of their application, as required under Rule 7 of the said Rules read with Trade Notice dated 21.12.2009 issued by Director General (Safeguards) under File No. D-22011/75/2009. Further, the DI has submitted reasons justifying their claim of confidentiality of this information.

46. In terms of Rule 7 of the said Rules, the applicant may choose not to disclose information which is by nature confidential and provide a non-confidential summary thereof. The DI has submitted reasons for claiming confidentiality of the information and furnished a non-confidential summary of the information filed on confidential basis. Since, the reasons satisfy the requirements of Rule 7 of the said Rules, the confidentiality claimed by the applicants is hereby granted.

#### 47. Increase in Imports in Absolute Terms

47.1.1 The PUC is being imported into India from various countries including China PR, Japan, USA and Korea RP. The major quantity of the PUC is being imported from China PR. The applicants have claimed that there has been a sudden, sharp and significant increase in imports in 2018-19, which has continued to be at high levels even in the most recent period, January 2019 to June 2019. The import volumes of the PUC have increased from 1,903 KFKM i.e. 2016-17 to 9,918 KFKM in 2018-19 including domestic industry imports and 7706 KFKM excluding imports by domestic industry.

47.1.2 Since inclusion of imports by DI inflates that actual volume of imports, therefore, for analysis of surge in imports and serious injury, the imports made by Domestic industry has been excluded from total imports and examination has been made considering only Non- DI imports as tabulated below.

| In KFKM                 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | Jan'19- June'19 | Jan'19- June'19 (annl.) |
|-------------------------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------------|
| <b>Imports (Total)</b>  | 1903    | 2469    | 9918    | 4,268           | 8,536                   |
| <b>Trend</b>            | 100     | 130     | 521     | 449             | 449                     |
| <b>Imports (non DI)</b> | 1,903   | 2,469   | 7,066   | 3,267           | 6,534                   |
| <b>Trend</b>            | 100     | 130     | 371     | 343             | 343                     |

47.1.3 The Imports (non DI) has increased from 1,903 KFKM in 2016-17 to 7066 KFKM in 2018-19, and have continued to be at increased levels in the most recent period (annualized figure 3,267 KFKM). There has been significant increase of 271% in 2018-19 and 243% in January 2019 to June 2019 as compared from the base year 2016-17.

47.1.4 There has been a significant surge in each quarter of 2018-19 and Quarter 1 of 2019-20, compared to previous year(s), as indicated below. However, this surge was much higher in Quarter 2 of 2018-19. The lowered imports in Q3 and Q4 of 2018-19 and Q1 of 2019-20 may be appreciate in this perspective. The imports in 2018-19 and most recent period have clearly continued to be at significantly high levels.

| Imports (Non DI)KFKM | Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>2016-17</b>       | 420       | 353       | 598       | 531       |
| <b>2017-18</b>       | 769       | 545       | 540       | 615       |
| <b>2018-19</b>       | 1244      | 2797      | 1436      | 1589      |
| <b>2019-20</b>       | 1678      |           |           |           |

#### 47.2 Increasing Imports in Relative Terms

47.2.1 Relative to the domestic production, imports of the PUC are found to have consistently increased between 2016-17 to 2018-19 and January- June' 2019 and has more than tripled from the base year as well as previous year level.

| In KFKM                                   | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | Jan'19- June'19* | Jan'19- June'19 (annl.) |
|---|---------|---------|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Imports (non DI)</b>                   | 1,903   | 2,469   | 7,066   | 3,267            | 6,534                   |
| <b>Trend</b>                              | 100     | 130     | 371     | 343              | 343                     |
| <b>DI Production</b>                      | ***     | ***     | ***     | ***              | ***                     |
| <b>Trend</b>                              | 100     | 114     | 120     | 103              | 103                     |
| <b>Import as % trend of DI Production</b> | ***     | ***     | ***     | ***              | ***                     |
| <b>Trend</b>                              | 100     | 114     | 329     | 286              | 286                     |

### 47.3 Imports in Post POI period

47.3.1 The DG-Safeguards in case of Carbon Black final finding dated 1.7.1998 on the relevance of POI held that “*In their application the domestic producers had submitted data upto September, 1997 and the decision to initiate the investigation was taken on the basis of this data. It would now not be fair to change this reference period as various interested parties respond to the investigation with reference to the facts available during this period.*” However, in later findings e.g. Caustic Soda Final Finding No. 22011/47/2009 dated 09.04.2010, the DG-Safeguards also analysed the data beyond the notified POI in consonance with the appellate body report in the Argentina Footwear and to mainly evaluate public interest. Further, the jurisprudence requires analysis of increased imports to be made over a sufficiently long period of investigation, which is defined at the time of initiation of investigation. Data analysis over a comparatively long period is done so as to even out any temporary variation or seasonal effects. It is therefore, the general practice of the Authority is to collect and examine relevant information for at least a period of 3 years. Considering data for one or two quarters in isolation, would not allow an objective analysis of “increased imports” However, as many interested parties have submitted on the decline in imports in the Post POI period, the import data for July – December’ 2019 i.e. Quarter 2 and Quarter 3’ 2019 has also been considered and examined herein below;

47.3.2 From the import data for the period post POI, it is observed that imports in Quarter 2 and Quarter 3 of 2019-20 have declined as compared to previous quarter i.e. Q1 of 2019-20 as given in table below:

| FY 2019-20  | Quarter 1 | Quarter 2<br>Post POI | Quarter 3<br>Post POI | Q2 and Q3 Post<br>POI |
|---|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Imports (non DI) (KFKM)</b>                          | 1678      | 655                   | 320                   | 975                   |
| <b>Import Price (CIF) Rs/FKM</b>                        | 328       | 306                   | 313                   | 308                   |
| <b>Import (non DI) of DI production<br/>(%) (Trend)</b> | 100       | 48                    | 22                    | 33                    |

47.3.3 Imports in Q2 and Q3 of 2019-20 are claimed to be inordinately low by DI on account of initiation of the present investigation on 23.09.2019 and issuance of Preliminary findings dated 06.11.2019, recommending Provisional Safeguard duty. The DI has submitted that during Quarter 3 of 2019-20, domestic sales were able to substitute imports, as importers in order to avoid running the risk of incurring Provisional Duty, had started buying from the DI. However, even though the sales of DI increased in Quarter 3 of 2019-20, their injury further accentuated as such sales were at prices comparable to import prices.

47.3.4 The below depicts analysis of post POI imports (Data of Quarter 2 and Q3 of 2019-20), and previous POI period as well:

|  | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 (Q1-Q2<br>annul.) | Quarter 2'<br>2019-20 | Q2 and Q3 |
|--|---------|---------|---------|---------------------------|-----------------------|-----------|
| <b>Imports (Non<br/>DI)</b>                                  | 1,903   | 2,469   | 7066    | 4666                      | 655                   | 975       |
| <b>Trend</b>   | 100     | 130     | 371     | 245                       | -                     | -         |
| <b>DI Production</b>   | ***     | ***     | ***     | ***                       | ***                   | ***       |
| <b>Trend</b>   | 100     | 114     | 120     | 89                        | -                     | -         |
| <b>Imports<br/>relative to DI<br/>Production<br/>(Trend)</b> | 100     | 114     | 328     | 285                       | 185                   | 128       |
| <b>Trend</b>   | 100     | 114     | 329     | 286                       | -                     | -         |

It is noted that though there is a decline in imports in Quarter 2 and Quarter 3 of 2019-20, they have continued to be at a comparable level as compared to 2016-17 and 2017-18, in relative terms to DI’s production.

47.3.5 As regards contention raised by some of the interested parties that the requirement of “increased imports” is not met in the present case, as the imports have declined in the most recent period, the reference is drawn to the following practice/Jurisprudence of panel decision in WTO. Attention is drawn to Rule 2(c) of the Safeguard

Rules, which defines "increased quantity" to include increase in imports whether in absolute terms or relative to domestic production. In the Final Findings dated 11.03.2014 issued in Safeguard duty investigations concerning imports of *Tubes, Pipes and Hollow Profiles, Seamless of iron, alloy or non-alloy steel*, it was held that:

*"the expression "increased quantity" has been defined in inclusive terms and the definition includes two parameters i.e. increase of imports in absolute terms and increase of imports in relative terms to domestic production. It is also seen that both these parameters need not exist together. The increased quantity is to be measured either in absolute terms or in relative to domestic production. The satisfaction/existence of one parameter is sufficient to fulfill the legal requirement."*

- The Panel in *US – Line Pipe*, has held that "*there is no need for a determination that imports are presently still increasing. Rather, imports could have 'increased' in the recent past, but not necessarily be increasing up to the end of the period of investigation or immediately preceding the determination*"(emphasis added)
- Further, interpreting the requirement of "*recent, sudden, sharp and significant increase in imports*" as set out by Appellate Body report in *Argentina-Footwear* Safeguard, the Panel concluded that the word 'recent' to mean 'not long past; that happened, appeared, began to exist, or existed lately'. In other words, the word 'recent' implies some form of retrospective analysis. It does not imply an analysis of the conditions immediately preceding the authority's decision. Nor does it imply that the analysis must focus exclusively on conditions at the very end of the period of investigation.
- In Panel in *US – Steel Safeguards*, in findings upheld by the Appellate Body, addressed the question of how recently the imports must have increased and concurred with the Panel's view in *US – Line Pipe*, as follows:

*"As the Panel in US – Line Pipe did, that Article 2.1 of the Agreement on Safeguards speaks of a product that 'is being imported ... in such increased quantities'. Thus, imports need not be increasing at the time of the determination; what is necessary is that imports have increased, if the products continue 'being imported' in (such) increased quantities. The Panel, therefore, agrees with the US – Line Pipe Panel's view that the fact that the increase in imports must be 'recent' does not mean that it must continue up to the period immediately preceding the investigating authority's determination, nor up to the very end of the period of investigation. As pointed out by the Panel in US – Line Pipe, the most recent data must be the focus, but should not be considered in isolation from the data pertaining to the less recent portion of the period of investigation. However, as indicated by the present continuous 'are being', there is an implication that imports, in the present, remain at higher (i.e. increased) levels.*

*Whether a decrease in imports at the end of the period of investigation, in the individual case, prevents a finding of increased imports in the sense of Article 2.1 of the Agreement on Safeguards will, therefore, depend on whether, despite the later decrease, a previous increase nevertheless results in the product (still) 'being imported in (such) increased quantities'. In this evaluation, factors that must be taken into account are the duration and the degree of the decrease at the end of the relevant period of investigation, as well as the nature, for instance the sharpness and the extent, of the increase that intervened beforehand."* (emphasis added)

It is also noted that in past safeguard cases (*Tubes, Pipes and Hollow Profiles, Seamless of iron, alloy or non-alloy steel, Methyl Acetoacetate and Soda Ash*), despite a slight decline in imports in the last year of POI, Safeguard duty was recommended.

47.3.6 In addition to the above, another relevant aspect which must be examined in such cases, is whether the decline in imports is a temporary phenomenon or reflects a long term change in demand pattern. (Ref: Appellate body report in *Argentina- Footwear*). DI has made reference to the Panel ruling in *Argentina – Footwear (EC)*, as well as in *Dominican Republic- Safeguard measures on Tubular fabric and Polypropylene bags*, where while considering decline in imports in the last year of the period of investigation, the Panel upholding the finding of increased imports, held that any temporary decline should not be taken in consideration, unless competing parties are able to adduce evidence to show that such decline is not temporary. Relevant para is extracted below:

*"7.233 The Panel does not consider the arguments of the complainants convincing. The Panel does not exclude the possibility that the demand for certain products could have remained stable and therefore unaffected by the overall fall in imports. However, the complainants have not argued or put forward any evidence from which it could be concluded that this was the case with respect to the products in question. Although the DEI did not explicitly show that the decrease in imports at the end of the period was temporary, the complainants have not offered any evidence to the contrary. In particular, the complainants have not demonstrated that the*

*decrease in imports (or the overall decrease in imports) reflected a permanent or long-term change.”*

47.3.7 In this context, the Domestic Industry has claimed that the decline in imports in Quarter 2<sup>1</sup> 2019-20 was on account of temporary decline in market demand, *inter alia*, caused by; Troubled condition of Indian telecom industry, Prolonged Monsoons and flooding in many places, Delay in rolling out of new Bharatnet projects, Stockpiling by importers and Filing of the present Petition seeking imposition of Safeguard Duty.

47.3.8 Since SMOF is one of the most important component of the telecommunication network and digital infrastructure in today's world. The Domestic Industry has stated that the demand of SMOF in India is likely to increase in near future, viz. new Bharatnet projects being announced, very low FTTH penetration in India (0.7% against 78% in China) offering huge potential for growth in demand, recent investments made by Reliance Jio, talks about Amazon's likely investment in Airtel, alongside Google potentially taking a stake in Vodafone Idea, amongst others. Thus, there is a likelihood of Indian demand increasing in the near future.

47.3.9 It is noted that the condition of telecom sector and monsoon led to decline in demand whose impact would happen both on imports and as well as the domestic sales. Therefore, imports in relative terms to production would be appropriate to be examined for Q2 and Q3 of 2019-20 as stated above.

47.3.10 Based on the above jurisprudence and the analysis of import data, it is concluded that though there is a decline in imports in Quarter 2<sup>1</sup> and Q3 2019-20 i.e. Post POI period, the imports in relative terms to DI production have continued to be at the levels, prevalent in 2016-17 and 2017-18. Thus, the decline in demand, and consequently in imports, in Post POI could be a temporary phenomenon and such a decline which cannot be confirmed as a long lasting phenomena, cannot undo the previous increase in imports.

#### 48. Unforeseen Developments

48.1 While Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 nor the Rules made thereunder impose an obligation on the Director General (Safeguards) to analyze the unforeseen developments as a result of which the increased imports have occurred, the Agreement on Safeguards read with Article XIX of GATT obligates the national authorities to examine “unforeseen developments” that led to the increase in imports and the consequent serious injury to the DI.

48.2 In view of the above requirement, the Director General has consistently been examining the issue of “unforeseen developments” in its investigations. Therefore, even in the present case, it is considered appropriate to examine the unforeseen developments that have led to the sharp increase in the imports of the PUC during the period of investigation.

48.3 The Appellate Body of WTO in **Argentina–Footwear (EC)**<sup>1</sup> case held that imports in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to domestic producers, must have been ‘unexpected’. In that case it was also held that the development of increased imports must have been due to “unforeseen developments”. The relevant para from the findings of Appellate body is reproduced below:

*“91. To determine the meaning of the clause – “as a result of unforeseen developments and of the effect of the obligations incurred by a Member under this Agreement, including tariff concessions ...” – in sub-paragraph (a) of Article XIX:1, we must examine these words in their ordinary meaning, in their context and in light of the object and purpose of Article XIX. We look first to the ordinary meaning of these words. As to the meaning of “unforeseen developments”, we note that the dictionary definition of “unforeseen”, particularly as it relates to the word “developments”, is synonymous with “unexpected”. “Unforeseeable”, on the other hand, is defined in the dictionaries as meaning “unpredictable” or “incapable of being foreseen, foretold or anticipated”. Thus, it seems to us that the ordinary meaning of the phrase “as a result of unforeseen developments” requires that the developments which led to a product being imported in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to domestic producers must have been “unexpected”. With respect to the phrase “of the effect of the obligations incurred by a Member under this Agreement, including tariff concessions ...”, we believe that this phrase simply means that it must be demonstrated, as a matter of fact, that the importing Member has incurred obligations under the GATT 1994, including tariff concessions. Here, we note that the Schedules annexed to the GATT 1994 are made an integral part of Part I of that Agreement, pursuant to paragraph 7 of Article II of the GATT 1994. Therefore, any concession or commitment in a Member’s Schedule is subject to the obligations contained in Article II of the GATT 1994.” (emphasis added)*

<sup>1</sup> Appellate Body Report, Argentina- Footwear (EC), para 90

48.4 Thus, Article XIX requires the importing member who has incurred obligation under the GATT, to examine developments it had not "foreseen" or "expected" when it incurred that obligation, which led to increase in imports.

48.5 Similarly, the **Appellate Body of WTO in Korea-Dairy<sup>2</sup>** case held that unforeseen developments are developments not foreseen or expected when member incurred that obligation. In that case it was also recognized that unforeseen developments are circumstances which must be demonstrated as a matter of fact. In another case, the Panel on **US-Steel Safeguards<sup>3</sup>** concluded that the confluence of several events can unite to form the basis of an unforeseen development. The relevant para is reproduced below, for ease of reference:

*"10.99 Article XIX does not preclude consideration of the confluence of a number of developments as "unforeseen developments". Accordingly, the Panel believes that confluence of developments can form the basis of "unforeseen developments" for the purposes of Article XIX of GATT 1994. The Panel is of the view, therefore, that it is for each Member to demonstrate that a confluence of circumstances that it considers were unforeseen at the time it concluded its tariff negotiations resulted in increased imports causing serious injury."*

48.6 The above reasoning of the Panel has been relied upon by the Hon'ble Authority in the Final Findings issued in **Safeguard Investigations concerning Solar Cells** dated 16.07.2018.

48.7 In the present investigation, the applicants have submitted that the sudden increase in imports in 2018-19 and the POI was a consequence of a confluence of several unforeseen developments in the global market, such as global over-capacity in Fibre industry, imposition/extension of trade measures by China against most of the Fibre manufacturing countries, policy restrictions imposed by countries like USA, Australia on import of telecom equipment/components from China and other non-fiscal/ non –regulatory restrictions imposed by major telecom operators (especially telecom operators in western Europe and USA) against China made Fibre, which have resulted in sudden diversion of imports to India. Some of these developments are discussed in detail herein below:

#### 48.7.1 Global Overcapacity created in 2018-19 is far in excess of the global demand

a. It has been submitted by the Applicants that anticipating that the global demand for SMOF is going to increase exponentially, primarily because of planned 5G roll outs, FTTH deployment, increased investments in digitization etc., most SMOF and preform manufacturers had made huge investments in scaling up their capacities. Consequently, there was an unprecedented increase in global SMOF manufacturing capacity in 2018-19 and 2019-20 by approximately 220 Million FKM, as compared to 2016-17. The enormity of this increase is more apparent from the fact that the total demand in India, which is the third biggest consumer of SMOF, was only 35 Million Fkm in 2018-19.

b. Further, in addition to the above, due to unexpected delaying of 5G roll out plans coupled with slower growth in FTTH deployment and digitization projects, the global demand did not increase commensurate to the increase in global capacity, thereby causing significant idling of capacities. In fact, an analysis of data for 2018-19 shows that as against the world's cumulative SMOF draw capacity of 753 Million FKM, the global demand in 2018-19 was only 554 Million FKM.

c. Thus, the overcapacity created in 2018-19 coupled with decreased demand, forced the SMOF manufacturers to look for new avenues to offload their excess production. At the same time, announcement of the New Digital Communications Policy, 2018 by Government of India focusing on widespread digitization in India, along with announcement of launch of FTTH services by Reliance Jio, created a huge demand possibility in India, thereby making it a very lucrative export target during 2018-19.

d. In addition to the above, the slower than expected growth in 2018-19 especially in China, which is the biggest consumer and producer of SMOF, further accentuated the overcapacity being faced by Chinese as well as other manufacturers. The lower than expected demand for SMOF in China during January- June' 2018 resulted in augmentation of inventories not only in China but in other jurisdictions as well, thereby forcing them to export to growing markets such as India. The Domestic industry has referred to the extracts from various CRU –reports capturing changing dynamics of global SMOF industry during the period leading to surge in imports, which are reproduced herein below:

<sup>2</sup> Appellate Body Report, Korea- Dairy, Para 85 and 89

<sup>3</sup> US – Steel Safeguards, para. 315

[[https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/248\\_259\\_abr\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/248_259_abr_e.pdf)]

*CRU – September' 2018 report-*

*"As a result, we see the fibre industry shifting from a shortfall of preform capacity in 2017 to an excess of preform capacity in 2018. The shift has become more pronounced as 2018 has progressed. In other words, there is more excess capacity in the latter months of the year. The reason is that several major suppliers have been bringing up further new preform capacity as the year progresses"*

*CRU- November' 2018 report-*

*"China market flattens out*

*World optical cable installations in H1 2018 amounted to 245 million fibre-km. This figure is 20 million fibre-km lower than the amounted we reported for H1 2018 in the last issue of this report (Sept. 2018 OFC Monitor). The downward revision reflects new information about weaker-than-expected orders in China.*

*... The excess capacity in some markets, such as China, is also putting pressure on some fibre makers to get more aggressive in export markets."*

- e. Further, the lower than announced procurement by Chinese telecom giant, China Mobile ('CM') during January- June' 2018 started off a global slowdown. The impact of this slowdown is visible in most SMOF producing nations, with many countries reporting accumulation of inventory level. The relevant para of **CRU-November' 2018** report is as below:

*In other words, one customer, which accounted for 28% of the world's 2017 optical cable consumption, did not procure as much cable in 2018 as it had indicated in its tender documents. Thus, CM (China Mobile) was the main contributor to the market slowdown reported in the summary on page one.*

...

*The tender documents that CM issued in Q4 2017 said that its demand for standard (loosetube, G.6523.D) cable in H1 2018 would be 110 million fibre-km. Over six months, this amount would average 18.3 million fibre-km per month. But recent reports indicate that CM had amassed a non-negligible inventory of cable at the end of 2017, and this quantity resulted in lower-than-expected orders in the early months of 2018. As the year progressed, CM's orders showed no increase compared with 2017 orders. Recent comments suggest that CM's standard cable orders through three quarters barely had reached 110 million fibre-km."*

...

*"Further, Chinese companies have said that inventories have continued to accumulate, contributing to the downward pressure on prices. China is more than half the world's optical cable – in terms of both production and consumption. China's manufacturers also have stepped up international sales, leading China to become a major exporter of fibre and cable. Thus, China's domestic market developments, such as higher inventories, also are affecting prices and sales in other countries and regions.*

*For example, we note that optical cable inventories in Japan, as indicated in the monthly data from Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) have increased this year. Japanese inventories in September 2018, for example, were 71% higher than in September 2017...."*

- f. Thus, from the above, it is evident that the global overcapacity on account of various factors such as delayed 5G roll outs, slower growth in FTTH deployments and Digitization projects, along with slump in Chinese market has distorted the international SMOF market. The slump has forced producers in various jurisdictions to look for other viable export markets. In such circumstances, India being a significant consumer of Optical Fibre cable, witnessed surge in imports.

48.7.2 The Domestic industry has further claimed that various trade barriers/ restrictions imposed by SMOF producing nations against each other, has made open markets such as India as a prime target for exports. For example,

- a. China's MOFCOM has significantly increased anti-dumping duties on imports of SMOF from US and Japan, Anti-dumping duty investigation initiated by Eurasian Union concerning imports of fibre from the US and Japan

- b. In March 2018, the department for the protection of the internal Market of the Eurasian Economic Commission (ECE) initiated an anti-dumping investigation against single-mode optical fibre imports from the US and Japan to the Eurasian Economic Union.
- c. China has extended Anti-dumping duty on imports SMOF from India

48.7.3 It has further been submitted by the Domestic industry that the trade barriers imposed by major markets to protect their domestic industries, has left open markets like India a soft target for exports. Further, China has imposed anti-dumping duty against most of the Optical Fibre manufacturing countries including India, Japan and the USA. Consequently, Chinese market, which is the biggest consumer of the subject goods, has become unviable option for exporters from other countries. These factors have forced exporters in China as well as other countries to look for other viable export options. Consequently, year 2018-19 has seen an unprecedented diversion of exports from different nations to India, which has substituted the Indian domestic industry's market share. The European Commission Regulation imposing definitive Safeguard duty on Certain Steel Products (supra), had considered trade restrictive measures as an "unforeseen development", as below:

*"(56) The Commission disagrees with such claims as the fact that trade restrictive actions are taken within the framework of WTO rules does not imply that they cannot be considered as an unforeseen development. The Commission does not contest the right of countries to take anti-dumping or anti-subsidy measures according to the relevant WTO rules. The issue at stake, however, is the unprecedented and increased number of such measures taken by third countries, which have created trade diversion resulting in increase of imports into the EU ..."*

#### 48.7.4 **Restriction on sale/use of China made Optical Fibre in many western countries including USA and most of the Europe.**

It has been submitted by the Domestic industry that since SMOF is one of the key products in the digital infrastructure, with a view to ensure digital security, many telecom operators in western/developed countries have imposed restriction on use of China made Optical Fibre in their networks. Similar, non-regulatory and non-fiscal barriers to Chinese products have been put in place by various nations including Australia, Western Europe in order to protect themselves from onslaught of Chinese exports, as well as for data security concerns. Therefore, the Chinese manufacturers have a restricted international market and are forced to off-load their production in nearby growing markets such as India.

48.7.5 The Indian demand is about 35 Million FKM, as against the global capacity of approx. 220 Million FKM in 2018-19. With many countries undertaking tariff/ non- tariff or regulatory measures to protect their domestic industry, there has been diversion of exports to countries with open markets, such as India. Such factors were not foreseeable or expected when India incurred obligations under GATT and therefore I hold that the condition of unforeseen developments causing increase in imports is met in the present case.

48.7.6 Some of the interested parties have contended that these unforeseen developments primarily relate to China and therefore do not justify global action. China accounts for approximately 60% of global SMOF production as well as consumption, and therefore the state of plan in Chinese market would affect most of the SMOF producers globally. Further Domestic Industry has stated in China, the market is predominantly driven by China Mobile, which accounted for almost 30% of global fibre consumption in 2017-18. Thus, changed dynamics of Chinese market, especially any change in consumption pattern of China Mobile, significantly impacts the global SMOF trade pattern. In this context, the Domestic industry has relied upon the below excerpt from CRU- September' 2018 report, highlighting the influence of China Mobile (CM) on global scale-

*"This scrutiny of China Mobile's demand is warranted because the company's orders in 2017 accounted for 29% of the world's optical cable consumption. In the 2018 forecast, China Mobile's orders are expected to account for 32% of the world's total fibre installations. Thus, if China Mobile's orders are lower than expected, say by 10%, then the world market will be 3% lower than expected."*

*"This situation, with one customer having such an influential role in the world's optical cable market, is unusual. In 2006, the peak year of fibre installations for its FiOS FTTP program, Verizon accounted for 9% of the world's optical cable market. In 2001, when NTT East and West together installed almost 11 million fibre-km, the two "sister" companies accounted for 11% of the world's optical cable consumption."*

48.7.7 Therefore with China being the biggest producer, and also the biggest consumer of SMOF, has the ability to influence the dynamics of Global SMOF trade. Slowdown of Chinese market coupled with trade barriers imposed by China as well as other nations, has made open markets such as India an easy target for offloading excess productions. From the aforesaid demonstrated factors, it is noted that confluence of various aforestated factors has led to a surge in imports to India, the significant overcapacity, slump in global demand and inventory build-up in other jurisdictions.

48.7.8 In this context, reference is also made to the decision of Panel in **India- Steel Safeguards**, wherein it had accepted India's claim that significant increase in global production capacity along with decline in demand, among other factors, were "unforeseen developments" that caused increase in imports. The relevant paras of the said report are extracted below for reference:

*"7.97. In our view, it was reasonable for the Indian competent authority to find that an increase to such extent in production capacity, combined with higher domestic demand in India, decreased demand in several major markets, and that currency depreciation in Russia and Ukraine were unforeseen developments. We consider that negotiators could not reasonably have expected this confluence of events when India negotiated its tariff concessions. In light of the above reasons, we conclude that the Indian competent authority provided reasoned and adequate explanation as to why the identified developments were unforeseen."*

48.7.9 With respect to the "the effect of the obligations incurred" under the GATT 1994, according to India's Schedule of Concessions, the bound rate on the product concerned is 40% ad valorem. India reduced its applied rates on products in many sectors, including SMOF with the applied rate on the product concerned being 10% during the POI. (15% from July' 2019 onwards). Thus, the increase in imports during POI and in the most recent period may be appreciated in the context of aforesaid unforeseen development and the effect of obligation incurred.

#### **49. Serious Injury and threat thereof:**

49.1 To determine whether the increased imports of the PUC have caused and / or are threatening to cause serious injury to the Domestic Industry of like or directly competitive products, various parameters including domestic Industry's share production, capacity utilization, and price parameters were analysed in the preliminary finding dated 6.11.2019, which are retracted below after examining submissions filed in respect of later investigation.

49.2 The term "*serious injury*" has been defined in sub Section (11) (c) of Section 8B of the Act, as amended by Finance Act, 2020, an injury causing significant overall impairment in the position of a domestic industry. "Threat of serious injury" has been defined in subsection 11 (d) of section 8B, as a clear and imminent danger of serious injury.

49.3 The Article 4.2(a) of the Agreement on Safeguard and Annexure to Rule 8 of the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard duty) Rules, 1997 technically require that certain listed factors as well as other relevant factors must be evaluated to determine serious injury or threat of serious injury. In this regard, reference may be made to the decision of **Argentina – Footwear (EC)**<sup>4</sup>, wherein the Appellate Body discussed the relationship between the definition of "serious injury" in Article 4.1(a) and the requirement of an evaluation of "all relevant factors" in Article 4.2(a):

*"[I]t is only when the overall position of the domestic industry is evaluated, in light of all the relevant factors having a bearing on a situation of that industry, that it can be determined whether there is 'a significant overall impairment' in the position of that industry. Although Article 4.2(a) technically requires that certain listed factors must be evaluated, and that all other relevant factors must be evaluated, that provision does not specify what such an evaluation must demonstrate. Obviously, any such evaluation will be different for different industries in different cases, depending on the facts of the particular case and the situation of the industry concerned. An evaluation of each listed factor will not necessarily have to show that each such factor is 'declining'. In one case, for example, there may be significant declines in sales, employment and productivity that will show 'significant overall impairment' in the position of the industry, and therefore will justify a finding of serious injury. In another case, a certain factor may not be declining, but the overall picture may nevertheless demonstrate "significant overall impairment" of the industry. Thus, in addition to a technical examination of whether the competent authorities in a particular case have evaluated all the listed factors and any other relevant factors, we believe that it is essential for a panel to take the definition of 'serious injury' in Article 4.1(a) of the Agreement on Safeguards into account in its review of any determination of 'serious injury'.*

---

<sup>4</sup>Appellate Body Report, Argentina – Footwear (EC), para. 139.

49.4 Further the Panel in US – **Wheat Gluten**<sup>5</sup>, in a finding which was upheld by the Appellate Body, elaborated on the meaning of the term "serious injury":

*"[A] determination as to the existence of such 'significant overall impairment' can be made only on the basis of an evaluation of the overall position of the domestic industry, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry.*

...

*[W]e do not consider that a negative trend in every single factor examined is necessary in order for an industry to be in a position of significant overall impairment. Rather, it is the totality of the trends, and their interaction, which must be taken into account in a serious injury determination. Thus, such upturns in a number of factors would not necessarily preclude a determination of serious injury. It is for the investigating authorities to assess and weigh the evidence before them, and to give an adequate, reasoned and reasonable explanation of how the facts support the determination made."*

49.5 Accordingly, in analyzing serious injury and threat of serious injury, factors which are mentioned in the rules and are relevant for determination of serious injury or threat of serious injury, have been considered, as discussed herein below:

**a. Changes in level of Sales:**

The Applicants' sales in domestic market can be bifurcated into two segments: (i) Sales to independent Customers, (ii) Sales to Captive/related parties. It has been submitted by the DI that surge in imports has not impacted their sales to captive/related parties, as imports do not compete with them in captive/related party segment. However, their Domestic sales to independent customers have declined significantly as compared to the previous years, and the sales of Domestic industry in this segment has been substituted by imports. Analysis of Sales made by the DI as against imports is as below:

| (KFKM)   | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | Jan'19 to June'19 | Jan'19 to June'19 (Annl.) |
|--|---------|---------|---------|-------------------|---------------------------|
| <b>DI sales (captive &amp; related)</b>            | ***     | ***     | ***     | ***               | ***                       |
| <b>Trend</b>                                       | 100     | 188     | 213     | 171               | 171                       |
| <b>DI Domestic Sales (Non-captive/Non related)</b> | ***     | ***     | ***     | ***               | ***                       |
| <b>Trend</b>                                       | 100     | 65      | 48      | 31                | 31                        |
| <b>Imports (Non DI)</b>                            | 1,903   | 2,469   | 7,066   | 3,267             | 6,534                     |
| <b>Trend</b>                                       | 100     | 130     | 371     | 343               | 343                       |

The above table demonstrates that in 2016-17 the imports was 1903 KFKM and DI sales was \*\*\* KFKM. The situation has reversed in most recent period with imports increasing to \*\*\* KFKM and DI sales being reduced to \*\*\* KFKM. The share of market lost by DI has been substituted by the increased imports. Further, DI's sales to captive/related party customers has by and large remained unaffected by the surge in imports.

**b. Market Share of imports and domestic producers in domestic demand:**

The Applicants have submitted that they do not have access to sales data of other Indian producers, therefore, total Indian Consumption number has been taken from quarterly reports of CRU, a body which specialises in studying and analysing commodity markets, including Optical Fibre market. Accordingly, in the Preliminary findings Indian demand computed in terms of data published in CRU was considered. Since, none of the interested parties have raised objection to the computation of demand from CRU reports or have produced any alternate source of information on India demand, the demand computed in terms of CRU is being considered for final determination as well.

<sup>5</sup>Panel Report, US – Wheat Gluten, paras. 8.80 and 8.85.

For the analysis of share in market for independent consumers, the consumption of PUC by the domestic industry (either by captive/related party sale or imports) has been excluded from the Total Indian consumption as reported in CRU and the percentage share in demand is tabulated below.

Fig: In KFKM

|   | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | Jan'19-June'19 | Jan'19-June'19 (Annl.) |
|---|---------|---------|---------|----------------|------------------------|
| <b>Indian Consumption as per CRU</b>  | 27062   | 32186   | 35197   | 17547          | 35094                  |
| <b>Indian Consumption for independent customers (excluding DI's Captive/Related party sales and DI imports)</b>               | 17,971  | 15,057  | 12,948  | 8,763          | 17526                  |
| <b>Imports (Non DI)</b>   | 1,903   | 2,469   | 7,066   | 3,267          | 6534                   |
| <b>DI Market share in demand for independent customers</b>  | ***     | ***     | ***     | ***            | ***                    |
| <b>DI Domestic Sales (Trend)</b>  | 100     | 65      | 48      | 31             | 31                     |
| <b>Imports (Non DI) share in demand for independent customers (excluding DI's Captive/Related party sales and DI imports)</b> | 11%     | 16%     | 55%     | 37%            | 37%                    |
| <b>Trend of DI's Share in demand for independent customers (excl. DI's Captive consumption and related party sales)</b>       | 100     | 77      | 67      | 31             | 31                     |

**c. Changes in level of Production:**

The production of the domestic industry in the most recent period has substantially declined in comparison to 2017-18 & 2018-19 though the demand has increased substantially.

| Production (KFKM) (Trend)  | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | Jan'19-June'19 | Jan'19-June'19 (Annl.) |
|----------------------------|---------|---------|---------|----------------|------------------------|
| <b>STL</b>                 | 100     | 115     | 123     | 117            | 117                    |
| <b>BFL</b>                 | 100     | 111     | 109     | 62             | 62                     |
| <b>Total DI Production</b> | 100     | 114     | 120     | 103            | 103                    |

**d. Capacity Utilisation:**

The capacity utilisation of the Domestic industry is given below.

| Capacity Utilization         | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | Jan'19-June'19 | Jan-June'2019 (annualised) |
|------------------------------|---------|---------|---------|----------------|----------------------------|
| DI Installed Capacity (KFKM) | ***     | ***     | ***     | ***            | ***                        |
| Trend (%)                    | 100     | 112     | 135     | 143            | 143                        |
| DI Production (KFKM)         | ***     | ***     | ***     | ***            | ***                        |
| Trend (%)                    | 100     | 114     | 120     | 103            | 103                        |
| DI Capacity Utilization      | ***     | ***     | ***     | ***            | ***                        |
| Trend (%)                    | 100     | 103     | 86      | 73             | 73                         |

The capacity utilisation of the Domestic industry has declined from \*\*\* % in 2017-18 to \*\*\* % in the most recent period.

The Applicants have claimed that the optimum capacity utilization for this industry is around 95-100%, as the cost associated with reducing production or restarting plant is very high. The DI has further claimed that the capacity utilization going below previous years' levels and remaining below 95% to 100%, without there being any fall in demand of PUC.

The applicant has also submitted that anticipating the increase in Indian demand, the applicants had made huge investments for increasing their production capacity and that STL was forced to delay the commissioning of its new capacity of 11000 KFKM (not considered in the above table) because of lack of orders in the domestic market. However, this capacity has now been commissioned and is in use from August, 2019, thereby further accentuating the injury and reducing the capacity utilisation in the post POI Period.

#### e. Employment

The applicants have submitted that there has not been any substantial change in employment levels during the POI.

| Locations                 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | Jan-June'19 |
|---------------------------|---------|---------|---------|-------------|
| STL, Waluj (Trend)        | 100     | 110     | 110     | 107         |
| STL, Shendra (Trend)      | 100     | 201     | 167     | 153         |
| BFL(Trend)                | 100     | 112     | 112     | 110         |
| Total DI Employees(Trend) | 100     | 125     | 120     | 115         |

However, in view of the reducing market share and capacity utilization, the applicants have claimed that they have shut-down a part of their manufacturing capacity in Quarter2' 2019-20 (July 2019 to September 2019), and had to lay-off some of their work-force.

#### f. Productivity

Productivity has marginally declined in the most recent period due to decrease in production, as stated below;

| Productivity         | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | Jan- June'19 |
|----------------------|---------|---------|---------|--------------|
| <b>DI Production</b> | ***     | ***     | ***     | ***          |
| <b>Trend</b>         | 100     | 114     | 120     | 103          |
| <b>Employees</b>     | ***     | ***     | ***     | ***          |
| <b>Trend</b>         | 100     | 125     | 120     | 115          |
| <b>Productivity</b>  | ***     | ***     | ***     | ***          |
| <b>Trend</b>         | 100     | 90      | 99      | 89           |

#### g. Profitability

The profitability of the domestic industry has declined in 2018-19 as compared to previous year i.e. 2017-18 with losses in the most recent period. Due to imports coming at such lower prices, the domestic industry is not able to earn reasonable return/profit. The profit/loss trend, during the POI is as below:

Fig.- in Trend

|   | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | Jan- June' 19 |
|---|---------|---------|---------|---------------|
| <b>DI Wt. Avg. Unit Selling Price<br/>(Non-captive/Non-related)</b> | 100     | 117     | 121     | 82            |
| <b>DI Wt. Avg. Cost of Sale</b>                                     | 100     | 103     | 112     | 118           |
| <b>DI Profit/ Loss</b>  | 100     | 173     | 158     | (65)          |

The above table depicts that during the most recent period, the applicants had to sell at prices substantially below their cost of sales, due to imports coming at very low prices in the most recent period, especially Quarter 1 of 2019-20 and suffered losses. The quarterly analysis of profitability of DI for the last 4 quarters is as below:

| Profit/Loss         | Q1' FY 18-19 | Q2' FY 18-19 | Q3' FY 18-19 | Q4' FY 18-19 | Q1' FY 19-20 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>STL (Rs/FKM)</b> | ***          | ***          | ***          | ***          | ***          |
| <b>Trend</b>        | 100          | 80           | 79           | 9            | (48)         |
| <b>BFL (Rs/FKM)</b> | ***          | ***          | ***          | ***          | ***          |
| <b>Trend</b>        | 100          | 95.80        | (35)         | (138)        | (192)        |

#### **h. Price Underselling, undercutting and Price suppression**

Price Underselling, undercutting and Price suppression is shown in the table below:

*Fig.- In Rs/ FKM*

| Per Unit                                  | Jan- June 2019 |
|---|----------------|
| DI- Weighted Avg. Unit Selling Price (SP) | ***            |
| Weighted Avg. Fair Selling Price (FSP)    | ***            |
| Landed Value (Rs/KFKM) (LV)               | 411            |
| Price Undercutting (SP-LV)                | (***)          |
| Price Underselling (FSP-LV)               | ***            |
| Price Suppression                         | ***            |

In the most recent period, the landed price of the subject goods is significantly below the level of Fair Selling Price of the domestic industry, thereby suppressing the prices of the domestic industry.

On the point of negative Price undercutting, DI has submitted that the exporters have been providing longer credit period or huge volume discounts to the importers.

The Director General notes that the DI is able to achieve a selling price of Rs. \*\*\* per FKM which is much below the cost of sales and fair selling price established for DI for the PUC. Thus, the negative price undercutting needs to be appreciated in this backdrop that the import prices have infact led to significant price suppression to the extent that it has pulled the NSR of DI even below the landed price of import for it to remain in market.

#### **a. Inventory**

The table below depicts the inventory levels which have witnessed a significant increase during the POI.

The applicants have submitted that generally they maintain production in line with the projected sales, so as to avoid costs associated with maintaining high inventories. Consequently, it would normally have limited stock available. However, due to onslaught of imports, many customers of the applicants have refused to honour their contracts, leading to high inventories. Moreover, reducing production has led to building up of huge raw material (preform) inventory with BFL.

*fig-In Trend*

| Financial Year/Quarter | Inventory (STL) | Inventory (BFL) | Total DI |
|------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 2016-17                | 100             | 100             | 100      |
| 2017-18                | 79              | 67              | 73       |
| 2018-19                | 567             | 171             | 356      |
| Jan'19 to June'19      | 588             | 193             | 377      |

49.6 From the above analysis, it is noted that the all major relevant parameters in the present case indicate deterioration in the condition of the domestic industry establishing serious injury and threat thereof.

#### **50. Causal Link between Increased Import and Serious Injury / Threat of Serious Injury**

50.1 The WTO Panel on Korea-Dairy set forth the basic approach for determining “causation”, as follows:

*“In performing its causal link assessment, it is our view that the national authority needs to analyse and determine whether developments in the industry, considered by the*

*national authority to demonstrate serious injury, have been caused by the increased imports. In its causation assessment, the national authority is obliged to evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry. In addition, if the national authority has identified factors other than increased imports which have caused injury to the Domestic Industry, it shall ensure that any injury caused by such factors is not considered to have been caused by the increased imports. To establish a causal link, Korea has to demonstrate that the injury to its Domestic Industry results from increased imports. In other words, Korea has to demonstrate that the imports of SMPP cause injury to the Domestic Industry producing milk powder and raw milk. In addition, having analyzed the situation of the Domestic Industry, the Korean authority has the obligation not to attribute to the increased imports any injury caused by other factors.”*

50.2 In the WTO Appellate Body Report in Wheat Gluten case, it has been held as under:

*“We begin our reasoning with the first sentence of Article 4.2(b). That sentence provides that a determination “shall not be made unless [the] investigation demonstrates ... the existence of the causal link between increased imports ... and serious injury or threat thereof.” (emphasis added) Thus, the requirement for a determination, under Article 4.2(a), is that “the causal link” exists. The word “causal” means “relating to a cause or causes”, while the word “cause”, in turn, denotes a relationship between, at least, two elements, whereby the first element has, in some way, “brought about”, “produced” or “induced” the existence of the second element.[1] The word “link” indicates simply that increased imports have played a part in, or contributed to, bringing about serious injury so that there is a causal “connection” [2] or “nexus” between these two elements. Taking these words together, the term “the causal link” denotes, in our view, a relationship of cause and effect such that increased imports contribute to “bringing about”, “producing” or “inducing” the serious injury. Although that contribution must be sufficiently clear as to establish the existence of “the causal link” required, the language in the first sentence of Article 4.2(b) does not suggest that increased imports be the sole cause of the serious injury, or that “other factors” causing injury must be excluded from the determination of serious injury. To the contrary, the language of Article 4.2(b), as a whole, suggests that “the causal link” between increased imports and serious injury may exist, even though other factors are also contributing, “at the same time”, to the situation of the domestic industry”.*

- 50.3 Keeping in account the aforesaid jurisprudence, the facts of the present case are examined to see whether there is a causal link between imports and serious injury or threat of serious injury being faced by the Domestic industry. Analysis of data for the period 2016-17 to 2018-19 and January-June 2019 indicates that imports of the PUC have remained at significantly high levels from Quarter 1' 2018-19 onwards till the most recent period, and also the import prices of the PUC have come down significantly in the most recent period. This has led to the DI revising their own prices downwards in the most recent period, leading to losses. As a result, the net sales realization of the DI has sharply declined when compared to previous quarters and the base year and previous year.
- 50.4 A comprehensive evaluation of parameters enumerated above demonstrates that serious injury is being caused to the DI by the significantly increased imports of PUC during POI more so from Q1 of 2018-19 to Q1 of 2019-20. Under aforesaid circumstances and, it is concluded that there exists a causal link between sudden surge in imports and the injury (and threat thereof) being caused to the DI. The period of decline in market share of the DI, sales (volume as well as price), capacity utilization and profitability etc., directly coincides with the period when there was a sudden and significant surge in imports.

#### **Submissions regarding Anti-dumping duty to be more suitable remedy for DI**

- 50.5 Some of the interested parties have claimed that as the injury to domestic industry is on account of surge in low priced imports from China, therefore the suitable remedy in the present case would have been “Anti-dumping duty” and not safeguard action. They have therefore requested for termination of the present investigation in terms of Para 2 of Annexures to the Rules.
- 50.6 Noting the submissions of the Interested Parties, it is clarified that various Trade Remedy Measures i.e. anti-dumping, countervailing duty or safeguard are not mutually conclusive and infact can be applied concurrently as well if conditions pertaining to a measure are satisfied. In this investigation, the analysis has been undertaken for a safeguard measure in accordance with relevant Act/Rules and remedy of appropriate quantum and tenure due to increase in imports in later paras has been considered.

### Imports of Individual Countries

- 50.7 Further, SEI Ltd., one of the interested parties, has submitted that share of Japan in total imports has declined considerably during 2018-19 and the most recent period, therefore, imposition of Safeguard duty on Japan is not warranted. In this regard, it is noted that neither the Customs Tariff Act nor the Rules made thereunder provide for country-wise examination of “increased imports”. Thus, for a determination of “increased imports”, there is no requirement under the law to show that imports from all sources have increased. In this context, it is imperative to note that the mandate under Safeguard law is to protect domestic industry from onslaught of sudden surge in imports. As such, country wise import analysis is not warranted, other than for determining *de-minimis* imports from developing countries, in a Safeguard investigations. Thus, no relevance is required to be given to the each country’s share in Imports.

Further, in the Final findings dated 16.11.2012, issued in Safeguard duty investigation concerning imports of ***Diocyl Phthalate*** into India, while dealing with a similar argument, the Authority held as below:

*“As regards the arguments that the Korea’s exports dropped to 3382MT from 11924 MT in the said period in 2011, it is noted that individual country movements in imports are entirely irrelevant under Safeguard investigations because cumulative imports from various sources have been considered for surge in imports”*

- 50.8 Thus, keeping in view the objective of the legislation as well as the past practice of this Directorate, termination of the present investigation is not warranted.

### 51. Adjustment Plan

- 51.1 One of the essential features of the WTO Agreement on Safeguards is adjustment by the domestic industry.
- 51.2 Further, Article 5.1 of the Agreement on Safeguards provides that a Member shall apply Safeguard measures only to the extent necessary to prevent or remedy serious injury and to facilitate adjustment. Article 7.1 of the Agreement on Safeguards mandates a WTO member country to apply safeguard measures only for such period of time as may be necessary to prevent or remedy serious injury and to facilitate adjustment. Article 7.4 mandates that in order to facilitate adjustment in a situation where the expected duration of a safeguard measure as notified under the provisions of paragraph 1 of Article 12 is over one year, the Member applying the measure shall progressively liberalize it at regular intervals during the period of application. The provisions are *pari-materia* with Safeguard Rules 4(4)(ii), 11(2), proviso to 11(3), 12(1), 16(1) and proviso to 16(2). In addition Rule 5(2) of the Safeguard Rules provides as under:

*(2) An application under sub-rule (1) shall be in the form as may be specified by the Director General in this behalf and such application shall be supported by, -*

*(b) a statement on the efforts being taken, or planned to be taken, or both, to make a positive adjustment to import competition”.*

51.3 The Domestic industry have submitted a detailed statement of plan that they have undertaken or will be undertaking to make themselves more competitive to the imports. The plan includes steps towards improving their efficiency and reducing their costs by better utilization of raw materials/consumables and through backward integration. The Domestic industry has already taken concrete steps towards achieving better yield from their raw material, reducing cost by in-house generation of certain raw material for which they were otherwise import dependent. Both the companies constituting Domestic Industry have given their separate plans/projects they are considering for adjusting to the increased level of imports. They have also provided a statement of saving that would ensue on successful implementation of their plan.

51.4 Some of the interested parties opposing the levy of safeguard duty have argued that the DI has claimed excessive confidentiality on their adjustment plan. It is noted that in the Non-confidential summary, DI has indicated that they have undertaken projects which would help them achieve more cost efficiency by better utilization of raw material, reduction in cost of procurement of raw material and removal of bottlenecks in the production process. It has been submitted by the Domestic industry that the projects being undertaken by them consist of developing proprietary technology, information in respect of which is not available in public domain and is business sensitive.

51.5 It is observed that Rule 5(2) of the Safeguard Rules does not provide a format for the statement of adjustment referred to as adjustment plan. No guidance is provided in the Agreement on Safeguards also. The statement of the efforts planned to be taken by the Domestic Industry as provided in the Petition has been examined. Further, since this is a technology intensive industry, with several patented process being adopted by all interested parties, the DI’s claim for confidentiality on their Adjustment plan has been accepted.

51.6 It is observed that STL has indicated \*\*\* different projects that has been undertaken by them which would significantly bring down their raw material prices and improve their efficiency. Further, BFL has also submitted their plan of action which would help them bring their cost down by 8-10 %.

51.7 The panel report in Korea-Dairy case (WT/D598) held the following regarding adjustment plan

*“We wish to make it clear that we do not interpret Article 5.1 as requiring the consideration of an adjustment plan by the Authorities, as the European Communities asserts. The panel finds no specific requirement that an adjustment plan as such must be requested and considered in the text of the Agreement on Safeguards. Although there are references to industry adjustment in two of its provisions, nothing in the text of the Agreement on Safeguards suggests that consideration of a specific adjustment plan is required before a measure can be adopted. Rather, we believe that the question of adjustment, along with the question of preventing or remedying serious injury, must be a part of the Authorities’ reasoned explanation of the measure it has chosen to apply .Nonetheless, we note that examination of an adjustment plan, within the context of the application of a Safeguard measure, would be strong evidence that the Authorities considered whether the measure was commensurate with the objective of preventing or remedying serious injury and facilitating adjustment.”*

51.8 Therefore, in view of the aforesaid and the adjustment plan submitted by the Domestic Industry, it is found that the adjustment plan contemplated by industry in the given ecosystem appears to be reasonable and pragmatic. Needless to mention that since relief under a safeguard measure is only for a limited period of time as an emergency measure and industry’s adjustment efforts to withstand the surge in imports needs to be seen primarily in accordance with the provision of the rules.

## 52.

### Public Interest

52.1 The requirement to analyse whether imposition of Safeguard measure would be in public interest is contained in Article 3.1 of the Agreement on Safeguards, which states as follows:

*“A Member may apply a safeguard measure only following an investigation by the competent authorities of that Member pursuant to procedures previously established and made public in consonance with Article X of GATT 1994. This investigation shall include reasonable public notice to all interested parties and public hearings or other appropriate means in which importers, exporters and other interested parties could present evidence and their views, including the opportunity to respond to the presentations of other parties and to submit their views, inter alia, as to whether or not the application of a safeguard measure would be in the public interest. The competent authorities shall publish a report setting forth their findings and reasoned conclusions reached on all pertinent issues of fact and law.”*

52.2 Though Section 8B of the Customs Tariff Act 1975 and the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, does not stipulate examination of public interest, the DG-Safeguards has consistently evaluated public interest before recommending the levy of definitive safeguard duty in terms of Article 3.1 of the Agreement on Safeguards.

52.3 In the present case, it is noted that the Domestic Industry is facing serious injury due to surge in imports in POI as evaluated during POI especially, in 2018-19 and Q1 of 2019-20. Being highly technology and investment intensive industry, the domestic industry needs protection.

Also, one of the interested parties has stated that Safeguard duty would not be in public interest as it will impact users industry. It is noted that the SMOF is a input for optical cable manufacturing which is further used by Telcos. The obligation to evaluate public interest essentially requires a likely impact of the recommended safeguard measure on various stakeholders. It is therefore important to examine the same with reference to the value chain partners.

52.4 It is noted that w.e.f. 01.07.2019 the BCD on PUC has been increased from 10% to 15%. This increase is just after the end of POI during which increased imports have been analysed to have caused serious injury to domestic industry.

During the Post POI the imports have came down significantly in absolute terms though they remain at a comparable level with 2016-17 and 2017-18 in relative terms as percentage of DI's production. The market share of DI in Q2 and Q3 of 2019-20 i.e. Post POI has not been adversely impacted though price suppression is witnessed. As in a Safeguard measure, it is the surge in imports and not the import price which is of prime importance, the safeguard measure recommended should commensurate with the extent of injury essentially on account of import surge. As stated above a domestic industry may face injury on account of various trade practices which may include dumping, subsidy or surge in imports.

52.5 Therefore, on the basis of all the aforesaid considerations, a safeguard measure of an appropriate quantum and tenure has been recommended so as to balance the two competing concerns in the later paragraphs.

### 53. Conclusions

53.1 During the period of investigation there was an overall deterioration in the functioning of the DI, which is indicative of the serious injury and threat of serious injury in future. The parameter-wise finding of the serious injury suffered by the DI on account of enhanced imports of the PUC is summarized as under:

- a) The volume of imports of the PUC have increased significantly during POI mainly in 2018-19 and Q1 of 2019-20.
- b) The imports in Q2 and Q3 of 2019-20 are at comparable level of 2016-17 and 2017-18 in terms relative to production.
- c) The DI's market share has declined, whereas the market share of imports has increased.
- d) The increased imports of the PUC have substituted for the market share of DI;
- e) The capacity utilization has decreased significantly in POI despite increase in demand;
- f) The Domestic sales of the DI has declined significantly during the most recent period with their lost market been taken over by the imports;
- g) The DI was earning profit in 2017-18 are in significant losses during 2018-19 and Post POI;
- h) The inventories of the PUC have increased significantly;
- i) There is significant price underselling and price suppression due to imports of PUC.
- j) On an overall basis, DI has suffered serious injury during POI due to increased imports.

### (F) Developing Nations

54. Proviso to Section 8B(1) of the Customs Tariff Act, 1975 provides that Safeguard Duty shall not be imposed on article originating from a developing country so long as its share of imports does not exceed 3% of the total imports of that article or, where the article is originating from more than one developing country, then, so long as the aggregate of the imports from all such developing countries, each with less than 3% import share taken together, does not exceed 9% of the total imports of that article. Further, Notification No.19/2016-Custom (NT), dated 5th February, 2016 specifies the developing countries for the purposes of this provision. Upon applying this legal provision read with the said notification to the available data during the most recent period of the POI in the present case, it is noted that as a percentage of the total imports of the PUC into India, the imports from China PR individually account for more than 3% while the share of every other developing country is individually less than 3%. As data of most recent period has been considered, DI's claim to consider Indonesia not meeting the 3% criteria is not justified and has not been considered. Also, the collective share of the developing countries whose individual share is less than 3% does not exceed 9% of the total imports of the PUC into India. Therefore, it is held that the import of the PUC originating from developing countries (except China PR) will not attract Safeguard Duty in terms of proviso to Section 8B(1) of the Customs Tariff Act, 1975.

### 55. (G) Recommendations

55.1 In view of the aforementioned analysis, it is concluded that;

- i. The product under consideration viz. "Single Mode Optical Fibre" is being imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threaten to cause serious injury to the DI manufacturing like or directly competitive products.
- ii. The existing circumstances justify the imposition of a Safeguard Duty in order to protect the DI from further serious injury, which may be difficult to repair.

55.2 Accordingly, the following recommendations are made:

- i. Considering that BCD has been increased by 5% on 01.07.2019 and imports in Post POI have reduced, a weighted average Fair Selling Price (FSP) of the Domestic Industry has been computed on the basis of cost plus a return as considered appropriate after considering competing interests of all stake holders. This FSP has been compared with the landed value of imports of PUC during the most recent period which leads to an injury margin of \*\*\*%.
- ii. Considering all circumstances and the extent of serious injury, a Safeguard Duty of 10% is proposed to be imposed *ad valorem* on CIF price on the imports of the PUC viz. "Single Mode Optical Fibre" falling under Customs Tariff Item 9001 10 00 of the Customs Tariff Act, 1975 from all countries with the exception of the developing countries indicated in clause (iii) below. The Tariff Item mentioned herein is

indicative only and the description of the imported goods will determine the applicability of the Safeguard Duty.

- iii. As the imports from the developing countries listed in Notification No.19/2016-Custom (NT), dated 5th February, 2016, other than China PR, do not exceed 3% individually and 9% collectively, the imports of “Single Mode Optical Fibre” originating from such developing countries (other than China PR) will not attract the Safeguard Duty in terms of first proviso to Section 8B(1) of the Customs Tariff Act, 1975.
- iv. The Safeguard Duty on the import of the said product, as above, is proposed to be levied for a period of one year. Since, the safeguard duty is proposed to be for one year only, no progressive liberalisation is recommended.
- v. An appeal against the order of the Central Government arising out of these findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975.

BIDYUT BIHARI SWAIN, Special Secy. & Director General (Safeguard)